R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

पहले कोविड-19, फिर डेल्टा, अब
ओमिक्रॉन, डेल्टाक्रॉन का खतरा

भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए
तैयार नहीं है कोई भी देश

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

HEIDELBERGCEMENT SINCE 1873 QUALITY ASSURANCE MARK

mycem cement

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा **"सर्वोत्तम निर्माण के लिए"** उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

JNC 07, 20

इस अंक में

विकास

9 | मप्र में देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

देश के हृदय प्रदेश मप्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए उद्योग विभाग ने 10 हजार हैक्टेयर पर देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना...

राजपथ

10-11 | अब मिशन मोड पर होगा काम

आत्मनिर्भर मप्र के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह संकल्पित हैं। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने गत दिनों प्रदेश के सभी विभागों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब ना-नुकुर...

मनरेगा

14 | फिर याद आई मनरेगा की

पिछले साल नवंबर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 यानी मनरेगा में काम मांगने वालों की तादाद में उछाल आया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते उपजी बीमारी कोविड-19 के बाद स्थितियों में सुधार...

बिजली

18 | लगेगा 10 फीसदी का करंट

बिजली की दरों को बढ़ाने की याचिका पर बीते साल अफसर चुप्पी साधे हुए थे। सरकार का पहले ही दबाव था कि याचिका को लेकर किसी तरह का हल्ला न हो। शायद डर था कि बिजली बढ़ोतरी की हकीकत विपक्ष को राजनीति का मौका न दे दे। अब मप्र विद्युत नियामक आयोग ने याचिका...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

कोविड-19 महामारी ऐसा नासूर बन गई है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। पहली और दूसरी लहर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद अब तीसरी लहर का दौर शुरू हो गया है। तीसरी लहर में अभी ओमिक्रॉन वैरिएंट फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही डेल्टाक्रॉन वैरिएंट भी उपज रहा है। इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह दूसरी लहर से भी अधिक लोगों की जान ले सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महामारी से निपटने के लिए किसी देश के पास पूरी तैयारी नहीं है।

29

32-33

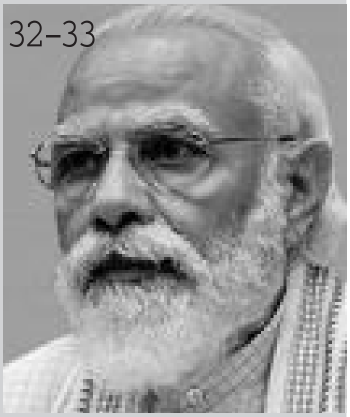

44

45

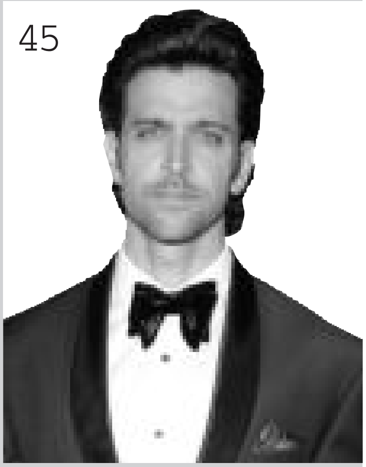

राजनीति

30-31 | अबकी बार जनता की अग्निपरीक्षा

पांच राज्यों के चुनाव घोषित होते ही मीडिया महोत्सव शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि ये चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल हैं और भाजपा-कांग्रेस समेत उन सभी राजनीतिक दलों (जो मैदान में हैं) की अग्निपरीक्षा इन चुनावों में होगी। लेकिन वास्तविकता...

महाराष्ट्र

36 | सब कुछ ठीक नहीं

राजनीति में नेता और नेता पर निर्भर पार्टी का भविष्य चुनाव से तो आंका ही जाता है, नेता के स्वास्थ्य से भी ये सीधा जुड़ा होता है। इसीलिए कई बार किसी नेता की तबियत ठीक ना हो तो उसपर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। यही वजह है कि पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश...

बिहार

38 | राज्यसभा की सीटों को लेकर रस्साकशी

2022 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है। यह 5 सीटें बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगी। खासतौर पर जदयू से एकमात्र केंद्र में मंत्री बने आरसीपी सिंह साल के जुलाई में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं। तो वहीं, लालू यादव...

6-7 अंदर की बात

41 महिला जगत

42 अध्यात्म

43 कहानी

44 खेल

45 फिल्म

46 व्यंग्य

अपनी बात

यहां हर मोड़–मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा...

फिल्म हादसा का यह गीत तो आपने सुना ही होगा...

'हे, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है
यहां जिन्दगी हादसों का सफर है...'

अब यह गीत देश के हृदय प्रदेश मप्र की राजधानी पर सटीक बैठता है। यहां की सरकारों ने तो इस शहर को पेरिस बनाने का दावा किया और योजनाएं-परियोजनाएं भी ला दी गईं, लेकिन आज भी यह शहर किसी बूचड़खाने की तरह नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अनियंत्रित विकास और विकास में भेदभाव। भोपाल में एक तरफ चार इमली, अरेरा कॉलोनी, 74 बंगले, 45 बंगले, श्यामला हिल्स, वल्लभ भवन जैसे वीआईपी मूवमेंट वाले क्षेत्र हैं, जहां लगातार विकास कार्य चलते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर है, जहां विकास के नाम पर खुदी सड़कें, सड़कों के किनारे बिखरा मलबा, स्मार्ट सिटी के गड्ढे, मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट के कारण अस्त-व्यस्त सड़कें नजर आती हैं। वीआईपी मूवमेंट वाले क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त रहती है। वहीं आमजन के क्षेत्र में हमेशा जाम की स्थिति निर्मित रहती है। ऐसा लगता है जैसे करीब 25 लाख की आबादी वाले इस शहर में सारी व्यवस्था कुछ हजार लोगों के लिए ही होती है। हालांकि 9 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद ऐसा लगा था कि खास के साथ ही आम को भी परिवहन, सुरक्षा और सुदृढ़ व्यवस्था मिलेगी। लेकिन सिस्टम लागू होने के एक माह से अधिक दिन होने के बाद भी स्थिति जस की तस है। शहर में महिला संबंधी अपराधों में इजाफा हुआ है। नाबालिग बच्चियों को अगवा किए जाने की वारदात 21 प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि ज्यादती के मामलों में 13 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अच्छी बात ये रही कि इस एक महीने में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर 3 बड़े प्रयोग हुए, जो इस सिस्टम से पहले नहीं किए जा रहे थे। हालांकि, शहर में चल रहे निर्माण कार्य से अब भी जगह-जगह ट्रैफिक जाम की परेशानी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। मजिस्ट्रियल अधिकार वाले अफसरों की कोर्ट भी शुरू कर दी गई हैं। भोपाल में साइबर अपराधों का ग्राफ बेहद तेजी से बढ़ रहा है। अहम बात ये है कि हर थाने में साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन के लिए एक-एक एसआई और दो-दो सिपाही दिए गए हैं। इसके बाद भी थाना स्तर पर खुलासे महज 2-3 ही हो पाए हैं। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भोपाल साइबर क्राइम यूनिट भी कोई खुलासा नहीं कर पाई है। शहर में ट्रैफिक जाम प्रोन एरिया में ड्रोन से नजर रखना शुरू कर दिया गया है, ताकि जाम की सटीक वजह पता चले और उसमें सुधार किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस को 416 नवआरक्षक मिले, जिन्हें अभी चौराहा-तिराहा प्रबंधन व सड़क पर लोगों से बातचीत के तरीके सिखाए जा रहे हैं। जिन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां शाम को ज्यादा बल तैनात किया जाता है, जो वाहनों की कतार लगने से रोकते हैं। लेकिन इससे शहर की समस्याएं दूर होने वाली नहीं हैं। शहर में विकास और परिवहन पूरी तरह अनियंत्रित है। शासन और प्रशासन कायदे-कानून को बनाता है और उसे लागू भी किया जाता है लेकिन उसका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इस कारण प्रदेश की राजधानी को पेरिस बनाने का सपना अभी भी कल्पना बना हुआ है। शहर में मेट्रो और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कारण विभिन्न क्षेत्रों में गांव से भी बदतर स्थिति बनी हुई है। इससे लगातार हादसे भी हो रहे हैं और ये हादसे फिल्म हादसा के गीत-
'यहां हर मोड़-मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा' को चरितार्थ कर रहा है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 8, पृष्ठ-48, 16 से 31 जनवरी, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता**:- इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़**:- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ** :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिंलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र-संपादक के नाम

akshnews.com

कमर कस ले कांग्रेस

2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा का पूरा जोर संगठन और मतदाताओं में अपना प्रभाव बढ़ाने पर है। प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, उसे देखकर कांग्रेस को भी अभी से कमर कस लेनी चाहिए।

● **प्रदीप शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

कोरोना से लड़ता रहा मप्र

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथी बार सत्ता में आने के बाद प्रदेश में धुंआधार विकास कार्य हुए हैं। मप्र कोरोना से डरने के बजाय लड़ता रहा और कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास के भी नए कीर्तिमान गढ़ता रहा। सरकार ने अच्छी तरह सब हैंडल किया।

● **रेखा भारद्वाज,** इंदौर (म.प्र.)

नक्सलियों पर नकेल जरूरी

मप्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इन दिनों बालाघाट जिले में एक सैकड़ा से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी बनी हुई है, जो महाराष्ट्र के रास्ते से मप्र में प्रवेश कर रहे हैं। प्रदेश की पुलिस को नक्सलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

● **सुमित यादव,** बालाघाट (म.प्र.)

पंचायत चुनाव न होने से कईयों का नुकसान हुआ

पंचायत चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर शह-मात का ऐसा खेल खेला गया जो पहले कभी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भी देखने को नहीं मिला। इसी के साथ ही गांव-गांव में जहां सन्नाटा पसर गया, आवभगत का अभूतपूर्व दौर निकल गया। वहीं अब राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक पंचायती चुनाव को लेकर पंचायतें होती रहेंगी, क्योंकि दोनों ही दल एक-दूसरे को इस परिस्थिति के लिए दोषी ठहराते रहेंगे।मप्र में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद अब नामांकन पत्र दाखिल करके चुनाव प्रचार शुरू करने वाले लोगों का गुस्सा भी सामने आने लगा है। कई प्रत्याशियों का नुकसान हुआ है।

● **रिया नानकानी,** ग्वालियर (म.प्र.)

मजबूत होगी भारतीय अर्थव्यवस्था

बेशक पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक बदहाली का कारण कोविड-19 महामारी और उससे निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन था, लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के 5.7 फीसदी वृद्धि के मुकाबले 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उस कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सहारा है, जिस पर 43 प्रतिशत श्रमबल की निर्भरता है। ऐसी ही स्थिति रहती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

● **मोहन वर्मा,** नई दिल्ली

जैविक खेती लाभ का धंधा

मप्र में जैविक खेती के प्रति किसानों का लगाव तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में कई किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती तो करते ही हैं, वहीं जैविक उत्पाद भी बनाते हैं जिनकी मांग विदेश में भी है। खासकर आदिवासी बहुल जिलों में जैविक खेती का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश से अधिक से अधिक जैविक उत्पाद निर्यात हो, इसके लिए निर्यातकों को सुविधा दिलाने का काम किया जा रहा है।

● **आदित्य नागर,** राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

खुद संकट में संकटमोचक पीके

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कैरियर ग्राफ में इन दिनों ठहराव सा आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत लगभग हर राजनीतिक दल के रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर उर्फ पीके खुद के भविष्य की स्पष्ट रणनीति बनाने में हाल-फिलहाल तक विफल होते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान ही उन्होंने घोषित कर दिया था कि वे अब चुनाव प्रबंधन की रणनीति बनाने का काम नहीं करेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि पीके राजनीति में सीधे इंट्री बजरिए कांग्रेस करने जा रहे हैं। पीके ने कांग्रेस आलाकमान संग कई बार बैठकें भी की लेकिन मामला जमा नहीं। अब बेचारे करें तो क्या करें। चुनाव प्रबंधन की रणनीति बनाने के बिजनेस से उन्होंने खुद को दूर करने का ऐलान स्वयं किया है, इसलिए सीधे वापसी करने से वे हिचकिचा रहे हैं। हालांकि उनकी कंपनी 'आई-पैक' कई राज्यों में यह धंधा अलग-अलग पार्टियों के लिए अब भी कर रही है, पीके लेकिन सामने न आकर, पर्दे के पीछे से कमान संभाले हुए हैं। विशेषकर तृणमूल कांग्रेस के बंगाल से बाहर विस्तार में वे बड़ी भूमिका निभाते बताए जा रहे हैं।

कर्नाटक भाजपा में खुली रार

कर्नाटक में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बने अभी कुल चार महीने ही हुए हैं। लिंगायत समाज के बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा को यकायक पैदल कर भाजपा आलाकमान ने बोम्मई को राज्य की कमान गत् 20 अगस्त के दिन सौंप सबको हैरत में डालने का काम किया था। येदियुरप्पा की बरस्क बोम्मई का न तो राज्य में खास जनाधार है, न ही पार्टी के विधायकों में उनकी येदियुरप्पा समान पकड़ रही है। इसके चलते भले ही पार्टी आलाकमान के आदेश पर विधायकों ने उन्हें अपना नेता तो मान लिया लेकिन विधान दल और संगठन में इस निर्णय के चलते भारी असंतोष पसर गया है। अब यही असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। स्वयं बोम्मई ने अपने पद पर बने रहने पर शंका जाहिर कर दी है। गत दिनों येदियुरप्पा की तर्ज पर बोम्मई भी आंखों में पानी और भरे गले से यह कहते सुने गए कि 'राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है।' दरअसल कर्नाटक भाजपा के कुछ दिग्गज बसवराज बोम्मई के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। हालात इतने विकट हो चले हैं कि राज्य के एक मंत्री मुलगेश निरानी ने तो घोषणा ही कर डाली कि 2013 के चुनाव पहले राज्य में नया मुख्यमंत्री पदासीन हो जाएगा। इतना ही मानो कम नहीं, एक अन्य कैबिनेट मंत्री ईएस ईश्वरकृपा ने तो यह भी कह डाला है कि निरानी जल्द ही राज्य के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।

दलबदल का मौसम शबाब पर

5 राज्यों में चुनावी घोषणा के साथ ही दलबदल का मौसम शबाब पर है। खासकर देश की सत्ता का फैसला करने वाले उत्तरप्रदेश में दलबदल जोरों पर है। विधायकों का एक-दूसरे राजनीतिक दलों में आने-जाने का दौर जारी है। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे है। सबसे मजे की बात ये है कि जिस अंदाज में भाजपा के विधायक और मंत्री सत्ता को छोड़कर दूसरे राजनीति दलों में जा रहे है, वहां पर अब संभावनाएं, ये जताई जा रही है कि कहीं ये सियासी खेल तो नहीं है। और तो और भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने से अब समाजवादी पार्टी में इस बात का मंथन चल रहा है कि अगर भाजपा और अन्य राजनीति दलों से विधायक या बड़े नेता शामिल होते और समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा तो टिकट देना पार्टी के लिए मुसीबत हो सकता है। क्योंकि समाजवादी के जो नेता भाजपा के विरोध में और सत्ता के विरोध में गत पांच सालों से संघर्ष करते आ रहे है। उनका टिकट काटना या उपेक्षा करना मुश्किल साबित होगा। क्योंकि वो पार्टी के साथ बगावत भी कर सकते है। अब देखना यह है कि दलबदल का यह दौर किस पर भारी पड़ता है और किसको फायदा देता है।

भाजपा-जदयू में बढ़ रहा है तनाव

बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों खासे परेशान चल रहे हैं। उन्होंने गांधीजी की प्रेरणा से राज्य में संपूर्ण शराबबंदी कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया था। उनका दांव लेकिन अब पलटवार कर रहा है। राज्य में नशाबंदी तो हो नहीं पाई, पुलिस की भ्रष्ट कमाई जरूर रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। राज्य के नशाबंदी कानून का असर गरीब तबके पर जमकर पड़ा है। लाखों की तादाद में इस तबके के लोग शराब पीने के चलते राज्य की जेलों में बंद है। न्यायालयों में लगभग साढ़े तीन लाख मामले इस कानून के चलते लंबित पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त कर डाली है। राजनीतिक स्तर पर भी हालात नीतीश बाबू के खिलाफ जाते स्पष्ट नजर आने लगे हैं। सरकार में अब उनका दबदबा पहले समान नहीं रहा है। भाजपा हर मामले में नीतीश कुमार के कदम रोकने का प्रयास कर रही है। विधानसभा में जद(यू) के सदस्यों की संख्या भाजपा और राजद के मुकाबले बेहद कम रह गई है। इसलिए न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को भाजपा के इशारों पर नाचना पड़ रहा है।

कोश्यारी खफा, त्रस्त ठाकरे सरकार

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लिए उनके गृह राज्य उत्तराखंड में कहा जाता है कि उनसे प्यार से तो कोई भी काम करा सकता है, तेवर यदि दिखाए तो कोश्यारी के तेवर भी कड़े हो जाते हैं और फिर उस व्यक्ति का काम वे कतई नहीं करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोश्यारी को सीधा-साधा पहाड़ी समझने की भूलकर बैठे। उनकी इस भूल का नतीजा यह रहा कि गवर्नर साहब सरकार की हर फाइल की गहन पड़ताल करने बाद ही उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। इस गहन पड़ताल के चलते सरकार के कई निर्णय महीनों से अधर में लटके पड़े हैं। पिछले एक साल से राज्य विधान परिषद् के लिए 12 नामों की संस्तुति राज्यपाल की सहमति न होने के चलते खटाई में पड़ी हुई है। सूत्रों की मानें तो सरकारी भाषा मराठी होने के चलते राज्यपाल पहले हरेक पत्रावली का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराते हैं फिर दिल्ली से मुंबई राजभवन आयातित किए गए केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी संग गहन विचार-विमर्श कर अपना निर्णय लेते हैं।

2013 के गॉडफादर

यह लोकोक्ति तो आपने सुनी ही होगी कि 'काम के न काज के दुश्मन अनाज के।' कुछ इसी तरह की श्रेणी में प्रदेश के कुछ ब्यूरोक्रेट्स शुमार हैं। इनमें से एक आईएएस अधिकारी 2013 बैच के हैं, जिन्हें हाल ही में एक बड़े जिले में पदस्थ किया गया है। इनकी पदस्थापना पर हर कोई आश्चर्यचकित है, क्योंकि माना जाता है कि ये उस लायक नहीं हैं। दरअसल, इनकी कार्यप्रणाली हमेशा विवादों में रही है। लेकिन मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान की तर्ज पर इनकी भी चल पड़ी है। दरअसल, प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा है कि प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया 2013 बैच के आईएएस अफसरों के लिए गॉडफादर बन गए हैं। बात-बात में सवाल उठाने वाले साहब 2013 बैच वालों पर इतने मेहरबान क्यों हैं, इसको लेकर कयासों का दौर भी चल रहा है। लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि छोटी-छोटी बात पर समझौता न करने वाले साहब ने 2013 बैच के उक्त आईएएस को इतने बड़े जिले का कलेक्टर कैसे बना दिया। कुछ तो यह कह रहे हैं कि राजनीति ही नहीं प्रशासन में भी संतुलन का अपना महत्व रहता है। एक कुशल ब्यूरोक्रेट अपने समकक्षों के साथ ही कनिष्ठों से भी संतुलन साधे रहता है। अगर अपनों को लाभान्वित करना है तो संतुलन बेहद जरूरी हो जाता है। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों ऐसे ही संतुलन की चर्चा खूब हो रही है।

मंत्रालय रास नहीं आ रहा

प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी का क्रेज ही कुछ ऐसा है कि जिस अधिकारी की पदस्थापना वहां होती है वह वहीं का होकर रह जाता है। इंदौर की तासीर में ऐसी क्या चीज है, यह तो आमजन को पता नहीं, लेकिन अफसरों को यह तासीर इस तरह लगती है कि वे तबादले के बाद भी इंदौर छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसी ही एक अफसर इन दिनों राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर तक चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल, मैडम व्यावसायिक राजधानी में एक निगम में पांच साल से प्रबंध संचालक के पद पर आसीन थीं। लेकिन अब उनका स्थानांतरण मंत्रालय में कर दिया गया है। लेकिन मैडम को मंत्रालय रास नहीं आ रहा है और वे आज भी उसी निगम की गाड़ी-बंगले और सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं। बताया जाता है कि मैडम का इंदौर से ट्रांसफर हुए तीन महीने हो गए पर मंत्रालय में आमद दे कर वे वापस इंदौर आ गई हैं और उसी निगम के कर्मचारी उनकी सेवा चाकरी कर रहे है। नए प्रबंध संचालक के पास अतिरिक्त चार्ज है तथा उनसे जूनियर है। अत: संकोच में कुछ कह नहीं पा रहे। सूत्रों का दावा है कि मैडम किसी अन्य निगम में पदस्थापना के लिए कोशिश कर रही हैं। क्योंकि मंत्रालय की आबोहवा उन्हें पसंद नहीं आई है।

रिश्तेदारी का द्वंद

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में यह माना जाता है कि इंदौर में पदस्थापना किसी भी अफसर के लिए बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद भी अफसर चाहते हैं कि उनकी पदस्थापना कम से कम एक बार तो इंदौर में जरूर हो। इसके लिए वे अपने करीबी माननीयों के माध्यम से कोशिश करते हैं। इसी को लेकर अक्सर सत्तापक्ष के नेताओं में द्वंद होता रहता है। इन दिनों एक ऐसा ही द्वंद सामने आया है, जिसके तहत सरकार के नंबर-1 और नंबर-2 के बीच द्वंद की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार व्यावसायिक राजधानी में एडिशनल एसपी को लेकर यह द्वंद चल रहा है। बताया जाता है कि वर्तमान में जो अधिकारी वहां एडिशनल एसपी के पद पर आसीन है, वे अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी उनके काम से संतुष्ट हैं। हालांकि उनका समय भी पूरा हो चुका है। ये अधिकारी सरकार में नंबर-2 की पोजिशन रखने वाले माननीय के करीबी भी हैं। लेकिन खबर यह चल रही है कि सरकार में नंबर-1 की पोजिशन वाले माननीय इनकी जगह अपने एक रिश्तेदार को पदस्थ करना चाहते हैं। उक्त अधिकारी महाकाल की नगरी से ट्रांसफर होकर आए हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें इस बार व्यावसायिक राजधानी इंदौर में एडिशनल एसपी का चार्ज मिल जाए। अब देखना यह है कि उज्जैन से आए साहब की मंशा पूरी हो पाएगी या नहीं।

नजदीकियां चर्चा में

प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में इन दिनों एक मंत्री और एक महिला विधायक की नजदीकियां काफी चर्चा में हैं। आलम यह है कि न केवल राजनीतिक वीथिका में बल्कि प्रशासनिक वीथिका में भी इन दोनों के किस्से चटखारे लेकर सुनाए जा रहे हैं। दोनों जवान हैं, ये जहां भी उपस्थित रहते हैं वहां का वातावरण खुशहाल और सौंदर्यपूर्ण हो जाता है। मैडम अपनी साज-सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं। सूत्र बताते हैं कि वे साल में एक बार ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए देश की राजधानी में इलाज के लिए भी जाती हैं। यह ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है कि इसका एक बार का बिल तकरीबन 2 से 4 लाख रुपए तक का आता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार मैडम जब ट्रीटमेंट कराने दिल्ली गईं तो उनके बिल का भुगतान मंत्रीजी ने ही किया। भले ही मंत्रीजी ने बिल का भुगतान चोरी-छिपे किया, लेकिन मंत्रीजी यह कहावत भूल गए कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। फिर क्या था, यह बात दिल्ली से भोपाल पहुंची और यहां राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में नमक-मिर्च मिलाकर परोसी जा रही है तथा लोग मन लगाकर सुन रहे हैं।

घर वापसी की कवायद

प्रदेश के एक बड़े शराब व्यावसायी इन दिनों हैरान-परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना कारोबार इतना फैला लिया है कि उस पर हर किसी की नजर पड़ने लगी है। उक्त व्यावसायी पहले भगवा दल में थे, लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने पार्टी भी बदल ली थी। लेकिन वे जिस पार्टी में गए उसकी सरकार अधिक दिन नहीं टिक पाई। अब आए दिन अधिकारी उन्हें परेशान करते रहते हैं। आलम यह है कि कभी भी उनकी संपत्तियों की नापजोख शुरू हो जाती है। इससे वे परेशान हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी में लौटने का मन बना लिया है, ताकि रोज-रोज की परेशानियों से निजात मिल सके। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने सरकार के एक दमदार मंत्री की परिक्रमा करनी शुरू कर दी है। अक्सर उन्हें मंत्रीजी के आसपास मंडराते हुए देखा जा रहा है। यही नहीं ये पार्टी में मोटा चंदा भी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि उक्त शराब व्यावसायी की कब तक घर वापसी होती है या फिर उन्होंने पूर्व में जो गलती की है, उसे भुगतना पड़ेगा।

अक्स का आईना

जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो बहुत से लोग हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं। किसी के साथ फोटो होना, सेल्फी होना, गाड़ी में बैठना अपराध नहीं है। जिन्होंने गलत किया है, तो वे भुगतेंगे। कानून अपना काम करेगा।

● **विजय शाह**

खालिस्तानी न तो सिख हैं, न ही किसान। वे लोग आतंकवादी हैं, लश्कर-ए-तैयबा की तरह। भारत सरकार को इन्हें आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। अगर आप इनकी तरफ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये चाहते हैं... आतंकवाद और गृहयुद्ध। इसलिए इनका विरोध होना चाहिए और सरकार को देशद्रोही ताकतों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए।

● **कंगना रनौत**

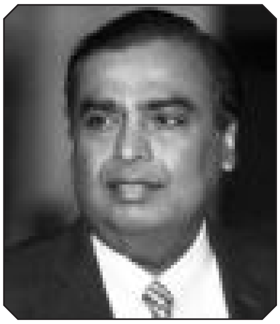

अब वर्तमान पीढ़ी का समय आ गया है। आकाश, ईशा और अनंत की सोच मुझसे विकसित है। नई पीढ़ी नई रणनीति और क्रांतिकारी नजरिए के साथ काम कर रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि इनको जिम्मेदारियां दी जाएं। ताकि ये अपने नजरिए से उद्योग जगत को नई बुलंदियों पर ले जा सकें। इसके लिए प्रारंभिक तैयारी चल रही है।

● **मुकेश अंबानी**

भारतीय टीम में लड़ाई-झगड़े की हवा उड़ाई जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूरी टीम एकजुट होकर खेल रही है। क्रिकेट हो या कोई अन्य खेल इंजुरी आम बात है। अगर कोई खिलाड़ी इंजुरी के कारण मैच नहीं खेलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि टीम में मतभेद है।

● **राहुल द्रविड**

एक किरदार या एक फिल्म आदमी को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए काफी है। इस बात का अब मुझे एहसास हो गया है। बजरंगी भाईजान में मैंने मुन्नी का किरदार निभाया, जिसे सभी ने पसंद किया। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुझे भारतरत्न डॉ. अम्बेडकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। मुझे फिल्मों के लगातार ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस अच्छी कहानी पर है। भविष्य में मुझे अच्छा रोल मिलेगा तो जल्द ही अपने प्रशंसकों के सामने दिखूंगी। फिलहाल मैं कुछ नई योजना पर काम कर रही हूं।

● **हर्षाली मल्होत्रा**

वाक्‌युद्ध

चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि हम जनता तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। चुनाव आयोग को एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए जहां सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर सकें। ऐसा लगता है जैसे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है।

● **अखिलेश यादव**

चुनाव प्रचार से जरूरी जनस्वास्थ्य है, इसलिए चुनाव आयोग ने रैलियों पर जो प्रतिबंध लगाया है, उसका स्वागत होना चाहिए। आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देश की 90 फीसदी आबादी सक्रिय है। पार्टियां वहां अपनी बात रखे। हर चीज को राजनीति के नजरिए से देखना सपा और कांग्रेस की आदत बन गई है। इसका कोई समाधान नहीं है।

● **योगी आदित्यनाथ**

आत्मनिर्भर मप्र के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार मिशन मोड में आ गई है। इसके लिए सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में विकास कार्य इस तरह हों कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार की इसी मंशा के अनुरूप गत दिनों उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने समीक्षा के दौरान मप्र में देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा है।

मप्र में देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

देश के हृदय प्रदेश मप्र में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देखते हुए उद्योग विभाग ने 10 हजार हैक्टेयर पर देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना तैयार की है। यह एयरपोर्ट भोपाल-इंदौर रोड पर सोनकच्छ और आष्टा के बीच बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा इसकी टाइमलाइन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने समय और कितने फेज में पीपीपी मॉडल पर किस तरह इसका निर्माण किया जाएगा। सभी कार्यों की समयसीमा तय की जाएगी।

जानकारी के अनुसार गत दिवस जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा की थी तब समीक्षा के दौरान विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने प्रजेंटेशन दिया, जिसमें आने वाले वर्षों में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रजेंटेशन में बताया गया कि तेजी से औद्योगिक विकास के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अन्य सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। इसमें बताया गया कि अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, दुबई आदि देशों के प्रमुख एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं व सुविधाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया। इसी के तहत मप्र में भविष्य में यातायात की मांग को पूरा करने के लिए हब एंड स्पोक एयरपोर्ट मॉडल के रूप में विकसित होने की काफी संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री को टाइम लिमिट की रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस इस पर विभिन्न विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रिपोर्ट तैयार करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कार्य करने वाले बड़े उद्योगपतियों से भी चर्चा कर लें। इंदौर व भोपाल से एक घंटे में आने-जाने वाले लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इसके लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। प्रजेंटेशन में यह भी बताया गया है कि यात्रा समय को कम करने के लिए प्रस्तावित एयरपोर्ट के माध्यम से इंदौर और भोपाल के बीच मेट्रो रेल परियोजना व एक्सप्रेस-वे का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित एयरपोर्ट के आसपास विभिन्न स्थानों पर मेगा औद्योगिक टाउनशिप भी विकसित किया जाएगा। साथ ही इसे भारत सरकार के इंडस्ट्रीयल पार्क स्कीम से भी जोड़ा जाएगा, ताकि केंद्र सरकार से मदद मिल सके। इससे नर्मदा एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत भोपाल और इंदौर के बीच आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। प्रजेंटेशन में यह भी बताया गया है कि वर्तमान एयरपोर्ट इतने व्यस्त हैं कि प्रशिक्षण व रखरखाव का कार्य वहां नहीं हो पाता। विमानों के सुधार और ट्रायल के लिए मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवर हालिंग (एमआरओ) के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। प्रस्तावित एयरपोर्ट में पार्किंग व्यवस्था भी होना चाहिए। यह व्यवस्था अभी मप्र के किसी एयरपोर्ट पर नहीं है।

वहीं मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास के कार्यों को गति प्रदान करने का निर्देश दिया है। आत्मनिर्भर मप्र में भारत सरकार से प्राप्त मेडिकल उपकरण पार्क की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फार्मा विभाग भारत सरकार से मिली मंजूरी के बाद यह पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में विकसित किया जाएगा। इसी तरह होशंगाबाद जिले में मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भविष्य की यातायात जरूरतों के लिए हब एंड स्पोक एयरपोर्ट मॉडल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं का दोहन करने के निर्देश दिए।

2 लाख को मिलेगा रोजगार

उद्योग विभाग का कहना है कि मप्र में बनने वाले देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। दरअसल, इस एयरपोर्ट के आसपास मेगा औद्योगिक टाउनशिप भी विकसित की जाएगी। उधर, समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष नए निवेश प्रयासों से सात औद्योगिक पार्कों से 50 हजार से अधिक रोजगार मिलना अनुमानित है। साथ ही रतलाम, देवास, पीथमपुर के नए निवेश क्षेत्रों के साथ ही इंदौर-पीथमपुर इकनोमिक कॉरीडोर के क्रियान्वयन के फलस्वरूप 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्ति का अनुमान है। सात औद्योगिक पार्कों में प्रस्तावित निवेश 32 हजार 900 करोड़ रुपए रहेगा। रतलाम, देवास, पीथमपुर की संयुक्त लागत लगभग पौने चार हजार करोड़ रुपए होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री गति-शक्ति जैसे मॉडल कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न अधोसंरचना विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। बैठक में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजधर्वन सिंह दत्तीगांव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य अधिकारियों ने अपने-अपने विचार रखे।

● नवीन रघुवंशी

आत्मनिर्भर मप्र के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह संकल्पित हैं। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने गत दिनों प्रदेश के सभी विभागों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अब ना-नुकुर और बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। प्रदेश में अब मिशन मोड पर काम होंगे। हर काम की समयसीमा होगी और उसे उस सीमा में पूरा करना है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग का टारगेट पूरा करने में जुट गए हैं।

अब मिशन मोड पर होगा काम

मप्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों की समीक्षा के दौरान अफसरों को साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि आत्मनिर्भर मप्र की राह में कोई रोड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही केवल टारगेट पूरा करने से काम नहीं चलने वाला। सभी विभाग अपने-अपने लक्ष्य को नियत समय में पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं लगातार विभागों के लक्ष्य की मॉनीटरिंग करूंगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए साल की शुरुआत नए संकल्प के साथ की है। इस साल रोजगार के अवसरों में वृद्धि, विभागों में प्रशासनिक कसावट के साथ योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर सर्वाधिक जोर रहेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को न सिर्फ मैदान में उतारा जाएगा बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं भी दौरे करने के साथ समीक्षा करेंगे। इसी क्रम में विभागों की समीक्षा की गई । आत्मनिर्भर मप्र की कार्ययोजना के आधार पर विभागों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसी आधार पर बजट भी तैयार होगा। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों के सम्मेलन करने के साथ सर्वाधिक जोर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने पर रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र प्रवर्तित सभी योजनाओं में प्रदेश को नंबर-1 बनाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करें। वर्तमान में प्रदेश पीएम स्व-निधि योजना में प्रथम, आवास योजना में द्वितीय, स्मार्ट सिटी में द्वितीय, स्वच्छ भारत मिशन में तृतीय और अमृत योजना में चतुर्थ स्थान पर है। प्रदेश को अन्य क्षेत्रों में भी नंबर-1 बनाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाटी विकास विभाग में अफसरों के निरीक्षण न करने पर नाराज होकर कहा कि आप लोगों की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। जैसी समीक्षाएं फील्ड में होना चाहिए वैसी नहीं हो रही हैं। इसलिए मैदान में जाएं। डायरी मेंटेन करें। इसी तरह जल संसाधन विभाग के अफसरों को सिंचाई योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर डपट लगाई। शिवराज ने कहा कि सिंचाई जैसे कामों में गड़बड़ होती है, ऐसा न होने दिया जाए। विभागीय समीक्षा के दौरान अफसरों ने उपलब्धियों को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। शिवराज ने विभागों के तय लक्ष्यों को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए।

शिवराज ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा में मैदानी दौरे न होने पर नाराजगी जताकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैदानी स्तर पर जितनी समीक्षा होना चाहिए, वह नहीं हो रही है। लीपा-पोती नहीं चलेगी। विभाग के फील्ड अफसर नियमित दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। शिवराज ने कहा कि जो लक्ष्य बताए गए हैं, उनका रोडमैप बनाकर काम शुरू करें। कोई भी यदि काम में ढिलाई बरत रहा है, तो उसे कस दें। प्रति एकड़ सिंचाई के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका प्रचार करें। सभी सिंचाई योजनाएं, जो कंप्लीट हो रही हैं, उनका प्रचार करें। बड़ी योजनाओं का ऑपरेशन और मेंटेनेंस की पूरी व्यवस्था हो। प्रोजेक्ट्स में देरी न हो। अगर देरी हुई तो उसकी जिम्मेदारी तय करें। सारे काम जनभागीदारी से होना चाहिए।

शिवराज ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा में कहा कि सिंचाई जैसे कामों में गड़बड़ होती है। यह गड़बड़ न हो। सिंचाई के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों से संबंधित एक बुकलेट बने। इसके

रोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अटल पथ और नर्मदा एक्सप्रेस वे के निर्माण पर फोकस करने और नए क्षेत्र निवेश के लिए प्रयास करने के भी निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर में रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए अच्छा वातावरण बन सकता है। रक्षा सेक्टर की इकाई के लिए अपनी तैयारी कीजिए। वर्कआउट कीजिए, केंद्र से हम बात करेंगे। फार्मा सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं, इस दिशा में रणनीति बनाइए। हमें एक टेक्सटाइल्स पार्क की योजना बनानी है जो प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी तरह की कसर न छोड़ें। एक जिला, एक उत्पाद के लिए वैल्यू चैन कैसे बने, इस पर काम कीजिए ये कागज में न रहे। सभी प्रोजेक्ट के टारगेट तय कीजिए और समय पर कार्य पूरे कीजिए। निर्यात संबंधी समितियों की मदद कीजिए। हमें मार्केट तैयार करना है। एम्बेसडर और राजदूतों से संपर्क कीजिए। प्रदेश में एनआरआई से संबध स्थापित कीजिए।

जरिए हमारे अच्छे कामों का प्रचार हो। खान नदी में प्रदूषण पर कहा कि यह प्रदूषण होना हमारी असफलता है। इसमें प्रदूषण रोकने का कार्य ढंग से करें। इसका पुख्ता समाधान निकालें। अटल भू-जल योजना के क्रियान्वयन में हम देश में अव्वल कैसे आएं इस पर काम करें। राज्य की जल उपभोक्ता समितियों के सदस्यों का एक सम्मेलन हो। हर योजना समय पर पूरी हो और अगर बिना वाजिब कारण के देरी हो रही है तो जिम्मेदारी तय करें। प्रेशराइज्ड पाइपलाइन की योजना पर काम करें।

शिवराज ने मुछआ कल्याण विभाग की समीक्षा में कहा कि हमारी मीठे पानी की मछलियों की ब्रांडिंग होना चाहिए। जो गरीब मछुआरे हैं, उनकी आजीविका किसी भी कीमत पर सुनिश्चित करें। अनेक स्थानों पर दबंग आते हैं और तालाबों पर कब्जा करते हैं। यह न हो। हमारा काम मत्स्य उत्पादन बढ़ाना है। इस पर ध्यान दिया जाए। मछली पालन में मनरेगा के तहत लाभ दिया जाएगा। मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आइडियल क्रियान्वयन की योजना बनाएं। सभी तालाबों की चेन बनाएं और मनरेगा के तहत काम दें। सभी मछुआरों को मछुआ क्रेडिट कार्ड बांटें। किसानों की तरह मछुआरा एफपीओ बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन्स को प्रमोट करें।

शिवराज ने चिकित्सा शिक्षा और गैस त्रासदी राहत विभाग की समीक्षा में कहा कि चिकित्सक नैतिकता के उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित भी किया जाए। अच्छे कार्य करने वालों की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। मैं जब पढ़ता था, तब अस्वस्थ होने पर हमीदिया अस्पताल में गया, जहां मुझे डॉक्टर एचएस त्रिवेदी ने देखा। अस्पताल की दूरी अधिक होने के कारण मैं अगली बार उनके निवास पर ही उपचार के लिए गया। वहां कोई फीस नहीं ली और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आपको हमीदिया अस्पताल में देखा था, मैं फीस नहीं ले सकता। ऐसे डॉक्टरों की कमी नहीं है। शिवराज ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट बढ़ाई जाए।

चिकित्सालय की क्षमता में वृद्धि की जाए। चिकित्सा महाविद्यालयों में न्यूनतम जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहें। फीस कमेटी की अवधारणा तैयार कर मापदंड तय करें। नर्सिंग छात्राओं को अधिकाधिक रोजगार से जोड़ा जाए। रतलाम में मेडिकल कॉलेज में अलग से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के प्रयास हों। चिकित्सा महाविद्यालयों में नशामुक्ति केंद्र बने। महिलाओं में कैंसर की प्राथमिक रोकथाम के लिए पिंक कैम्पेन को प्रारंभ करें। हिंदी में चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर देश में प्रथम बनाने में सहभागी बनें। फायर सेफ्टी जैसे ऑडिट करवाएं, ताकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल-इंदौर में मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य 15 अगस्त 2023 तक का रखा जाए। साथ ही इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर के लिए भी मेट्रो ट्रेन के सर्वे की कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में शिवराज ने अस्पतालों को सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सरकारी अस्पताल ऐसे होने चाहिए कि निजी अस्पताल में जाने की कोई सोचे ही नहीं। इसके लिए मिशन मोड में काम करो।

शिवराज ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा में कहा कि शहर की सड़कें प्रदेश की छवि का आईना होती है। इसलिए शहर की सड़कें खराब नहीं दिखनी चाहिए। शिवराज ने दीनदयाल रसोई योजना पर फीडबैक लेने और मोबाइल रसोई योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिह ने कहा कि दीनदयाल रसोई का संचालन पूरी तरह नगरीय निकायों को दिया जाए। शिवराज ने रात्रिकालीन आश्रयों के आंकलन व ब्रांडिंग के लिए कहा। साथ ही प्रदेश को स्वच्छता में देश में नंबर वन पर लाने के लिए कहा। इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन-2 की डीपीआर को केंद्र से जल्द मंजूर कराने के लिए मुख्यमंत्री से विशेष प्रयास करने की मांग की। शिवराज ने वायु गुणवत्ता में सुधार करने व इंक्यूवेशन सेंटर को उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों की आय बढ़ाने के लिए साधन ढूंढें। इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने लैंडयूज चेंज करने की प्रक्रिया को सरल करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शहर में मैरिज गार्डन का निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। पेयजल के लिए अलग से प्लानिंग करें। सभी केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश को नंबर-1 बनाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करें। नगरीय निकायों का कैडर बनाएं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को हिदायत दी है कि मैं खुद समय-समय पर विभागों के टारगेट की समीक्षा करूंगा।

● कुमार राजेन्द्र

अजजा कल्याण विभाग को 6 महीने में हालत सुधारने के निर्देश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अजजा कल्याण विभाग की समीक्षा में कहा कि इस वर्ग की सभी योजनाओं का संवेदनशीला के साथ क्रियान्वयन हो। इसके लिए व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करने की जरूरत हो तो उसे भी तत्काल अमल में लाएं। शिवराज ने कहा कि इन वर्गों के छात्रावासों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है। इस पर तत्काल कदम उठाएं। छात्रावासों को ठीक किया जाए और मरम्मत के लिए राशि दी जाएं। पीएस और आयुक्त भी दौरे करें। सिस्टम को पारदर्शी रखें। 6 महीने में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। विभाग में प्रतिनियुक्ति पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। मंत्री मीना सिंह ने भी प्रतिनियुक्तियां बंद करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली पदों पर भर्ती हो और अनुसूचित वर्गों के लोगों को जरूरी तौर पर काम दिया जाए। उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं से अनुसूचित-जाति और जनजाति के लोगों को जोड़ा जाए।

डीजीपी सहित कई आईपीएस होंगे रिटायर

इस साल मप्र में पुलिस विभाग के मुखिया सहित कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे। वहीं प्रशासनिक मुखिया का भी कार्यकाल इस साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में इस साल पुलिस और प्रशासन में कई बदलाव नजर आएंगे। मप्र पुलिस में इस साल कई आला अधिकारी रिटायर होने वाले हैं। खाली होने वाले पदों को भरने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं अधिकारी भी लॉबिंग में जुट गए हैं। प्रदेश में दो महीने बाद नए डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। वहीं जून में लोकायुक्त में भी नए डीजी की नियुक्ति शासन को करनी होगी। दोनों ही अफसर इस साल अपने पदों से मुक्त हो रहे हैं। इन दोनों अफसरों के अलावा 9 और आईपीएस अफसर रिटायर होने जा रहे हैं।

विवेक जौहरी 5 मार्च 2020 को डीजीपी बने थे। हालांकि वे उसी वर्ष 60 साल की उम्र पार कर गए थे, लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने उन्हें दो साल के लिए इस पद पर बने रहने का आदेश जारी कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस आदेश को मानते हुए विवेक जौहरी को इस पद पर बरकरार रखा। विवेक जौहरी के इस पद पर दो साल 5 मार्च 2022 को पूरे हो रहे हैं। 6 मार्च को प्रदेश को नए डीजीपी मिल सकते हैं। डीजीपी बनने के लिए इस वक्त दो अफसरों के नाम तेजी से चल रहे हैं। उनमें पहला नाम सुधीर सक्सेना का है, जो इस वक्त प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि दूसरा नाम पवन जैन का है। वे होमगार्ड के डीजी हैं। वहीं मई में 1988 बैच के लोकायुक्त डीजी राजीव टंडन रिटायर हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली इस संस्था में एक जून को नए डीजी की नियुक्ति कर दी जाएगी। इस पद के लिए भी उस वक्त कई दावेदार होंगे।

इन दो अफसरों के अलावा 1987 बैच की आईपीएस अफसर स्पेशल डीजी पुलिस फायर अरुणा मोहन राव मार्च में रिटायर हो रही हैं। वहीं 1987 बैच के ही स्पेशल डीजी कॉआपरेटिव फ्रॉड राजेंद्र कुमार मिश्रा अक्टूबर और 1989 बैच के स्पेशल डीजी एसएएफ मिलिंद कानस्कर अगस्त में रिटायर होने जा रहे हैं। वहीं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 1988 बैच के यूसी षडंगी जुलाई और 1989 बैच के पीएस फलणीकर अक्टूबर में रिटायर होंगे। जबकि 1990 बैच के एडीजी रैंक के जीआर मीणा और 1991 बैच के वी मधु कुमार दिसंबर में रिटायर होंगे। इस महीने के अंत में 2002 बैच के आईजी नारकोटिक्स इंदौर जीजी पांडे रिटायर हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे आईजी पंकज कुमार सिंघी भी इस साल रिटायर होंगे।

नए डीजीपी की फाइल डेढ़ माह से सीएमओ में

प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी इस साल मार्च में रिटायर होंगे। प्रदेश के अगले डीजीपी के लिए इस वक्त दो अफसरों के नाम तेजी से चल रहे हैं। उनमें पहला नाम सुधीर सक्सेना का है, जो इस वक्त प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि दूसरा नाम पवन जैन का है। वे होमगार्ड के डीजी हैं। इनमें से सुधीर सक्सेना का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन अगले डीजीपी के लिए जो सूची तैयार की गई है, वह मुख्यमंत्री के पास पिछले डेढ़ महीने से है। पूर्व में प्रदेश सरकार ही डीजीपी की पदस्थापना कर देती थी, लेकिन इस समय नियम बदल गए हैं और सूची यूपीएससी को भेजी जाती है। हालांकि सरकार द्वारा तय नाम के अनुसार ही डीजीपी के नाम पर मुहर लगाई जाती है। लेकिन अभी सूची मुख्यमंत्री के पास है और वर्तमान डीजीपी 5 मार्च को रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में संशय की स्थिति बनी हुई है कि प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा?

उधर, प्रदेश में आने वाले समय में एडीजी और आईजी का टोटा हो जाएगा। प्रदेश में वर्तमान समय में आईजी के 36 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 22 ही आईजी हैं। वहीं 2025-26 में एडीजी की कमी बढ़ जाएगी। उधर, अगले साल तक प्रदेश में डीआईजी की भरमार हो जाएगी। 2023 में डीआईजी के पदों की संख्या दोगुनी यानी 45 हो जाएगी। वहीं प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के 1995 बैच तक के अधिकारियों की डीपीसी समाप्त हो चुकी है और 1996 बैच के अधिकारियों की डीपीसी शुरू हो गई है। 1995 बैच के तीन अधिकारियों को आईपीएस बनाया गया है, इनमें सुनील तिवारी, संजीव सिंह और संजीव कंचन का नाम शामिल है।

आईपीएस के साथ ही आईएएस कैडर में भी इस साल कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। खास बात यह है कि इस साल जो अफसर सेवानिवृत्त होंगे उनमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का नाम भी शामिल है। उनके अलावा सरकार के बेहद करीबी माने जाने वाले कई अफसरों को भी इसी साल सेवानिवृत्त होना है, जो बेहद अहम पदों पर कार्यरत हैं। इनमें कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेंद्र सिंह, एनवीडीए उपाध्यक्ष आईसीपी केशरी के अलावा केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सचिव स्तर के तीन अधिकारी भी शामिल हैं। सेवानिवृत्ति की शुरुआत 31 जनवरी को सहकारिता आयुक्त नरेश पाल कुमार व शिवपाल के रिटायर होने से होगी। केंद्र में सचिव स्तर के अधिकारी अनिल कुमार जैन, संजय कुमार सिंह तथा राजेश कुमार चतुर्वेदी भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके अलावा एनवीडीए के उपाध्यक्ष एवं एसीएस आईसीपी, केशरी, एपीसी शैलेंद्र सिंह, आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे, ग्वालियर कमिश्नर आशीष कुमार सक्सेना, बेला देवर्षि शुक्ला, डेयरी फेडरेशन के एमडी शमीम उद्दीन तथा जगदीश चंद्र जटिया भी इसी साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्य सचिव 30 नवंबर को रिटायर होंगे। इससे पहले नए सीएस की नियुक्ति हो जाएगी। वैसे बैंस को एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, लेकिन सीएस की दौड़ में 89 बैच के आईएएस अधिकारी शामिल हैं।

आईपीएस और आईएएस कैडर में वरिष्ठ अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाले पदों की लॉबिंग के लिए अभी से अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। आने वाले समय में प्रशासनिक वीथिका में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रशासनिक मुखिया के लिए भी कई अफसर कतार में खड़े हैं। जबकि पुलिस विभाग के नए मुखिया की कवायद अंतिम दौर में है।

● सुनील सिंह

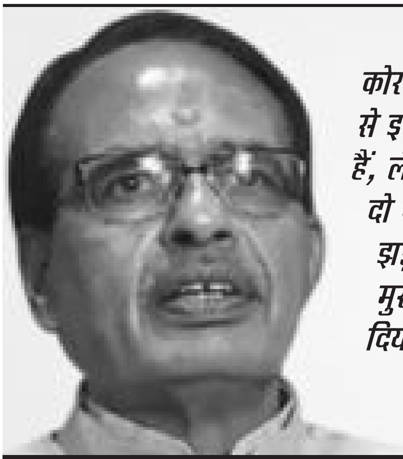

'कोरोना संक्रमण के कारण माननीय भी मीडिया से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से संपर्क में रह रहे हैं, लेकिन इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही दो पूर्व मुख्यमंत्रियों ने रूबरू होकर आरोपों की झड़ी लगाई। दिलचस्प पहलू यह रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि संघ महाराज को मुख्यमंत्री बना दे तो हम उसका विरोध करना बंद कर देंगे।'

महाराज को सीएम बना दो तो छोड़ देंगे विरोध...!

वर्ष 2022 के पहले महीने का पहला पखवाड़ा ही राजनीतिक दांवपेंच से भरा रहा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो या फिर मप्र में पंचायत चुनाव का मामला, राजनीति गर्म रही। इस महीने में मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तापक्ष और विपक्ष पर आरोपों की बौछार की। सबसे अधिक चर्चा में दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रही। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे हिंदू और संघ विरोधी कहा जाता है, तो मैं संघ से कहना चाहता हूं कि वह मप्र में महाराज (ज्योतिरादित्य सिंधिया) को मुख्यमंत्री बना दें तो मैं उसका **विरोध करना बंद कर** दूंगा। हालांकि उनकी इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि दिग्गी राजा ऐसे शगूफा छोड़ते रहते हैं।

यही नहीं अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से बात चल रही है कि मैं हिंदू विरोधी हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से आता हूं जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। मेरे गृह स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें अलग-अलग भगवान विराजमान हैं। संघ के बारे में उन्होंने कहा कि संघ के लोग मेरे पास आए थे। राजमाता सिंधिया मुझे जनसंघ में आने के लिए कहती थीं, लेकिन मैंने राजमाता से जनसंघ में जाने के लिए मना कर दिया था। मेरे पिताजी कभी हिंदू महासभा में नहीं गए। ये लोग हिंदू-मुस्लिम के बीच कटुता फैलाते हैं। सिर्फ संघ ही नहीं विश्व में कई संगठन हैं, जो अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। भारत में कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुए, सियासी युद्ध जरूर हुए हैं।

उधर, मप्र में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर शिकायत गर्माती दिख रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अटकने का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा है। साथ ही कहा है कि अगर प्रदेश की सरकार 2 महीने के भीतर परिसीमन, रोटेशन और ओबीसी आरक्षण के साथ ग्राम पंचायत चुनाव नहीं कराती तो कांग्रेस पार्टी जिला स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आंदोलन करेगी। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। कमलनाथ ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि मप्र में पिछले 7 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह भाजपा सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी नीति है। ऑर्डिनेंस के जरिए शिवराज सरकार एक ऐसा काला कानून लेकर आई जिसमें न रोटेशन का पालन किया गया, न परिसीमन का और न आरक्षण का, इसी काले कानून की वजह से चुनाव रद्द हो गए। कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने परिसीमन और रोटेशन का मुद्दा उठाया था, लेकिन जब कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया तो सरकार के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं की।

अमृत महोत्सव की तैयारी

एक तरफ प्रदेश में कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह निरंतर सक्रिय हैं और सत्तापक्ष पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि हम तो इन दोनों का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि समारोहपूर्वक पार्टी से इनकी विदाई कर दी जाए। उनका यहां तक कहना है कि जब तक ये दोनों राजनीति से दूर नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। इसलिए इन दोनों नेताओं को हम ससम्मान पार्टी से विदा करना चाहते हैं।

शिवराज के सोनिया से सवाल

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारवार्ता में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर कांग्रेस आलाकमान और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि यह संयोग नहीं, साजिश थी, षड्यंत्र था। शिवराज सिंह ने कहा- मैडम गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं- कोरोना वाला बयान जारी करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री बिना मास्क लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए? प्रधानमंत्री के दौरे में मुख्यमंत्री क्यों नहीं थे? प्रधानमंत्री के काफिले के साथ मुख्य सचिव क्यों नहीं थे? डीजीपी की गाड़ी खाली क्यों चली? प्रधानमंत्री का दौरा हो और मुख्यमंत्री ना रहे, सीएस और डीजीपी की गाड़ी भी खाली हो, क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि इनको घटना के बारे में पता था? प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को किसने दी? कम समय में इतने प्रदर्शनकारी कैसे इकट्ठे हो गए? रूट सुरक्षित होने का मैसेज प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को क्यों दिया? दिक्कत थी, तो समय रहते खतरे से आगाह क्यों नहीं कराया गया? वो कौन से अफसर हैं, जो दौरे के अलर्ट के बाद भी जरूरी कदम नहीं उठा रहे थे? मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय के अफसरों के फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कॉल नहीं रिसीव किया। पंजाब के मुख्यमंत्री किस घटना का इंतजार कर रहे थे? जिस फ्लाईओवर पर काफिला फंसा था, वो पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही किमी दूर था। यदि घटना होती, तो कौन जिम्मेदार होता? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संबंध में गलत जानकारी देना राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का जुर्माना सिर्फ 200 रुपए है?

● जितेंद्र तिवारी

फिर याद आई मनरेगा की

पिछले साल नवंबर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 यानी मनरेगा में काम मांगने वालों की तादाद में उछाल आया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते उपजी बीमारी कोविड-19 के बाद स्थितियों में सुधार के चलते पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में इसमें काम मांगने वालों की तादाद अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई थी। पिछले कुछ महीने में कोविड-19 के चलते आर्थिक गतिविधियों में पाबंदियां कम होती गई हैं। इसके बावजूद मांग का बढ़ना गांवों में लोगों के आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है।

मनरेगा पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवंबर में 2.11 करोड़ और दिसंबर में 2.47 करोड़ परिवारों ने इस रोजगारी गारंटी योजना में काम की मांग की। यह अक्टूबर में 2.07 करोड़ परिवारों की मांग में वृद्धि को दर्शाता है। गौरतलब है कि यह मई 2020 के बाद सबसे कम मांग वाले महीनों में से एक था, जब पूरे देश में महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था।

सितंबर 2021 के बाद इस योजना में काम की मांग सबसे ज्यादा दिसंबर 2021 में दर्ज की गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, इस ट्रेंड की मासिक बेरोजगारी दर से भी पुष्टि होती है, जो दिसंबर में 7.91 फीसदी थी। यानी सितंबर के बाद सबसे अधिक, जब यह 6.86 फीसदी थी। मांग बढ़ने का **यह आंकड़ा उस समय** का है, जब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते मरीजों की तादाद में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं आई थी। जनवरी में अब तक (7 जनवरी 2022 तक) 68 लाख परिवार मनरेगा में काम की मांग कर चुके हैं।

बीते साल के सारे महीनों में मनरेगा में काम मांगने वालों की तादाद 2 करोड़ से ऊपर बनी रही। यह इस बात का संकेत है कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार के बावजूद हालात अभी महामारी से पहले के स्तर पर जैसे नहीं हो सके हैं। बड़ी तादाद में काम करने वाले मजदूर, जो 2020 में अपने काम करने की जगहों से गांव लौटे थे, अभी तक शहर वापस नहीं गए हैं और मनरेगा में काम मांग रहे हैं। आमतौर पर योजना में काम मांगने वालों की तादाद केवल फरवरी से लेकर जून के बीच दो करोड़ से ऊपर जाती है और यह मई और जून में सबसे ज्यादा होती है। ऐसा 2018-19 और 2019-20 दोनों वित्त-वर्षों में पाया गया।

वित्त-वर्ष 2021, जिसके पूरे होने में अभी ढाई महीने बाकी हैं, मनरेगा में काम की औसत मांग 2.37 करोड़ परिवार रही है। जबकि 2019-20 में औसतन 1.88 करोड़ परिवारों ने योजना में काम मांगा था। हालांकि गुजरते वित्त-वर्ष की यह मांग, 2020-21 की मांग से कम है, जिसमें इस योजना में काम मांगने वाले परिवारों की तादाद 2.55 करोड़ थी। मांग की तादाद के अनुपात में जहां तक काम पाने वालों का सवाल है, तो पिछले साल के अंतिम दो महीनों में काम मांगने वाले कुल 4.58 करोड़ परिवारों में से 3.53 करोड़ परिवारों को ही काम मिला। इनमें से 1.75 करोड़ परिवारों को बीते नवंबर में और 1.78 करोड़ परिवारों को दिसंबर में काम दिया गया।

मनरेगा के लिए धन की कमी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को श्रम बजट के लिए सहमत हुए और वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर धन जारी किया जाता है। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 से बजट अनुमान (बीई) के स्तर पर 18 फीसदी से अधिक धन आवंटन में वृद्धि हुई है। जो कि 61,500 करोड़ से 73,000 करोड़ रुपए है। अंतरिम उपाय के रूप में मनरेगा के लिए हाल ही में अतिरिक्त कोष के रूप में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बात की जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा को दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निधि जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग को ध्यान में रखते हुए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा उपलब्ध धन वर्तमान वेतन देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

मनरेगा के तहत मांग में लगातार वृद्धि, इस योजना के तहत अधिक धन के आवंटन का सवाल भी उठाती है। इस साल के बजट में इसके लिए वित्तीय आवंटन को 61,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। लेकिन इस योजना में अब तक के वास्तविक खर्च 99,770 करोड़ रुपए को देखते हुए यह राशि मोटे तौर पर काफी नहीं है। इस राशि में मजदूरी और अन्य दूसरे घटकों के रूप में किए जाने वाले लंबित भुगतान भी शामिल हैं। 11,569 करोड़ बकाया भुगतान में से 1,552 करोड़ रुपए मजदूरों की मजदूरी के हैं। जो राज्य यह मानते हैं कि यह योजना, रोजगार पैदा करने के लिए है, उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में हर साल सृजित रोजगार दिवसों की सीमा को पहले ही पार कर लिया है, जबकि इस वित्त-वर्ष के पूरा होने में अभी **ढाई महीने** से ज्यादा का वक्त बाकी है। केंद्र के नियम के मुताबिक, मनरेगा में काम मांगने वाले को साल में कम से कम 100 दिन काम दिया जाना जरूरी है।

नवंबर में 80 सामाजिक-कार्यकर्ताओं के एक समूह ने महामारी के बाद मनरेगा में मांग में वृद्धि के बावजूद योजना में धन की भारी कमी को लेकर आवाज उठाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखकर उनसे योजना के लिए वांछित फंड को जारी कराने की मांग की थी। पत्र में उन्होंने लिखा था, 'धन की कमी के चलते काम की मांग को दबाया जाता है और इससे मजदूरों को उनकी मजदूरी के भुगतान में देरी होती है। ये इस अधिनियम का उल्लंघन है और इससे आर्थिक सुधारों में भी बाधा पड़ती है।'

● लोकेंद्र शर्मा

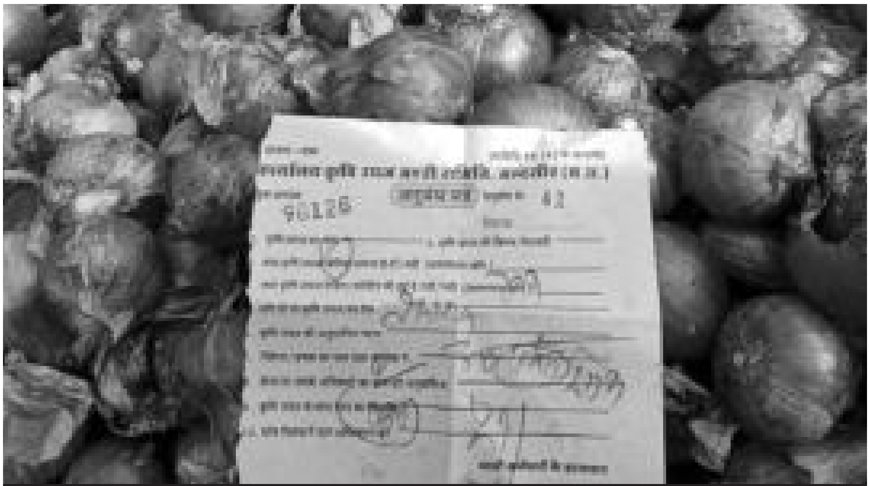

किसानों को भी रुला रहा है प्याज!

एक ओर जहां किसान नए कृषि कानून बिल की वापसी के बाद घर को रवाना हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मप्र के नीमच में किसान प्याज की मार झेल रहे हैं। मंडी में आने वाले किसानों को उनके प्याज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि मालवा का नीमच जिला जहां पर लहसुन व प्याज की सर्वाधिक खेती की जाती है, इन दिनों यहां के किसान परेशान व निराश दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन दिनों मंडी में प्याज व लहसुन की बंपर आवक देखी जा रही है। किसान मप्र, राजस्थान के कई जिलों से प्याज और लहसुन लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनकी प्याज और लहसुन के सही दाम नहीं मिलने से किसान निराश व परेशान दिखाई दे रहे हैं।

मंदसौर जिले के विपिन शर्मा ने 47 हजार रुपए लगाकर 8 क्विंटल प्याज उगाया। नए साल में वे अपना प्याज बेचने मंदसौर पहुंचे। कीमत मिली 51 रुपए प्रति क्विंटल। यानी एक किलो प्याज पर उन्हें मुश्किल से 51 पैसे प्रति किलो की दर मिल रही थी। उन्होंने इतनी कम कीमत पर प्याज बेचने के बजाय उसे मंडी में ही छोड़ना ठीक समझा। शर्मा कहते हैं, मैंने 15 हजार रुपए का तो बीज ही खरीदा था। आधा एकड़ में प्याज लगाने की कुल लागत 47,000 आई थी। अब कोई प्याज का दाम देने को तैयार नहीं है। मैंने अपनी फसल मंडी में छोड़ना ही ठीक समझा। इन दिनों देश के अलग-अलग मंडियों में प्याज की आवक हो रही है, लेकिन हर जगह से किसान दाम कम मिलने की शिकायत कर रहे हैं और मंडी में क्विंटलों प्याज बिना बेचे छोड़कर आ रहे हैं।

शर्मा का कहना है कि बहुत से किसान इस बार निराश हुए। पहले लहसुन का ऐसा हाल हुआ, और अब प्याज का। इस बार पहले बीमारी लगने के कारण फसल खराब हुई, उसके बाद अब लागत भी नहीं निकल रही। मेरी फसल में जलेबी रोग हो गया था, जिससे फूल गोल होकर मर गए और पैदावार बहुत काम हुई। इस रकबे में लगभग 30 क्विंटल प्याज निकलती है पर इस बार केवल 8 क्विंटल ही उपज हुई। इसी जिले के रघुवीर सिंहजी ने 3 जनवरी को मंदसौर मंडी में 30 क्विंटल प्याज 12,000 रुपए में बेचा। उन्हें इस सौदे के बाद 18,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। वे कहते हैं, मेरी एक एकड़ में हुई 30 क्विंटल प्याज, मात्र 4 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिकी। मेरी लागत ही 8 से 9 रुपए प्रति किलो की दर से लगी है। इसके बाद गांव से मंडी तक ट्रैक्टर में लाद के लाने में भी खर्च लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा जब मुनाफा तो दूर, लागत भी नहीं निकली।

व्यापारियों का यह कहना कि प्याज खराब है, यह सच नहीं है। बारिश के कारण प्याज खराब हुई थी मगर खराब माल को खाद बना लिया गया या पशुओं को खिला दिया। अब जो प्याज हम बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता सही है। पूरे देश में 2019-2020 में 26,855.93 हजार टन प्याज की उपज हुई। मप्र में 4082.90 हजार टन प्याज की पैदावार हुई, जो कि पूरी उपज का 15 प्रतिशत है। प्याज पर समर्थन मूल्य न होने पर जिले के दूसरे किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। यही हाल है मंदसौर के बूढ़ा गांव के दिलीप पाटीदार का। उन्होंने 675 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मंदसौर मंडी में प्याज बेचकर घाटे का सौदा किया है। इस वर्ष तो प्याज के दाम कुछ ज्यादा ही गिर गए। पाटीदार का कहना है कि मैंने 15 क्विंटल प्याज 10,125 रुपए में बेची। दो बीघे (लगभग एक एकड़) में, 45,000 रुपए की लागत लगाकर फसल उपजाई थी, मगर मुझे तो लागत का 22 प्रतिशत भी दाम नहीं मिला। सरकार को प्याज और अन्य सब्जियों पर एमएसपी तय करनी चाहिए नहीं तो ऐसे कब तक किसान नुकसान झेलते रहेंगे? कृषि उपज मंडी, मंदसौर के सचिव पर्वत सिंह सिसोदिया कहते हैं कि जनवरी से हुई प्याज की खरीदी में प्याज 100 रुपए प्रति क्विंटल से 1900 प्रति क्विंटल की दर से बिक रही है। कृषि उपज मंडी में व्यापारी बोली लगाते हैं, और प्याज की गुणवत्ता देखकर उसे खरीदते हैं। इस बार 100 रुपए क्विंटल के दाम से बोली शुरू हो रही है। बारिश के कारण किसानों की फसल खराब भी हुई थी, इसलिए इस बार दाम कम मिल रहा है।

मप्र की आम किसान यूनियन के प्रमुख कदर सिरोही इस बात का दोष मार्केट फोर्सेज को देते हैं। उनके हिसाब से यह कुछ बड़े व्यापारियों का मुनाफा कमाने का तरीका है। प्याज मप्र के मालवा क्षेत्र की एक बड़ी फसल है। जैसे ही पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते हैं, वैसे ही प्याज, लहसुन और आलू का दाम सबसे पहले बढ़ता है। ये व्यापारी किसान से कम दाम पर खरीदकर रिटेल में प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो बेचते हैं। दूसरी चीजों में प्रोड्यूसर को कम से कम 40-50 प्रतिशत का मुनाफा होता है, पर यह बात किसानों पर लागू नहीं होती। यहां तो 90 प्रतिशत से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन खुदरा व्यापारियों को मिल रहा है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

अच्छी प्याज को भी नहीं मिल रहा भाव

किसानों का कहना है कि प्रदेशभर की कई मंडियों में मीडियम प्याज 3 रुपए प्रति किलो से लगाकर 4 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है और अच्छी क्वालिटी वाला प्याज 12 से लगाकर 18 रुपए तक बिक रहा है। तो वहीं दूसरी ओर लहसुन 11 रुपए प्रति किलो से लगाकर 18 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। ऐसे में उन्हें बुवाई का खर्चा व मंडी में लाने का भाड़ा तक भी नहीं निकल पा रहा है। वहीं देश में पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कृषि कार्य में पेट्रोल-डीजल का इस्तेमाल ट्रैक्टर में किया जाता है। किसान को हमेशा नुकसान ही होता है। जिससे किसान निराश दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्याज और लहसुन जब खेत में एक बीघा के अंदर बोया जाता है, तो 35 हजार से लगाकर 40 हजार तक का खर्च आता है। कम से कम मंडी में 4 हजार क्विंटल के अनुमान से तो भाव मिलने ही चाहिए।

आत्मनिर्भर मप्र का बजट

'मप्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार का फोकस है कि बजट ऐसा हो जो आत्मनिर्भर मप्र अभियान को पूरा करने में मददगार हो। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे बजट में ऐसी चीजें समाहित करें, जिससे आत्मनिर्भर मप्र को बल मिले।'

सरकार ने मार्च में प्रस्तुत होने वाले बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह उत्साहित दिख रहे हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित होगा। शिवराज सरकार का आगामी बजट निश्चित रूप से प्रदेश की दिशा तय करने वाला होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट शिवराज सरकार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इस मायने में कि राज्य में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य को संकट से उबारने में मदद मिली है। हालांकि वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत अभी भी है।

प्रदेश का बजट इस बार ढाई लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। स्वयं का राजस्व बढ़ाने पर सरकार द्वारा जोर दिया जाएगा। साथ ही विभागों को बजट से अतिरिक्त भी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में तीन प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रखे जाएंगे तो महंगाई भत्ते के लिए वेतन मद में कुल प्रस्तावित राशि का 32 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

अब तक की तैयारियों से माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट के जरिए सरकार बड़ा संकल्प जाहिर कर सकती है। सरकार के लिए यह बजट चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है। माना जा रहा है कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मप्र का खाका खींचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस बार का बजट अवसर सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि जोखिम लेकर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, वे सभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हुए हैं। कोरोना संकट से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है। यह शुभ संकेत हैं, क्योंकि सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसके लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक जरूरत होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को अतिरिक्त आय सृजित करने के लक्ष्य भी दिए हैं। जीएसटी के बाद राज्य के पास टैक्स लगाने का दायरा सीमित हो गया है। ऐसे में उन विकल्पों पर विचार करना होगा, जिनके माध्यम से सरकार जनता पर कर का बोझ बढ़ाए बगैर आय बढ़ा सकती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने देशभर के नामचीन विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन के बाद आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार किया है। इसमें सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विषम परिस्थितियों में बेहतर प्रबंधन करते आए हैं, वैसा ही इस दौर में भी वे बजट के माध्यम से करेंगे। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कदम उठाने से वह नहीं झिझकेंगे।

बजट भाषण के लिए सभी विभागों से आत्मनिर्भर मप्र को लेकर किए गए कामों का ब्यौरा मांगा गया है। दरअसल, बजट के माध्यम से सरकार यह बताएगी कि मप्र ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। चाहे निवेश

मिशन 2023 की दिखेगी झलक

वर्ष 2023 में मप्र का विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि इस बार के बजट में जनता को अधिक से अधिक सहूलियतें प्रदान की जाएं। इसलिए इस बार के बजट में जनता के लिए कई प्रकार की सौगातें मिलने की संभावना हैं। राज्य की वित्तीय स्थितियों के जानकार मानते हैं कि आगामी बजट का फायदा मुख्यमंत्री एक अवसर की तरह उठाने की कोशिश करेंगे। इसे ध्यान में रखकर ही बजट की तैयारी भी हो रही है। आत्मनिर्भर मप्र के तहत तय किए लक्ष्यों को वर्ष 2023 तक पूरा करने के लिए विभागवार राशि का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त आय के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 15 जनवरी के बाद बजट भाषण में शामिल किए जाने वाले विषयों पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे। वर्ष 2021-22 में सरकार ने कोरोना संकट के दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इसके लिए अधोसंरचना विकास के कामों पर सर्वाधिक ध्यान दिया था। इसकी वजह से केंद्र सरकार से प्रदेश को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए अधिक भी मिले हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों को रोजगार फिर से जमाने के लिए बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण दिलाया गया। सरकार का फोकस सबसे अधिक युवा वर्ग पर है। इसलिए सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने वाले संसाधनों पर जोर देगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे लोगों को काम देने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है और बजट में इस पर फोकस किया जाएगा।

बढ़ाना हो या अधोसंरचना विकास के काम हों, प्रदेश किसी राज्य से पीछे नहीं है। कृषि के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मसूर, सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी गई। इससे किसानों को सुविधा मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगने वाली ऑक्सीजन के लिए लगभग 200 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। चार नए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अटल प्रोग्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी बजट प्रस्तावों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं। सभी विभागों से वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए 15 जनवरी तक उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रमों के अंतर्गत आत्मनिर्भर मप्र की योजनाएं और उनकी उपलब्धियां मांगी गई हैं।

मप्र के बजट में इस बार शिक्षा को प्राथमिकता, जनता से सुझाव शिवराज सरकार ने मांगे है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक के साथ जनता से सुझाव मांगने के लिए लिए आग्रह किया है। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य सरकार ने बजट में क्या हो इसके लिए सुझाव मांगे हो। इसके लिए बताया जा रहा है कि प्रयास यही है कि बजट सभी के लिए बेहतर हो, हर वर्ग का ध्यान रखा जाए। हालांकि सरकार विशेषज्ञों की राय भी ले रही है, विभागीय स्तर पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है। कॉलेज बंद होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इसके लिए सरकार बजट में विशेष प्रावधान करने की तैयारी में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर मप्र सरकार ने शिक्षा पर हो बल, सुरक्षित हो कल शीर्षक से एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि शिक्षित बच्चे ही भविष्य में देश-प्रदेश की उन्नति का आधार बनेंगे। उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए बजट में योजनाएं बनाना भी जरूरी है।

विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली लोक लेखा समिति सदन में आने वाले मामलों पर सिफारिशें कर विभागीय मंत्री और अफसरों को उन्हें पूरा करने की अनुशंसा करती है। लेकिन ऐसी 145 अनुशंसाओं पर भी अब तक विभागों ने कोई काम नहीं किया है, जिसकी वजह से वे अधूरी पड़ी हुई हैं। इनमें वाणिज्यिक कर विभाग की सर्वाधिक 36 सिफारिशों को अब भी पूरा होने का इंतजार

मंत्रियों के 5 सैकड़ा आश्वासनों पर अफसर पड़ रहे हैं भारी

विधानसभा में सरकार की ओर से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर भले ही माननीय खुश हो जाते हैं, लेकिन यह खुशी उनकी अधूरी ही रहती है, इसकी वजह है उनका पूरा न होना। दरअसल संबंधित अफसरों द्वारा ऐसे मामलों में सरकार के आश्वासनों को पूरा करने में रूचि ही नहीं ली जाती है। हालत यह है कि अब सदन के अंदर दिए गए करीब 500 से अधिक आश्वासन अब भी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए हैं। दरअसल यह आश्वासन विधानसभा में सवाल-जवाब, ध्यानाकर्षण और बजट तथा अन्य विषयों पर चर्चा के दौरान अक्सर मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं। कुछ आश्वासन तो ऐसे होते हैं जिनमें अफसर यह कहकर रोक लगवा देते हैं कि इनका पूरा करना मुश्किल है, तब उन्हें लंबित रख दिया जाता है। इसके अलावा कई आश्वासनों को पूरा करने में अफसर रूचि ही नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वे पूरा ही नहीं हो पाते हैं। अब लंबे समय बाद विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, ऐसे में सरकार के संसदीय कार्य विभाग को एक बार फिर अधूरे आश्वासनों को पूरा करने की याद आई है। यही वजह है कि अब मंत्रियों के आश्वासन और लोक लेखा समितियों की सिफारिशों को पूरा करने के लिए कहा गया है। इस मामले में सबसे खराब हालात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। इस विभाग में सर्वाधिक 80 आश्वासन अधूरे पड़े हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कृषि विभाग है, जिसमें 62 आश्वासनों को पूरा होने का इंतजार है। अन्य विभागों में नगरीय विकास तथा आवास विभाग में 44, गृह विभाग में मंत्रियों के 42 आश्वासनों पर अमल नहीं हुआ है।

बना हुआ है। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग से जुड़ी 21, पशुपालन विभाग की 19 और राजस्व विभाग की 14 सिफारिशों के अब भी पूरा होने का इंतजार है। इसके अलावा गृह, नगरीय प्रशासन, वन, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति कल्याण, जलसंसाधन, महिला एवं बाल विकास, खनिज, नर्मदा घाटी विकास, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय विभागों से जुड़ी सिफारिशों पर भी अमल नहीं किया गया है।

नए वित्त वर्ष के इस बजट की खासियत यह होगी कि उसमें पूरी तरह से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इस बजट में आत्मनिर्भर मप्र के रोडमैप की पूरी झलक दिखेगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने विभाग से जुड़े प्रस्तावों को आत्मनिर्भर मप्र के तहत ही तैयार करने के लिए कहा है।

उधर, सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाले विकास कार्यों के लिए फंड जुटाना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े मप्र के हिस्से के भुगतानों को लाने के प्रयास किए जाएं। गौरतलब है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर फंड की मांग कर चुके हैं। अब बजट से पहले मप्र के हिस्से के बजट को केंद्र से लाना सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार को मालूम है कि वित्तीय संसाधन जुटाने के जितने भी मार्ग हैं, सबको अपनाया जा चुका है। अब केंद्र के पास लंबित पड़े मप्र के हिस्से के बजट को लाना है। उधर, मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश पर कई विभागों के फंड में कटौती की तैयारी की जा रही है। विभागों में बेवजह होने वाले खर्चों को रोका जाएगा।

● विकास दुबे

लगेगा 10 फीसदी का करंट

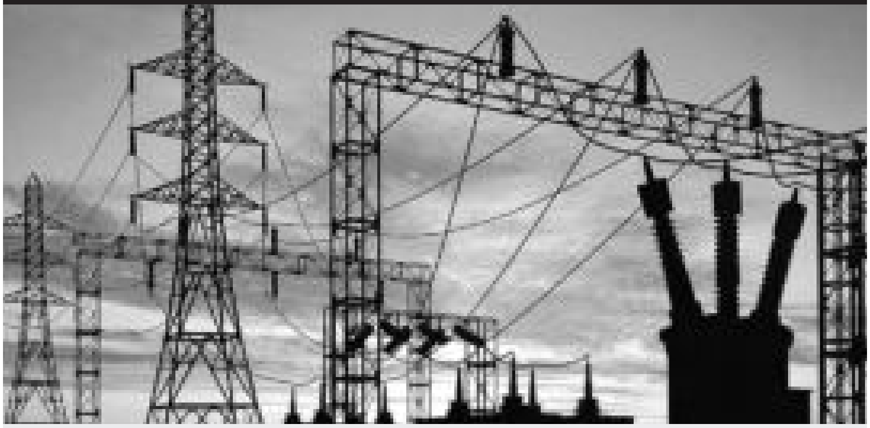

ऑडिट में सामने आया पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का गड़बड़झाला

प्रदेश में एक तरफ बिजली कंपनियां घाटे का हवाला देकर बिजली दरों में लगातार वृद्धि कर जनता पर बोझ डाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर 452 करोड़ की लागत से 155 ट्रांसफॉर्मर खरीदे है, जिन पर ज्यादा राशि खर्च की गई है। कंपनी के इस गड़बड़झाले का खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने आपत्ति उठाई है कि ज्यादा कीमत पर ट्रांसफॉर्मर क्रय करने और टेंडर प्रक्रिया का पालन सही ढंग से नहीं करने की वजह से सरकार को 58.51 करोड़ की चपत लगी है। गौरतलब है कि मप्र पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी प्रदेश में पारेषण प्रणाली का विकास, रखरखाव और मरम्मत के साथ ही ट्रांसफॉर्मर की खरीदी करती है। कंपनी ने प्रदेश में विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना करने 155 ट्रांसफॉर्मर खरीदने 19 टेंडर जारी किए थे। कंपनी इसके लिए कम दर का निर्धारण नहीं कर सकी और महंगी दर पर ट्रांसफॉर्मर खरीदने के लिए पिछली खरीदी की तुलना में उच्च मूल्य पर खरीदने को मजबूर हुई। कंपनी एल-2 बोलीदाता से एल-1 पर की गई खरीदी दर को प्रतिबंधित करने में भी विफल रही और समझौते में मूल्य गिरावट की धारा और 50 प्रतिशत मात्रा में कमी की शर्तों को शामिल करने में विफल रही। कंपनी ने 18 टर्नकी ठेकों में से 12 टर्नकी ठेकों में (बीपीआईटीएस) की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए ट्रांसफॉर्मर क्रय किए, जिसके चलते सरकार को 58.51 करोड़ की चपत लगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी कुशलता से धन का प्रबंधन नहीं कर सकी, जिसके कारण वित्तीय संस्थाओं को ब्याज के भुगतान के रूप में हानि उठानी पड़ी। इसके अलावा धनराशि अवरुद्ध रखने, कमीशनिंग में देरी हुई। क्योंकि स्थापना के लिए साइट की तैयारी किए बिना ट्रांसफॉर्मर की खरीदी के आर्डर दे दिए थे।

बिजली की दरों को बढ़ाने की याचिका पर बीते साल अफसर चुप्पी साधे हुए थे। सरकार का पहले ही दबाव था कि याचिका को लेकर किसी तरह का हल्ला न हो। शायद डर था कि बिजली बढ़ोतरी की हकीकत विपक्ष को राजनीति का मौका न दे दे। अब मप्र विद्युत नियामक आयोग ने याचिका को सार्वजनिक किया है, जिसमें घरेलू बिजली को 9.97 फीसदी महंगा करने का प्रस्ताव है। आयोग ने आमजनों से 21 जनवरी तक याचिका पर अपत्ति मांगी है।

प्रदेश में बिजली कंपनियां वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपभोक्ताओं को जोरदार झटका देने की तैयारी में है। बिजली कंपनियों की ओर से घरेलू बिजली में लगभग 10 प्रतिशत तो खेती-किसानी के लिए दी जाने वाली बिजली की दरों में साढ़े 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी करने की याचिका लगाई है। बिजली कंपनियों की मनमानी न थोपी जाए इसके लिए 21 जनवरी तक बड़ी संख्या में नियामक आयोग के समक्ष दावे-आपत्तियां पेश करना होगा। मप्र राज्य नियामक आयोग 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच दावे-आपत्तियों पर जनसुनवाई आयोजित करेगी।

प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है। तीनों कंपनियों ने इस दौरान 67 हजार 964 मिलियन यूनिट बिजली बेचने का अनुमान लगाया है। कंपनियों का दावा है कि **वर्तमान कीमत** पर बिजली बेचने पर उन्हें 44 हजार 957 करोड़ रुपए ही मिल पाएंगे। तीन हजार 915 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए तीनों कंपनियों ने आसान उपाय निकाला है कि इसे उपभोक्ताओं की जेब से वसूला जाए। इसके लिए बिजली की औसत दरों में 8.71 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

कंपनियों ने रेलवे को बेची जाने वाली बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी तरह ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और व्यवसायिक ई-चार्जिंग स्टेशन की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनियों की कोशिश है कि रेलवे और बिजली खरीदे। जबकि ई-व्हीकल वाहनों को प्रोत्साहन देने की नीति के चलते उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगभग 2 हजार करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2019-20 की ट्रू-अप याचिका के तौर पर वसूलने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल हर साल बिजली कंपनियां टैरिफ याचिका अनुमान के आधार पर पेश करती है। फिर वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने पर असल खर्च का पता चलता है। इसे कंपनियां सत्यापित ट्रू-अप के तौर पर उपभोक्ताओं से वसूलती हैं।

बिजली मामलों के जानकार और सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में मप्र में सबसे ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है जबकि मप्र में जरूरत से ज्यादा बिजली उत्पादन का दावा किया जा रहा है। यहां कोयला, पानी प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद बिजली के दाम इस कदर बढ़ाना आम जनता के साथ धोखा है। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कंपनी को अपने फिजूल खर्च को कम करना चाहिए। ज्ञात हो कि इस साल गोपनीय तरीके से आयोग के पास मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के राजस्व प्रबंधन विभाग ने याचिका जमा की। याचिका के बाद राजस्व प्रबंधन का पूरा दफ्तर ही भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठाया गया।

मप्र में साल में तीन बार यू ही दाम नहीं बढ़ रहे है। लगातार बढ़ रहे घाटे की भरपाई के लिए कंपनी की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हाल ही में मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दर निर्धारण की याचिका दी है। इसमें 3915 करोड़ रुपए का अंतर दिखाया गया है। इस अंतर की राशि में साल 2019 में हुए घाटे को भी जोड़ा गया है जो करीब 2 हजार करोड़ रुपए है। इसी वजह से कंपनी ने इतने बड़े अंतर को खत्म करने के लिए 8.71 फीसदी बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है। ज्ञात हो कि बिजली कंपनी ने 2022-23 के लिए 48 हजार 874 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है। इसमें आय में करीब 3915 करोड़ रुपए की कमी बनी हुई है जिसकी भरपाई के लिए कंपनी ने बिजली की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व लक्ष्य में कंपनी को करीब 2 हजार करोड़ रुपए की कम आय हुई थी। जिसे कंपनी इस साल उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी में है।

● अरविंद नारद

पुनर्वास के पेंच में फंसा बैराज

मुरैना जिले के पिलुआ और कोतवाल डैमों से जुड़ी पेयजल परियोजनाओं और भिंड जिले में सिंचाई क्षमताएं बढ़ाने 112 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित आसन नदी के धमकन बैराज का उपयोग 3 साल बाद भी नहीं हो पा रहा है। पहला पेंच तो पुनर्वास का मामला लटक जाना ही रहा। बाद में घसटुआ घाट पर बना रपटा बैराज के डूब क्षेत्र में आ जाने से ऊंचाई वाले पुल का निर्माण भी नया पेंच बन गया।

अब पुल का निर्माण तो 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू करवा दिया गया है, लेकिन पुनर्वास का रोड़ा अब भी दूर नहीं हो पा रहा है। पुनर्वास का पेंच दूर हो जाता तो तीन साल पहले ही डैम में पानी भरा जा सकता था और इसका लाभ जौरा व सुमावली क्षेत्र के लोगों को भूजल स्तर बढ़ने के रूप में मिलता और कोतवाल व पिलुआ डैम से जुड़ी पेयजल परियोजनाओं को भी इससे ज्यादा समृद्धि मिल पाती। लेकिन बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के 215 लोगों का पुनर्वास समस्या बना हुआ है। हालांकि 132 लोगों ने मकान निर्माण के लिए भूखंड खरीदने 5-5 लाख रुपए ले लिए हैं, लेकिन भवन और अन्य संपत्ति का मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने से उनका पुनर्वास भी नहीं हो पा रहा है।

विस्थापित होने वाले 215 लोगों के सामने शासन ने दो विकल्प रखे थे। या तो मकान के लिए भूखंड ले लें या भूखंड अपनी मनपसंद जगह पर खरीदने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए ले लें। 132 लोगों ने 5 लाख रुपए ले लिए थे। लेकिन गदालपुरा व आसपास के 83 परिवारों ने मकान बनाने के लिए भूखंड की मांग की थी। हालांकि जल संसाधन विभाग ने बानमोर क्षेत्र में बरुआ नहर के पास भूखंड दिए थे, लेकिन कानूनी पेंच से **यह प्रक्रिया** निरस्त हो गई। बरुआ नहर के पास जमीन कानूनी दांव-पेंच में उलझ जाने से शासन ने जल संसाधन विभाग की मुरैना नगर में चंबल कॉलोनी स्थित जमीन पर 83 परिवारों को भूखंड आवंटन की कवायद शुरू की। लेकिन इसमें भी नियम आड़े आए और अब यह जमीन भी नहीं दी जा सकती है। विकल्प के तौर पर एबी रोड किनारे नए आरटीओ कार्यालय के पास 83 परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। इसका प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन आवंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।

आसन नदी का धमकन बैराज उपयोग में आ जाने के बाद सुमावली क्षेत्र के 60 गांवों के भूजल स्तर में सुधार की उम्मीद है। सिंचाई के अभाव में सैकड़ों बीघा बंजर रह जाने वाली जमीन पर भी सिंचाई का इंतजाम हो सकेगा। वहीं अल्प वर्षा की स्थिति में धमकन बैराज से कोतवाल और पिलुआ डैम को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। हालांकि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पानी रपटे के लेबल तक ही डैम में रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि वर्ष 2020 में वर्षाकाल में आसन बैराज में पानी का भराव किया जाना था, लेकिन ग्राम पुरा हथरिया (गदाल का पुरा) एवं आसपास के लगभग 30 ग्रामों के लोगों के विरोध के कारण यह संभव नहीं हो पाया। धमकन बैराज में पानी भरने में एक और व्यावहारिक अड़चन थी। यहां पानी भरने से धमकन-घसटुआ मार्ग पर आवागमन के लिए बना पुराना रपटा वर्षभर डूब में रहेगा, जिससे करीब 60 गांवों के आवागमन का रास्ता प्रभावित होगा। इसलिए अब यहां 24 करोड़ रुपए की लागत से नया पक्का और ऊंचा पुल निर्माण कराया जा रहा है, जो वर्ष 2023 तक पूरा हो जाएगा। आसन बैराज में पानी भरने से हथरिया, गदालपुरा सहित निटहरा, कीरतपुर, दोहरा, बगियापुरा, नूरपुर सहित आधा सैकड़ा गांवों को लाभ मिलेगा। मैना-बसई, घुरैया-बसई, टिकटौली, सुमावली, बड़ोना, गणेशपुरा के लोगों को भी लाभ मिल सकता है।

2016 में आसन बैराज निर्माण की कवायद शुरू हुई थी। बैराज 2019 में बनकर तैयार हो गया था और पानी भरा जाना था। 2020 में प्रयास करने पर ग्रामीणों ने विरोध कर दिया था। आसन बैराज के निर्माण से 215 परिवार विस्थपित हो रहे हैं। 132 परिवारों ने भूखंड के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजा लिया है। 83 परिवारों ने भूखंड उपलब्ध कराने की मांग रखी है, जो पूरी नहीं हो पा रही। सुमावली के गदालपुरा के ग्रामीण धारा सिंह कुशवाह का कहना है कि हमें पहले बरुआ नहर के पास 83 भूखंड दिए गए थे, लेकिन वहां कानूनी विवाद था। बाद में चंबल कॉलोनी में भूखंड के लिए भी **औपचारिकताएं** पूरी होकर फाइल पीएस के पास पहुंचा दी गई, लेकिन आवंटन नहीं हो पा रहा है। मुख्य अभियंता, जल संसाधन ग्वालियर आरपी झा का कहना है कि विस्थापितों को चंबल कॉलोनी में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया मानकों के अनुरूप नहीं थी। अब एबी रोड पर आरटीओ कार्यालय के पास जमीन का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है, जल्द ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद बाकी प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी।

● राकेश ग्रोवर

डैम में भरपूर पानी लेकिन सिंचाई के लिए नहीं

उधर, छिंदवाड़ा के परासिया के ग्राम मायावाड़ी-बरारिया के बीच पेंच नदी पर बनाए गए स्टाप डैम का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। डैम के पानी का कैचअप एरिया अधिक है। डैम पूरे समय भरा रहता है। लेकिन सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। नदी के दोनों तरफ मायावाड़ी और बरारिया के किसानों के लगभग 100 हैक्टेयर खेत हैं। बरारिया के पूर्व सरपंच मोहन कहार का कहना है कि तामिया परियोजना अंर्तगत जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में 72 लाख की लागत से डैम का निर्माण कराया गया था। डैम में जल भराव क्षमता अधिक है लेकिन इसका उपयोग सिंचाई में नहीं हो पा रहा है। नहर अथवा सिंचाई के अन्य साधनों से यहां फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। जल उपभोक्ता समिति नाममात्र की है। अधिकारी कहते हैं कि डैम के पानी का उपयोग केवल निस्तार और पशुओं के लिए है। सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकार का आदेश होना चाहिए। पंच गुरूप्रसाद भलावी का कहना है कि किसान सिंचाई के लिए एकमात्र पेंच नदी पर ही निर्भर है। अन्य कोई कारगर व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को प्रतिवर्ष पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। मायावाड़ी की पूर्व सरपंच सनौती तेकाम के अनुसार डैम का जलभराव लगभग तीन किमी तक है लेकिन किसान सिंचाई नहीं कर पाते है। शासन को सिंचाई के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। हालांकि किसान चोरी छिपे मोटर पंप लगाकर सिंचाई करते हैं।

नर्मदा सहित मप्र की सभी नदियों में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन नदियों में अवैध खनन रुकने की बजाय और तेजी से बढ़ रहा है। यानी सरकार के सारे प्रयास पर रेत माफिया हावी है।

रेत माफिया हावी

प्रदेश में रेत माफिया हावी है। भोपाल, होशंगाबाद सहित प्रदेश के 24 जिलों में नदियों से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि ठेके बंद होने के बाद रोज हजारों ट्रक रेत शहरों में आ रही हैं। अभी भी वही ठेकेदार रेत बेच रहे हैं, जिनके ठेके निरस्त हो चुके हैं। तमाम शिकायतों के बाद खनिज साधन विभाग ने सभी कलेक्टरों और माइनिंग अफसरों को पुराने ठेकेदारों के रेत के पुराने स्टाक का सत्यापन करने के लिए कहा है। प्रदेश में 39 जिला रेत समूह खदानों में से 24 रेत समूह खदानें बंद हैं। इसके बाद भी प्रदेश में रेत का परिवहन हो रहा है। सबसे बड़े रेत खदान समूह होशंगाबाद बंद होने के बाद भी कहीं से भी रेत की कमी महसूस नहीं हो रही है। जबकि सरकार ने सभी जिलों में रेत की आपूर्ति करने के लिए होशंगाबाद से सभी जगह रेल से रेत परिवहन करने के लिए कार्ययोजना तैयार की थी। क्योंकि एक दर्जन से अधिक जिला रेत समूह से रेत का उत्खनन पिछले एक साल से बंद था।

पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन होने से रेत का कारोबार बंद हो गया था, जिससे करीब 20 ठेकेदारों ने खदानें बंद करने और मासिक किश्त की राशि देना बंद कर दिया था। होशंगाबाद सहित अन्य खदानों को रिस्क एंड कास्ट के आधार पर रेत का ठेका दिया गया है। इससे ठेकेदार को नए ठेके जारी होने तक किश्त देना होगा। वर्तमान में होशंगाबाद के ठेकेदार पर 63 करोड़ से अधिक की देनदारी है। ठेकेदार ने दिसंबर 2021 में खदान समर्पित करने का आवेदन तो दे दिया था, पर वह अक्टूबर 2021 से रायल्टी की नियमित किश्तों का भुगतान नहीं कर रहे थे। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। सरकार प्रतिवर्ष रेत के ठेके में दस फीसदी राशि जुलाई में बढ़ोत्तरी कर देगी। इस नीति से अगर सरकार रेत समूह की नीलामी करती भी है तो जो नए ठेका लेगा उसे ठेके की राशि से 10 फीसदी अधिक राशि देना होगा। इससे ठेकेदार जुलाई से पहले ठेके लेने से घबरा रहे हैं। क्योंकि रेत नीति के अनुसार जुलाई में दस फीसदी रेत की कीमत बनाना अनिवार्य किया गया है। इससे सरकार को इस रेत नीति में फिर से संशोधन करना पड़ सकता है।

वर्ष 2019 में सरकार ने रेत खदानों के 39 समूह (जिला स्तर पर समूह) नीलाम किए थे। इनमें से 8 ठेकेदारों ने खदानें छोड़ दी हैं और 16 ठेकेदारों के ठेके निरस्त कर दिए गए हैं। इस तरह प्रदेश में वर्तमान में 15 जिलों की खदानों से ही रेत निकाली जा रही है। उल्लेखनीय है कि रतलाम, भिंड और पन्ना के ठेकेदार पहले खदानें समर्पित कर चुके हैं। बैतूल, देवास, ग्वालियर, नरसिंहपुर और डिंडोरी के ठेकेदारों ने दिसंबर में खदानें समर्पित कर दी हैं। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, रायसेन, धार, आलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, शिवपुरी, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, मंदसौर, रीवा, राजगढ़ और शाजापुर की खदानें निरस्त की गई हैं।

ज्ञात हो कि होशंगाबाद जिले की 118 रेत खदानों के समूह का ठेका 19 महीने में दूसरी बार निरस्त हुआ है। वर्ष 2019 में रेत खदानों की नीलामी में शामिल होकर तेलंगाना की पावरमैक कंपनी ने 217 करोड़ में ठेका लिया था, जिसे मई 2020 में निरस्त किया गया था। जनवरी 2021 में छत्तीसगढ़ की कंपनी आरके ट्रांसपोर्ट ने 262 करोड़ रुपए में यह ठेका लिया था। खनिज निगम ने रायल्टी की राशि नियमित रूप से नहीं मिलने पर होशंगाबाद, भोपाल, खरगोन, बड़वानी, जबलपुर, दमोह और टीकमगढ़ की रेत खदानों के समूह के ठेके निरस्त कर दिए हैं।

प्रदेश की सबसे बड़े रेत खदानों के समूह होशंगाबाद के ठेकदार पर 63 करोड़ से अधिक की देनदारी थी। ठेकेदार ने दिसंबर 2021 में खदान समर्पित करने का आवेदन तो दे दिया था, पर वह अक्टूबर 2021 से रायल्टी की नियमित किश्तों का भुगतान नहीं कर रहे थे। इसे देखते हुए ठेका निरस्त किया गया है और 65 करोड़ रुपए की सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई है। साथ ही ठेकेदार को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला गया है। रिस्क एंड कास्ट के नियम सहित अन्य प्रतिबंधों के खिलाफ ठेकेदार ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जानकार बताते हैं कि रिस्क एंड कास्ट के नियम में ठेकेदार को राहत मिल सकती है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

चंबल का सीना छलनी कर रहे माफिया

मुरैना में चंबल का सीना छलनी किया जा रहा है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों द्वारा रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। यह खनन राजघाट के नए पुल के नीचे किया जा रहा है। खनन सबके सामने व दिन में किया जा रहा है। सुबह से माफिया की जेसीबी मशीनें धड़धड़ाने लगती हैं, हजारों ट्रॉलियों की लाइनें लग जाती हैं। यह सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। सबसे अहम बात यह है कि चंबल में पर्यटक आ रहे हैं। इन पर्यटकों के सामने रेत का अवैध खनन हो रहा है। जिला, पुलिस व वन विभाग के अधिकारी अपने परिवार के साथ चंबल घूम रहे हैं। उनके सामने अवैध रेत भरा जा रहा है और रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां धड़धड़ाती गुजर रही हैं। किसी की क्या मजाल जो उन्हें रोक सके। चंबल के रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए जिले के वन विभाग को 200 से अधिक एसएएफ जवानों की कंपनी दी जा चुकी है। लेकिन विभाग ने इस कंपनी के जवानों को इधर-उधर ड्यूटी पर लगा रखा है। जबकि इन जवानों का काम राजघाट पर हो रहे अवैध खनन को रोकना है। कहना गलत नहीं होगा कि वन विभाग की सहमति से इस खनन को अंजाम दिया जा रहा है।

'माननीयों' के विकास फाइलों में कैद

म प्र में सत्ता और संगठन ने सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने और विकास कार्य कराने का निर्देश दिया है। ताकि मिशन 2023 और 2024 को आसानी से फतह किया जा सके। लेकिन 'माननीयों' के सामने समस्या यह है कि उनके पहले के विकास प्रस्ताव फाइलों में कैद हैं। ऐसे में नए प्रस्ताव कैसे दें।

जानकारी के अनुसार, 2018 में भी सत्ता और संगठन ने 'माननीयों' को निर्देश दिया था कि वे अपने क्षेत्र के ऐसे बड़े प्रोजेक्ट तैयार करें जो सीधे जनता से जुड़े हैं। उधर, विधायकों की ओर से बात सामने आ रही है कि मिशन 2018 के लिए भी बड़े प्लान दिए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। सांसद रहते ज्योति धुर्वे और आमला के विधायक रहे चैतराम मानेकर के प्रस्ताव शासन की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं होने से करीब 400 करोड़ के प्रपोजल केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचे। उधर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि विभाग द्वारा केंद्र को भेजे गए सभी प्रपोजल मंजूर कर लिए गए हैं तथा एक माह पहले राशि भी मिल गई है। केंद्रीय सड़क विकास निधि योजना में सभी प्रस्ताव शामिल नहीं हो सकते हैं। विधायकों के कामों को शासन स्तर पर प्राथमिकता में लिया जाता है।

पूर्व सांसद धुर्वे और मानेकर अकेले जनप्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि कई सांसद और विधायकों के बड़े प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग ने शासन की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किए। इनमें वर्तमान विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे और सुखदेव पांसे भी हैं। इनके प्रस्ताव भी फाइलों में दबे पड़े हैं। विडंबना यह है कि लोक निर्माण विभाग केंद्रीय सड़क विकास निधि योजना में बजट लाने में पीछे हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर तक केंद्र सरकार के पास 1811.78 करोड़ के प्रस्ताव लंबित हैं। जबकि इन्हें मंजूर करने प्रमुख सचिव आधा दर्जन स्मरण पत्र लिख चुके हैं। योजना अंतर्गत 561.03 किलोमीटर सड़क निर्माण कराए जाने के लिए राशि मांगी जा रही है।

107 करोड़ लागत का सीहोर जिले में बकतारा, सियागेहन, सागपुर, रिछोड़ा, क्वाड़ा, सतरामऊ, बोदरा, गड़िया, नीमटोन और डूंगरिया रोड के उन्नयन कार्य। सागर जिले में शाहपुर दरारिया, चनौआ जामघाट पाटई संगी, ज्वाप मार्ग लागत 126.50 करोड़। सागर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का गृह जिला है। भोपाल जिले में बैरागढ़-भोपाल मार्ग पर एलीवेटेड कॉरीडोर निर्माण के लिए 234 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ है। मुलताई विधायक सुखदेव पांसे का कहना है कि केंद्रीय सड़क निधि योजना में प्रपोजल शामिल नहीं किया। पिछले डेढ़ साल से सड़क विकास के मामले में बैतूल और मप्र की लगातार उपेक्षा की जा रही है। मेरे द्वारा मांगी गई सड़क सीआरआईएफ योजना में शामिल किया जाना था।

तत्कालीन बैतूल सांसद ज्योति धुर्वे ने जुलाई 2018 को सारणी से लांदी होते हुए रतेडाकला-जमदेही, माहोली, जंबाडा, सोनतलाई, बुंडाला सर्रा होते हुए परमंडल (एनएच 47) तक कुल 48 किमी, आठनेर से मंढा छिंदवाड़ा, गारगुड, हीरादेही, धारूल होते हुए महाराष्ट्र राज्य की सीमा तक 48 किमी तक सड़क निर्माण और 45 किमी तक पाढर से चिखली-झाडकुंड, मलाजपुर-चिचोली होते हुए भीमपुर तक सड़क निर्माण के प्रपोजल दिए हैं। आमला के विधायक रहे चैतराम मानेकर ने 120 किलोमीटर मार्ग निर्माण के लिए करीब 300 करोड़ के प्रस्ताव दिए। विधायक योगेश पंडाग्रे ने सारणी से रतेडाकला तक सड़क निर्माण का प्रपोजल दिया है। विधायक सुखदेव पांसे ने बैतूल जिले के मुलताई पिसाटा बिरूलबाजार मार्ग को बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। इनके प्रपोजल शासन की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किए गए।

● **राजेश बोरकर**

बिना इंजीनियर अधर में लटकी परियोजनाएं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 2024 तक 60 लाख हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता विकसित करने का टारगेट तय कर रखा है। यह काम जल संसाधन सहित एनवीडीए को मिलकर करना है, लेकिन दोनों विभागों में इंजीनियरों की भारी कमी है। राज्य सरकार समय रहते यदि इंजीनियरों के पदों पर भर्ती नहीं करती है, तो अगले साल 20 हजार करोड़ से ज्यादा के सिंचाई प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि जल संसाधन विभाग में 40 फीसदी पद अगले दो सालों में खाली हो जाएंगे। गौरतलब है प्रदेश में जल संसाधन और एनवीडीए के पास महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। लेकिन दोनों विभागों में इंजीनियरों की कमी बढ़ती जा रही है। 2022 में ही ईएनसी सहित 9 चीफ इंजीनियर, 14 अधीक्षण यंत्री और 50 से ज्यादा कार्यपालन यंत्री सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और इसका असर सिंचाई परियोजनाओं पर पड़ने की आशंका है। जल संसाधन विभाग के ईएनसी एमएस डाबर कहते हैं कि जल संसाधन विभाग में 2022 में प्रथम श्रेणी के करीब 50 से ज्यादा अधिकारी रिटायर होने जा रहे हैं और इससे करीब 20 हजार करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। इस संबंध में शासन को अवगत करा दिया गया है। एनवीडीए में पहले से ही इंजीनियरों की कमी के चलते संविदा पर रिटायर इंजीनियरों को रखा जा रहा है। अभी भी करीब 54 पद खाली हैं। इधर, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदेश में करीब 30 हजार करोड़ की 50 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन इन प्रोजेक्ट की गति में अडंगा लग सकता है, क्योंकि अगले साल विभाग में ईएनसी मदन सिंह डाबर सहित 9 चीफ इंजीनियर, 14 अधीक्षण यंत्री और 50 से ज्यादा कार्यपालन यंत्री रिटायर होने जा रहे हैं। इससे करीब 20 हजार करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं। अगले साल रिटायर होने वाले चीफ इंजीनियरों में रज्जन रोहित, राजेंद्र प्रसाद, गजाधर सुनैया, प्रभारी चीफ इंजीनियर एनएन गांधी, ज्ञान प्रकाश सोनी, कृष्ण गोपाल सिंह, छोटेलाल गर्ग, शिशिर कुशवाहा तथा प्रमोद कुमार शर्मा का नाम शामिल है।

4 लाख में गिरवी कॉरिडोर एरिया

मप्र के वन विभाग में किस तरह का जंगलराज चल रहा है, इसका उदाहरण माधव नेशनल पार्क में सामने आया है। यहां कॉरिडोर की 2000 हैक्टेयर भूमि को अधिकारियों-कर्मचारियों ने प्रति हैक्टेयर 2000 रुपए की दर से खेती के लिए दे दिया था। यानी सालाना 4 लाख रुपए में पार्क के स्टाफ ने वन भूमि को गिरवी रख दिया था। यही वजह रही कि 2008 के बाद जितने भी डायरेक्टर और स्टाफ आते-जाते रहे, वे सभी खेती कर रहे किसानों से राशि वसूलते रहे हैं। करीब 13 साल बाद कब्जेधारियों को बेदखल किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि 2008 में बाघ पुनर्स्थापना के तहत माधव नेशनल पार्क से 2000 हैक्टेयर कॉरिडोर एरिया को कब्जेधारियों से हटाया गया था। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त जमीन पर फिर से खेती होने लगी। अब जाकर पार्क प्रबंधन ने 2000 हैक्टेयर कॉरिडोर एरिया को कब्जेधारियों से बेदखल कराया। यह कार्रवाई तब हुई, जब प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी आलोक कुमार ने बेदखली की कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए थे।

दिलचस्प पहलू यह है कि कब्जाधारियों में ज्यादातर लोग वही थे जो 2008 में बाघ पुनर्स्थापना के तहत लाखों रुपए मुआवजा ले चुके थे। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2008 में वन विभाग ने माधव नेशनल पार्क से विस्थापन होने के लिए 27 करोड़ 99 लाख से अधिक का भुगतान बतौर मुआवजा दिया गया था। वर्ष 2008 में मुआवजा लेने के बाद भी मामौनी, हरनगर, अर्जुनगवा, चक्डोगरा और लखनगवा गांव के लोग पार्क के कॉरिडोर एरिया माता की 2000 हैक्टेयर जमीन में खेती कर रहे थे। ग्रामीणों द्वारा खेती करने के कारण 2007-08 से 2016-17 में बाघ पुनर्स्थापना की कार्रवाई लंबित रही। इस बीच माधव नेशनल पार्क में कई डायरेक्टर आए और चले गए, किसी ने भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की। ऐसे या तो तय हो गया कि उनकी पार्क के कॉरिडोर जमीन पर अवैध खेती कराने में कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता रही है। फील्ड से मिली जानकारी के अनुसार 2017-18 में सबसे अधिक अतिक्रमण हुआ। बताया जाता है कि वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक एक दर्जन से अधिक आईएफएस अफसर माधव नेशनल पार्क के संचालक रह चुके हैं। इन अफसरों की भूमिका की जांच होनी चाहिए।

माधव नेशनल पार्क के डायरेक्टर सीएस निनामा ने प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल के निर्देश मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वन्य प्राणी प्रेमियों के साथ बैठक कर पहले तो ग्रामवासियों को कॉरिडोर की भूमि से हटने के लिए समझाने की कोशिश की। जब वे नहीं माने तो राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम बनाकर पुलिस की मदद से बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की। माधव नेशनल पार्क के कॉरिडोर की जमीन शहर से लगी हुई है। इसकी कीमत 1500 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।

एक दशक पहले तक वन्य प्राणियों द्वारा किसानों के फसल नुकसान के मामले काफी कम आते थे। लेकिन विगत कुछ सालों से जंगली जानवरों से किसानों के फसल क्षति के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह वनाधिकार **पट्टों की संख्या** में तेजी से इजाफा होना है। इसके अलावा बाह्य वन क्षेत्र में खेती का रकवा भी बढ़ा है तो जंगल में विडाल वंश के जानवरों की तादाद बढ़ने से शाकाहारी जानवर वन क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं। वनों का घटता घनत्व भी एक वजह है। शासन की तय व्यवस्था के अनुसार अगर जंगली जानवर वन्य क्षेत्र से बाहर आकर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह राहत राशि वन विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व विभाग देता है।

वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो वन्य प्राणियों की प्रवृत्ति के अनुसार सामान्य स्थितियों में वे पानी की तलाश में ही वन क्षेत्र के बाहर जाते हैं। लेकिन वन क्षेत्र के हिसाब से अब शाकाहारी वन्य प्राणियों नीलगाय, चीतल, सांभर की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। यही स्थिति जंगली शूकर की है। दूसरी ओर घने क्षेत्रों में बाघ की संख्या बढ़ने पर अन्य मांसाहारी जानवर तेंदुआ आदि बाह्य क्षेत्र में भगने लगे हैं। ऐसे में बाह्य क्षेत्र के शाकाहारी जानवर भोजन के लिए वन क्षेत्र से बाहर का रुख करते हैं। पहले वन क्षेत्र से लगी गैर वनभूमि में खेती कम होती थी। लेकिन अब लोग वन क्षेत्र से लगकर खेती करने लगे हैं। यही खेती शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए आसान भोजन होता है।

● बृजेश साहू

वनाधिकार पट्टों से बढ़ेगी दखल

वन महकमे के अनुसार सरकार की नीतियों और राजनीतिक लाभ के नजरिए से वनाधिकार पट्टों के जारी करने में तेजी आई है। हालांकि वन महकमा इसको लेकर सख्त रुख रखता है इसके बाद भी तमाम पट्टे जारी हो रहे हैं। विगत 5 सालों में वनाधिकार पट्टे तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में बीच जंगल में जब खेती होने लगी और वन्य प्राणियों के रहवास में दखल बढ़ा तो लोगों पर हमले और फसल नुकसानी के मामले बढ़ने लगे। जंगल में खेती होने से जंगली जानवर यहां स्वाभाविक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। किसान कहते हैं कि शासन के जो नियम हैं वही उनकी नुकसानी में सबसे ज्यादा बाधा है। दरअसल 25 फीसदी से कम नुकसानी पर राहत राशि नहीं मिलती है। वन विभाग ज्यादातर मामलों में नुकसान 25 फीसदी से कम ही बनाता है। जबकि नुकसान ज्यादा का होता है। राजस्व विभाग कहता है कि हमें जो प्रतिवेदन मिलता है उसी के अनुसार राहत राशि का वितरण किया जाता है। किसानों का कहना है कि जो राहत राशि मिलती है वह भी काफी कम होती है। वास्तविक नुकसान उसका तीन गुना तक होता है। वन्य प्राणी संरक्षण और सुरक्षा के बीच फसलों को क्षति से बचाने की चुनौती को लेकर तत्कालीन वनमंत्री गौरीशंकर शेजवार ने 2015 में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला बुलाई थी। जिसमें तय किया गया था कि वन विभाग वनों को जानवरों के खाने-पीने, शेल्टर के लिहाज से इतना संपन्न बनाए कि उन्हें जंगल के बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। चने की बोई फसलों का शूकर के झुंड द्वारा, गेहूं की खड़ी फसलों को नीलगाय-हिरण द्वारा उजाड़ना आम बात है।

> *मप्र और उप्र के 13 जिलों वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में खुशहाली लाने के लिए सरकारों ने अबतक जो भी प्रयास किए हैं, वे कागजी साबित हुए हैं। अब अब केंद्र की पहल पर दोनों राज्यों की सहमति से केन-बेतवा लिंक परियोजना शुरू होने जा रही है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि बुंदेलखंड पानीदार बन जाएगा। यानी बुंदेलखंड में सिंचाई के साथ ही पेयजल के लिए भी पर्याप्त पानी मिलेगा और खुशहाली बढ़ेगी।*

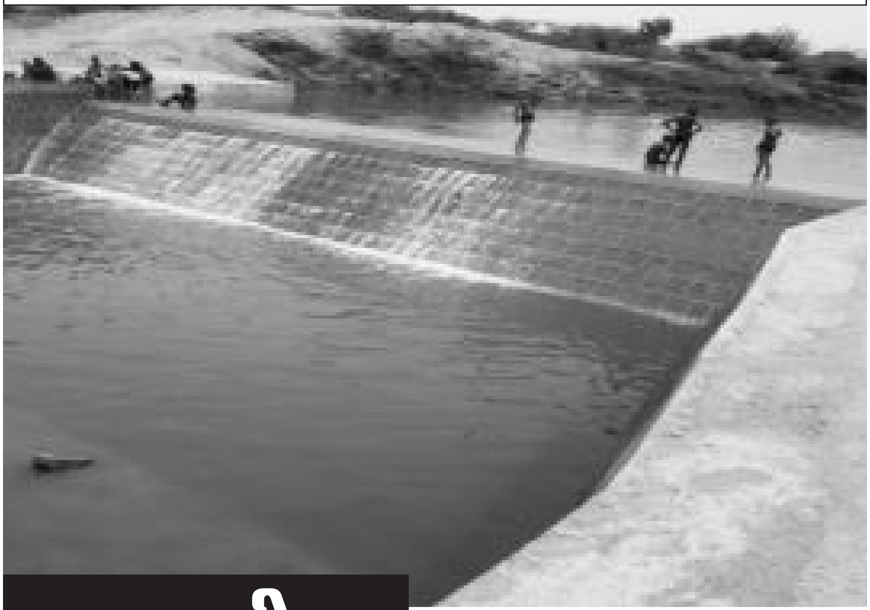

अब पानीदार बुंदेलखंड

बूंद-बूंद पानी को तरसता बुंदेलखंड 8 साल में पानीदार हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृत हो गई है। इस परियोजना से मप्र के 10 और उप्र के 4 जिलों को फायदा होगा। कृषि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रोजेक्ट के तहत मुख्य बांध केन नदी पर ढोड़न गांव में बनेगा। इसके अलावा तीन अन्य बांध बनाए जाएंगे। इनमें एक बांध बेतवा नदी विदिशा जिले में, दो बांध बेतवा की दो सहायक नदियों उर नदी, बीना नदी पर बनाए जाएंगे। इससे मप्र के 10 जिलों की 8.11 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी। साथ ही 41 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। परियोजना का डीपीआर वर्ष 2008 में तैयार किया गया था। तब परियोजना की लागत 10 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी।

13 साल तक परियोजना अटकी रहने के कारण अब प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 44605 करोड़ रुपए हो गई है। सरकार ने इस परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया है। केन नदी पर ढोड़न गांव में मुख्य बांध का निर्माण किया जाएगा। इस बांध से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा की जाएगी। परियोजना की कुल लागत में से 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार जबकि 5-5 प्रतिशत राशि मप्र और उप्र सरकारें भुगतान करेंगी। प्रोजेक्ट के तहत मुख्य बांध केन नदी पर पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ढोड़न गांव में बनाया जाएगा। इसी बांध पर बिजली बनाने की भी योजना है। ढोड़न बांध से मुख्य नहर निकलेगी। 220 किमी लंबी यह नहर छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी से गुजरते हुए झांसी जिले में बरुआसागर के पास बेतवा नदी में मिल जाएगी। इस नदी से हर साल 750 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर पानी) बेतवा पर छोड़ा जाएगा। साथ ही इस नहर से मप्र छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के खेतों में सिंचाई की जाएगी। साथ ही केन नदी के पानी से ही दमोह और पन्ना जिलों को भी 90 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

केन-बेतवा लिंक परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने वाले राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ओपीएस कुशवाह का कहना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहकर काम करना एक चुनौती था। जंगल में 25 किमी तक कोई दुकान नहीं, 40 किमी तक कोई होटल नहीं ऐसे स्थान पर इंजीनियरों को दो साल से अधिक समय तक अध्ययन करने में परेशानी हुई थी।

कुशवाह के नेतृत्व में ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के दोनों फेज के डीपीआर को तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट 11 वॉल्यूम में प्रकाशित की गई है।

डीपीआर में देश के 6 नामी संस्थान ने भाग लिया है। आईआईटी कानपुर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल सोइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, सेंट्रल वॉटर कमीशन नई दिल्ली, एनडब्ल्यूडीए के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार की है। इसमें उप्र और मप्र जल संसाधन विभागों के इनपुट लिए हैं। परियोजना को अगले 100 साल के लिए डिजाइन किया है। 13 साल की देरी से प्रोजेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केन नदी में एक मानसून सीजन में 6590 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी आता है, जबकि ढोड़न बांध की अधिकतम क्षमता 2853 एमसीएम है। यह नदी में आने वाले कुल पानी से आधे से भी कम है। बनने के बाद यह बांध मानसूनी बारिश की शुरुआत में ही फुल हो जाएगा। इसमें से 750 एमसीएम पानी उप्र को दिया जाएगा। केन नदी की कुल लंबाई 427 किमी है, जबकि कैचमेंट एरिया 28 हजार 500 वर्ग किमी है। कैचमेंट एरिया का 87 फीसदी हिस्सा मप्र में है। यह कटनी, सतना, दमोह, सागर, पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला है। इसे छोटी नदी कहना गलत है। यह पानीदार बड़ी नदी है। 221 किमी लंबी नहर कांक्रीट की होगी, जिसमें पानी आसानी से बहेगा। ढोड़न बांध से पन्ना टाइगर रिजर्व अगले 100 साल तक के लिए सुरक्षित हो जाएगा।

● **सिद्धार्थ पांडे**

विदिशा, शिवपुरी और बीना में बनेगा बांध

विदिशा की कोठा बैराज बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज का हिस्सा है। इसके तहत बेतवा पर बांध कोठा बैराज बांध का निर्माण होगा। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में उर नदी सिंचाई परियोजना को भी शामिल किया है। इन गांवों में शिवपुरी जिले के साथ ही सीमा से सटे दतिया जिले के गांवों को भी पानी मिलेगा। बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय वृहद परियोजना पर मप्र सरकार 70 के दशक से सर्वे कर रही है। लंबे समय से अधर में अटकी परियोजना को केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से फंड आवंटित किया है।

अबूझ नासूर कोरोना

पहले कोविड-19, फिर डेल्टा, अब ओमिक्रॉन, डेल्टाक्रॉन का खतरा

भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है कोई भी देश

कोविड-19 महामारी ऐसा नासूर बन गई है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। पहली और दूसरी लहर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद अब तीसरी लहर का दौर शुरू हो गया है। तीसरी लहर में अभी ओमिक्रॉन वैरिएंट फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही डेल्टाक्रॉन वैरिएंट भी उपज रहा है। इसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह दूसरी लहर से भी अधिक लोगों की जान ले सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस महामारी से निपटने के लिए किसी देश के पास पूरी तैयारी नहीं है। इसलिए पूरी फरवरी तक सजग रहने की जरूरत है।

● राजेंद्र आगाल

कोरोना (कोविड-19) महामारी ऐसी अबूझ पहेली बन गई है जिसके आगे बड़े-बड़े देश, बड़े-बड़े वैज्ञानिक, बड़े-बड़े डॉक्टर, बड़े-बड़े शोधार्थी नतमस्तक हैं। कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका खात्मा कैसे होगा इसके बारे में कोई ठोस तथ्य नहीं है। यही कारण है कि पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर शुरू हो गई है। तीसरी लहर में ओमिक्रॉन और डेल्टाक्रॉन दो ऐसे वायरस सक्रिय हैं जिन्हें कोई बेहद खतरनाक तो कोई कोरोना वायरस के खात्मे का रूप मान रहा है। देखते ही देखते ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका जैसे विकसित देश में ओमिक्रॉन के रोजाना 10 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। महज दो महीने पहले दक्षिण अफ्रीका में जिस वैरिएंट का पता चला था, उसने होश उड़ा देने वाली रफ्तार से पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लिया है। यह तब हुआ है जब यात्रा पर पाबंदियों से लेकर टीकाकरण और कर्फ्यू लगाने जैसे सारे प्रयास किए गए।

मप्र की स्वास्थ्य सेहत सुधारने केंद्र से मिले 922.79 करोड़

कोरोनाकाल के बाद से सरकार का फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किए जाने पर अधिक है। प्रयास यही है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त पलंग हो, दवाओं की कमी न रहे, जरूरत के मुताबिक अमला भी उपलब्ध रहे। इस दिशा में काम हो रहा है, वहीं केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्यों को स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 8453.92 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसमें मप्र को 922.79 करोड़ का अनुदान शामिल है। यह देश के सर्वाधिक तीन राज्यों में से एक है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की सिफारिश की थी। इसी आधार पर केंद्र ने यह राशि जारी की है। सूत्रों के मुताबिक यह रकम ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। इन अनुदानों का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों की खामियों को दूर करना तथा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इससे प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक उपचार सुविधा भी शामिल है। संसाधन बेहतर होंगे तो निकाय फैलने वाली महामारियों से बेहतर ढंग से निपट सकेंगे।

यह दिखाता है कि कोविड-19 के जनक कोरोना जितना फुर्तीला और खतरनाक वायरस मानवता के समक्ष इससे पहले कभी नहीं आया था। साल 2022 में कोरोना महामारी अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है और इसके ग्राफ में गिरावट का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। इसका कहर दुनिया के 200 देशों में अब भी जारी है और अब तक 55 लाख से अधिक मौतें (15 जनवरी 2022 तक) हो चुकी हैं। इस महामारी का प्रभाव ऐसा है कि कई देशों में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आ गई है। नेचर जर्नल में छपे बार्सिलोना की पब्लिक यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रिसर्च इन हेल्थ इकोनॉमी के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के मुताबिक, 81 देशों में कोविड-19 के चलते 2 करोड़ 5 लाख वर्ष का जीवन बर्बाद हो गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज के एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में जीवन प्रत्याशा में दो साल की गिरावट आई है।

...और अब ओमिक्रॉन

24 नवंबर 2021 को ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक हुई, जो कोविड-19 के दो सालों में आए सभी पांच वैरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक और ज्यादा नया रूप धारण करने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महानिदेशक टेड्रोस ए गेब्रेयेसस ने चेतावनी देते हुए कहा कि नए वैरिएंट से बीमारी की गंभीरता भले ही कम हो, लेकिन मामलों में तेजी आने से स्वास्थ्य तंत्र फिर से चरमरा सकता है। वह कहते हैं, बहुत से देशों में यह वायरस प्रवेश कर चुका है। अब हम यह जान चुके हैं और अपने जोखिम पर इसे नजरअंदाज करते हैं। 100 देशों में इस नए वैरिएंट की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। दिसंबर 2021 के मध्य के बाद ये महामारी परेशानी करने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। जिसके चलते 100 देशों ने उत्सव से संबंधित जुटानों को वर्जित करते हुए लॉकडाउन और शटडाउन जैसे उपायों की घोषणा की। विज्ञानी समाज इस नए वैरिएंट के व्यवहार को समझने के लिए माथापच्ची कर ही रहे थे कि इसके संक्रमण और लक्षणों ने उन्हें भ्रमित कर दिया। यह वैरिएंट न केवल टीके की सभी डोज ले चुके लोगों को संक्रमित कर रहा है, बल्कि संक्रमण के बाद जो प्राकृतिक इम्युनिटी विकसित हुई थी, उसे भी भेद रहा है। एक महीने तक तो इस वैरिएंट का कोई लक्षण नहीं दिखा जिससे संक्रमण की आशंका बढ़ गई। यह साल 2019 के दिसंबर में आए पहले कोविड-19 वायरस से मिलता-जुलता है।

जैसा सवाल उस वक्त उभरा था, वैसा ही सवाल फिर उभरा है कि क्या हम भविष्य को लेकर पर्याप्त तैयार हैं? अभी जो महामारी चल रही है, वैसी महामारी को सदी में एक बार या जीवन में एक बार की संज्ञा दी जाती थी। महामारी के खतरों पर काम करने वाली अमेरिका की एक संस्था मेटाबायोटा कहती है, मौजूदा महामारी जैसी जूनोटिक चरित्र की महामारी के अगले एक दशक में आने की 22-28 प्रतिशत तक आशंका है। दिसंबर के पहले हफ्ते में न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉप्किंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी की तरफ से जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी (जीएचएस) इंडेक्स 2021 रिपोर्ट बताती है कि हर आय वर्ग के देश, भविष्य की महामारी व उनके खतरों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। दुनियाभर के ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के प्रदर्शन का स्कोर साल 2021 में घटकर 100 में से 38.9 पर आ गया है। साल 2019 में यह स्कोर 40.2 था।

तेजी से फैल रहा संक्रमण

आज जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले अपने चरम पर हैं, वहां इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि एक बड़ी आबादी बेहद कम समय में संक्रमण की चपेट में आ रही है। संक्रमितों को एक से दो हफ्ते तक क्वारैंटाइन में रहना पड़ता है। इसका अर्थ है कि कामकाजी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अचानक बीमार और अनुपलब्ध हो जाता है। इसका मतलब यह भी है कि ओमिक्रॉन में उछाल से अचानक हमें दो से तीन हफ्ते तक डॉक्टरों, नर्सों, एंबुलेंस ड्राइवरों, पुलिसकर्मियों, ट्रक ड्राइवरों, स्टोर प्रबंधकों, फैक्ट्री मजदूरों और सफाईकर्मियों की संख्या में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे भोजन और दवाई जैसी अनिवार्य वस्तुओं के साथ ही स्वास्थ्य सुविधा जैसी अनिवार्य सेवाओं को निरंतर रूप से बनाए रखने पर जबरदस्त दबाव पड़ेगा। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में यह चुनौती और विकराल हो सकती है। यह अवधि ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन इससे निपटने की तैयारी नहीं की गई तो लोगों के लिए यह कष्टदायी हो सकती है। स्पष्ट है कि अगर हम अभी से इससे युद्धस्तर पर निपटने के लिए जुट जाएं तो उसके कहर से बचा जा सकता है।

सबसे पहले तो हमें जमाखोरी पर लगाम लगानी पड़ेगी। हमने देखा है कि पिछली बार दहशत में आए लोगों के साथ ही कालाबाजारी करने वाले अपराधियों ने आवश्यक वस्तुओं की कैसे जमाखोरी कर ली थी। प्रत्येक जिले से तुरंत यह कहा जाना चाहिए कि वे जमाखोरी रोकने के लिए अपनी-अपनी आपातकालीन योजना तैयार

कर लें और संक्रमण के चरम पर जाने से पहले ही अपने भंडार में आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्र में जुटा लें। इसके लिए प्राथमिकता वाले खाद्य पदार्थों, चिकित्सा के साधनों और ऐसी सेवाओं की पहचान करनी होगी जिन्हें पहुंचाने के बंदोबस्त तत्काल किए जा सकें। जिलास्तर की इन योजनाओं को कलेक्टरों के जिम्मे सौंप देना चाहिए और अगले एक महीने तक उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इन्हें लागू कराने की होनी चाहिए। राज्य स्तर पर अतिरिक्त संसाधनों और कर्मचारियों को उन जिलों के लिए तैयार रखना चाहिए, जहां हालात सबसे खराब हों। इस सबके अलावा छोटे शहरों में हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना होगा। ओमिक्रॉन कम घातक हो सकता है, लेकिन अस्पतालों पर यह जबरदस्त दबाव डालने वाला है। विशेष रूप से जब पहले से ही गंभीर रोगों से ग्रस्त लोग और बुजुर्ग इसका शिकार बन जाएंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल उन्हें ही बेड मिले, जिन्हें उनकी जरूरत हो। साथ ही बेड दिए जाने के कुछ पैमाने तय किए जाएं। उसी मानदंड के आधार पर बेड आवंटित किए जाएं। उसमें कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए। छोटे शहरों में रह रहे लोगों को इलाज के लिए बेहद जरूरी साधन अपने शहर में ही मिल जाएं और इलाज के लिए उन्हें बड़े शहरों की ओर भागने की जरूरत न पड़े। इसके लिए हमें अभी ही छोटे शहरों के अस्पतालों के लिए मेडिकल सप्लाई और ऑक्सीजन की जरूरत का हिसाब-किताब लगा लेना चाहिए।

पाबंदियां जरूरी

ओमिक्रॉन के खिलाफ जीत का मंत्र यह है कि इसका चरम कम समय तक रहे। यानी हमें हरसंभव तरीके से इसे फैलने से रोकना होगा।

जारी रहेगी महंगाई और बेरोजगारी

कहते हैं कि कोई भी समस्या हो एक-दो दिन में नहीं आती है, बल्कि उसकी दस्तक महीनों पहले दिखाई देने लगती है। मौजूदा समय में महंगाई और बेरोजगारी आज की समस्या नहीं, बल्कि यह समस्या सदियों पुरानी है और इसका अंत आसान नहीं दिख रहा है। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि मौजूदा सरकार हो या पूर्व की सरकारें। दोनों ने सही मायने में इस मामले पर सार्थक प्रयास नहीं किए हैं कि कैसे इस समस्या से निजात मिल सके। देश में लगातार महंगाई की मार से गरीब और मध्यम वर्ग आहत है। जबकि सरकार इस कवायद में जुटी है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या से बचा जा सके। पहले से धीरे-धीरे कमजोर होती देश की अर्थव्यवस्था 2020-21 की तमाम कोरोना महामारी के चलते ध्वस्त पड़ी है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई विकसित देश भी महंगाई का दंश महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह वैश्विक महामारी का होना है। कोरोना महामारी से जैसे-तैसे अर्थव्यवस्थाए पटरी पर आई थीं। फिर अचानक ओमिक्रॉन जैसी बीमारी से बाजार भयभीत होने लगा है। वहीं सरकार की कुछ लचर सोच भी आशंकाओं को जन्म देती है, जिसके चलते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इसको तोड़ पाना मुश्किल होता है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के 5.2 फीसदी तक रहने की उम्मीद जताई है, जिसके कारण मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई 5.8 तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे हालात में महंगाई को काबू पाना मुश्किल हो सकता है। महंगाई अपनी गति से जारी रहेगी।

हमें फरवरी के अंत तक सभी परीक्षाओं को टालने की तैयारी कर लेनी चाहिए। रैलियों, समारोहों और भीड़भाड़ से भी बेहद सावधान रहने की जरूरत होगी। चौथी बात यह कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना होगा। महामारी जाते-जाते तेज रफ्तार के साथ ही कम घातक हो जाती है। ओमिक्रॉन के मामले में हम ऐसा ही देख रहे हैं। ऐसी पूरी संभावना है कि कोविड-19 का अंत बहुत करीब है, पर उससे पहले हमें इस लहर से जीतना होगा। इतिहास साक्षी है कि 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू ने पूरे विश्व को अपने शिकंजे में लेकर करीब 10 करोड़ लोगों को मार डाला था, तब उसकी भी तीन बड़ी लहरें आई थीं। उसकी तीसरी लहर इस ओमिक्रॉन जैसी ही थी। यह जानकर हमें थोड़ा सकारात्मक हो जाना चाहिए और इस तीसरे युद्ध को इस मिशन के साथ लड़ना चाहिए कि कोविड-19 का हम हमेशा के लिए सफाया कर देंगे।

पिछले साल डेल्टा वैरिएंट के कारण आई दूसरी लहर में हमने भारी तबाही झेली। हालांकि डेल्टा वैरिएंट बिना किसी चेतावनी के ही आया और उसने हम पर हमला बोल दिया था। इस तीसरी लहर ने चेतावनी दी है और हमें तैयारी का समय भी दिया है। इस मौके का इस्तेमाल करना और लोगों की तकलीफ को कम करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी कुछ और नहीं हो सकता। भारत समेत 100 से अधिक देशों तक फैल चुके कोरोना के नए वैरिएंट ओमक्रोन के चलते ब्रिटेन में विश्व की पहली मौत हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी पुष्टि की है। नए वैरिएंट की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए आज विश्व में जहां नाना तरह के उपाय खोजे जा रहे हैं, वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका असर बहुत ही कम होगा। आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि देश में तीसरी लहर का आना तय है। इसका प्रभाव दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक दिखने लगेगा। जनवरी के अंतिम और फरवरी के पहले सप्ताह की शुरुआत में ओमिक्रॉन चरम पर होगा। कैंसर होना भी अपने आप में एक तरह का म्यूटेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैंसर की वजह से हम बीमार होते हैं और वायरस म्यूटेशन अपने बचाव के लिए करता है।

रूप बदलने में माहिर

इंसान के शरीर में जब इम्युनिटी डेवलप होने लगती है, चाहे वह नेचरल से हो या वैक्सीन से बनने वाली इससे पार पाना वायरस के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खुद को बचाए

रखने के लिए कोरोना अपना रंगरूप बदलने लगता है। अब तक कोरोना में कई हजार म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे म्यूटेशन थे जो जल्द ही स्वत: खत्म हो गए। हां, डेल्टा, डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन जैसे कुछ मजबूत वैरिएंट्स लंबे समय के लिए रह जाते हैं और हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं। अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट में सबसे ज्यादा 25 म्यूटेशन हुए थे, लेकिन ओमिक्रॉन में 50 से भी ज्यादा म्यूटेशन हुए हैं। इनमें से 30 से ज्यादा म्यूटेशन तो सिर्फ इसके स्पाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ही हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से यह ज्यादा जल्दी इंफेक्शन फैलाता है। कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ओमिक्रॉन वैरिएंट कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से पांच गुना ज्यादा संक्रामक है। जिस तेजी से यह दक्षिण अफ्रीका से निकलकर दुनियाभर में फैला है, उससे यह तो स्पष्ट है कि यह बेहद संक्रामक है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वैरिएंट कितना घातक है। ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह जानना भी जरूरी है कि इस वैरिएंट के संक्रमितों में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एलएनजेपी के चिकित्सा निदेशक डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि दिल्ली में जिस शख्स में इसकी पुष्टि हुई है, उसके गले में सूजन, बुखार, शरीर में दर्द जैसे मामूली लक्षण दिख रहे हैं और अभी हालत कोई गंभीर नहीं है। वहीं, मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत डॉ. भवेश ठाकुर ने बताया है कि चूंकि उनके पास इसके मरीज अभी आए नहीं हैं, लेकिन इसकी संक्रामकता अधिक ही है। इसलिए यह तेजी से फैल रहा है। लेकिन, इसकी मारक क्षमता कितनी है और इस पर हमारी दोनों डोज का कितना असर होगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो जानकारी है, उसके अनुसार सरकार इसके रोकथाम के लिए पूरी तरह सक्षम है। सरकार के निर्देश भी अस्पतालों में आ चुके हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बचाव का सबसे सुरक्षित उपाय यही है कि आप मास्क पहनें और शारीरिक दूरी का पालन करें।

डेल्टा के खिलाफ बचाव

ओमिक्रॉन वैरिएंट डेल्टा के खिलाफ बचाव में मदद कर सकता है। यह बात एक अध्ययन में सामने आई है। यह अध्ययन दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्थित अफ्रीका स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने किया है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में किए गए इस नए अध्ययन के अनुसार जो लोग नए ओमिक्रॉन कोरोनावायरस के संक्रमण से उबर चुके हैं, वे डेल्टा वैरिएंट से बाद के संक्रमणों को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि इस अध्ययन के आगे के प्रयोग उक्त निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं तो भविष्य में इस महामारी से बचने के लिए एक संभावित विकल्प का मिलना संभव है। ध्यान रहे कि थोड़े समय के लिए ओमिक्रॉन मामलों में वृद्धि होने से दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य देखभाल की प्रणालियों पर भारी दबाव बन गया है। लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि भविष्य में ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता है तो भी अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या कम रह सकती है। यही नहीं यह डेल्टा वैरिएंट से होने वाली मौतों की संख्या को भी कम कर सकती है।

दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्थित अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले वायरोलॉजिस्ट एलेक्स सिगल ने कहा कि वास्तव में इस अध्ययन से पता चलता है कि ओमिक्रॉन भविष्य में डेल्टा के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। वह आगे कहते हैं कि डेल्टा को बाहर करना वास्तव में एक अच्छी बात है और हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसके साथ हम अधिक आसानी से रह सकते हैं और जो हमें पिछले वैरिएंट की तुलना में कम नुकसान पहुंचाएगा। विश्व के स्वतंत्र वैज्ञानिकों के समूह ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीकी प्रयोगशाला का यह प्रयोग अपनी प्रारंभिक निष्कर्ष में तो काफी सकारात्मक और अच्छा संकेत दे रहा है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के महामारी विज्ञानी कार्ल पियर्सन ने कहा कि यह निष्कर्ष तो इंग्लैंड में वर्तमान में जो घट रहा है उसी के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन आता है और तेजी से बढ़ता है लेकिन उसके इस प्रकार से आने के बाद यह पता चलता है कि डेल्टा की प्रवृत्ति में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है।

मप्र में डॉक्टर, आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड की कमी

देश में फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, कोरोना की तीसरी लहर जब दस्तक दे चुकी है। इस बीच राज्य सरकारों पर दायित्व है कि वो अपनी स्वास्थ्य व्यस्था दुरुस्त करें। लेकिन अभी भी देश के कई राज्य सरकारें इस पर ध्यान न देकर बयानबाजी में लगी हुई हैं। इसी तरह का आरोप वाम पंथी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) मप्र की सरकार पर लगा रही है। उसका कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए अस्पतालों और डॉक्टरों सहित उपचार की समूची व्यवस्था करने की बजाय बयानबाजी में ज्यादा समय बर्बाद कर रही है। माकपा के मप्र के राज्यसचिव जसविंदर सिंह ने उक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश भर में दूसरी लहर की तुलना में डॉक्टरों की संख्या में 38 प्रतिशत और आइसोलेशन बेड की संख्या में 43.5 प्रतिशत की कमी कर दी गई है। तो क्या नाइट कर्फ्यू, कोरोना गाइडलाइन जारी करने भर से प्रदेश के नागरिकों के जीवन की रक्षा की जा सकती है? माकपा नेता के अनुसार दूसरी लहर की तुलना में डॉक्टरों की संख्या 1132 से घट कर 705 हो गई है। जिससे 427 डॉक्टर कम हो गए हैं। इसी तरह आइसोलेशन बेड की संख्या 29,247 से घटकर 16,527 रह गई है। दूसरी लहर की तुलना में यह कमी 12,720 बेड की है। इसी प्रकार ऑक्सीजन बेड भी 28,152 से घटाकर 27,645 कर दिए गए हैं। जसविंदर सिंह के अनुसार यह कमी ही दर्शाती है कि प्रदेश की भाजपा सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने की बजाय नागरिकों की जान जोखिम में डालने की तैयारी कर रही है।

फिर पलायन शुरू

अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि ओमिक्रॉन आर्थिक बहाली को ठप नहीं करेगा। लेकिन संक्रमण के मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगे हैं कि एक बार फिर से श्रमिकों ने पलायन शुरू कर दिया है। दरअसल, उनके अंदर कोरोना की पहली लहर का डर समाया हुआ है। आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए भारत के टीकाकरण अभियान को तेज गति देना जरूरी है। हमने जितने भी उद्योगपतियों से बात की, तकरीबन हरेक ने टीके लगाने की रफ्तार फिर तेज करने की जरूरत बताई। रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने एक रिपोर्ट में कहा कि दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों में बहाली की राह कहीं ज्यादा कमजोर है और इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत सहित इन अर्थव्यवस्थाओं में टीके लगाने की रफ्तार सुस्त रही है। मॉर्गन स्टेनली ने भी कहा कि भारत को फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार करना पड़ सकता है, जो नए वैरिएंट के फैलाव पर निर्भर करेगा और इसका आर्थिक वृद्धि पर गंभीर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के बाधित होने को लेकर आगाह किया गया। यह कहती है, मसलन, डेल्टा लहर के दौरान भारत और आसियान समूह के देशों की उत्पादन गतिविधियों पर उत्तर एशिया से कहीं ज्यादा असर पड़ा। हम यही दोबारा होते देख सकते हैं।

फिलहाल तो किसी भी स्वास्थ्य मानदंड से कहीं ज्यादा ये यात्रा प्रतिबंध ही हैं जो चिंता बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्रीय कामगारों और छात्रों के लिए अपनी सीमाएं फिर खोलने की योजना 29 नवंबर को एकाएक रोक दी। जापान, सिंगापुर और इजराइल सहित कई देशों ने विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी या ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगा दीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नया वैरिएंट अब तक कम से कम 100 देशों में मिला है। इनमें ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। ज्यों-ज्यों ज्यादा देश इसकी जद में आते जाएंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था और खासकर यात्रा क्षेत्र पर ओमिक्रॉन का प्रभाव बढ़ता जाएगा।

ओमिक्रॉन लहर में इलाज

भारत इस समय कोरोना वायरस के नए और तीव्र संक्रामक वैरिएंट ओमिक्रॉन से उपजी लहर का सामना कर रहा है। इसे ध्यान में रखकर मेडिकल विशेषज्ञों ने पुरानी गलतियों को न दोहराने, खासकर इलाज से जुड़ी बातों को लेकर चेतावनी दी है। कोरोना की पहली दो लहरों में इसके मरीजों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, स्वास्थ्य-लाभ से जुड़ी प्लाज्मा थेरेपी, आइवरमेक्टिन, फेविपिरवीर, डॉक्सीसाइक्लिन और एंटीबायोटिक्स का देश में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया था। उस समय इन सभी की प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी उठाए गए थे, हालांकि अब यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों के इलाज में इनमें से किसी की कोई भूमिका नहीं थी। स्वास्थ्य-विश्लेषक और महामारी-विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि कोरोना की पहली दो लहरों में लोगों की जान बचाने के लिए प्रयोग के तौर पर किसी खास थेरेपी का इस्तेमाल करना सही था। जबकि अब हमें कोविड-19 के इलाज के बारे में पहले से कहीं बेहतर जानकारी है। पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य-लाभ से जुड़ी प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग के खिलाफ सिफारिश की। उसने कहा कि इसके नतीजे काफी अनिश्चित हैं और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को लाना-ले जाना भी आसान नहीं है। उसने कहा कि अपने शुरुआती दावों से इतर, हाल की घटनाएं दर्शाती हैं कि यह थेरेपी न तो कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाती है और न ही मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत को कम करती है। साथ ही यह महंगी और समय लेने वाली थैरेपी भी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021 की शुरुआत में ही इस थेरेपी से इलाज बंद कर दिया था। लहरिया के मुताबिक, कोविड-19 के मरीजों का ज्यादातर इलाज, खासकर इसकी दूसरी लहर के दौरान, मरीजों की मांग के अनुकूल था। इसी के चलते प्लाज्मा थेरेपी, आइवरमेक्टिन और ऐसी ही अन्य विधियों से इलाज किया गया। हालांकि हमारा तरीका मरीजों की मांग के अनुकूल होने की बजाय रोग-विषयक निदान के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। तभी इस महामारी से निजात पाई जा सकती है। अब देखना यह है कि कोरोना की तीसरी लहर के बाद दुनिया आने वाले अन्य महामारियों से लड़ने के लिए क्या उपाय करती है।

मप्र में स्कूल बंद, प्री-बोर्ड की परीक्षा घर से ही देनी होगी

अन्य प्रदेशों की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र के सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 20 जनवरी से होने वाले प्री-बोर्ड एग्जाम घर से देने होंगे। सभी तरह के मेले, रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल रहे थे। बैठक में जो सुझाव आए हैं, उनके अनुसार जरूरी हो गया है कि 31 जनवरी तक सभी निजी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। आगे भी परिस्थितियों पर नजर रहेगी। इसके बाद पाबंदियों को लेकर निर्णय किया जाएगा। 15 जनवरी से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण के लिए शत-प्रतिशत लोगों को कवर करें। कार्य के लिए बाहर जाने वाले लोगों की संख्या की पुष्टि करें। माइग्रेटेड लोगों की सूची बनाएं। टीकाकरण सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसकी ग्राम स्तर तक समीक्षा हो। सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान से जुडें। सभी के प्रयत्नों और सामूहिक सहयोग से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घर-घर दस्तक दें, टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो। वैक्सीन ही कोविड से सुरक्षा का मजबूत कवच है। इसे अधिक से अधिक लोगों को कम समय में लगाना जरूरी है।

अब हिंसा परमो धर्मः!

सरकारी हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं

संस्थागत धर्म विशाल मठ-मंदिरों और बड़ी-बड़ी धार्मिक संस्थाओं के जरिए संचालित होता है। अपने विशाल धार्मिक साम्राज्य के विस्तार एवं रक्षा के लिए धर्म गुरुओं को कदम-कदम पर सरकार के सहयोग की आवश्यकता होती है। इन धार्मिक संगठनों का भौतिक ऐश्वर्य और संपत्ति के प्रति आकर्षण इतना प्रबल होता है कि धीरे-धीरे इनकी और किसी पूंजीपति की मालकियत वाले व्यावसायिक समूह की कार्यप्रणाली में अंतर करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि हम हिंदू धर्म की वैसी व्याख्याएं होती देखते हैं जैसी सरकार को पसंद हैं। हिंदू धर्म की मूल प्रवृत्ति न तो विस्तार की है न ही राज्य संचालन में हस्तक्षेप करने की। जिन धर्मों की आलोचना में कट्टर हिंदुत्व के समर्थक दिन-रात एक कर रहे हैं। दरअसल वे उन्हीं धर्मों के कतिपय त्याज्य दोषों का समावेश हिंदू धर्म में करने को लालायित हैं। पता नहीं हिंदू धर्म में ऐसे कितने धर्म गुरु हैं जिनमें इतना नैतिक बल शेष है कि वे देश को बता सकें कि सरकारी हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है। आज आवश्यकता असमावेशी और कट्टर हिंदुत्व के उभार के कारणों का विश्लेषण करने की है। हमें यह तय करना होगा कि हमारे बहुलताओं से परिपूर्ण देश को इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है? क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी परिपक्व है कि हम इन असंवैधानिक गतिविधियों का सामना कर सकें?

धर्म संसद के नाम पर समाज में हिंसा का जहर घोलने की सुनियोजित कोशिशें धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी हैं। हिंसा को स्वीकार्य बनाकर महिमामंडित करने का एक नवीनतम प्रयोग शांति के द्वीप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कथित धर्म संसद के जरिए प्रारंभ हुआ है।

सत्याग्रही गांधी और उनकी अहिंसा तथा सेकुलरवाद की रक्षा को समर्पित नेहरू एवं उनकी वैज्ञानिकता लंबे समय से हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे हैं। हमारे संघात्मक ढांचे को सशक्त बनाकर हमारी बहुलताओं को सम्मान, स्वीकृति एवं संरक्षण देने वाले संविधान की आलोचना एवं इसके सेकुलर-समावेशी चरित्र को बदलने की कोशिश इन फासिस्ट शक्तियों द्वारा की जाती रही है। हिंसक हिंदुत्व के हिमायती जानते हैं कि गांधी, नेहरू और संविधान को अलोकप्रिय बनाकर इन्हें अप्रासंगिक सिद्ध किए बिना हिंसाप्रिय साम्प्रदायिक समाज बनाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता।

रायपुर में हुई धर्म संसद में साधु का बहुरूप धारण किए हुए एक व्यक्ति ने गांधी के विषय में जहरीली और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और शायद उसे कानून दंडित भी करे। किंतु इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में उसे नायक सिद्ध करने के लिए चलाया जा रहा अभियान और रायपुर में हिंदूवादी संगठनों की बढ़ती सक्रियता एवं उनके आक्रामक तेवर यह संकेत दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों का साम्प्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के प्रयास अब परवान चढ़ने वाले हैं। वैसे भी साम्प्रदायिक हिंसा का प्रवेश कुछ दिनों पूर्व ही छत्तीसगढ़ की शांत फिजाओं में हो चुका है।

यह सारा घटनाक्रम अनेक जटिल एवं विचारणीय प्रश्नों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। क्या आने वाले समय में हिंसक तथा असमावेशी **हिंदुत्व की हिमायत** करने वाली फासीवादी ताकतें अपना ध्यान उन प्रदेशों पर केंद्रित करने वाली हैं जो अभी तक साम्प्रदायिकता के जहर से अछूते रहे हैं? क्या साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाकर सत्ता हासिल करने की रणनीति की कामयाबी ने इन ताकतों को यह हौसला दिया है कि वे इसके देशव्यापी क्रियान्वयन के लिए आक्रामक अभियान चलाएं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन प्रदेशों में धार्मिक-साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की रणनीति ने भाजपा को सत्ता दिलाई थी, उन प्रदेशों की जनता अब इसे नकारने लगी है और इसी कारण कट्टरपंथी नए प्रदेशों की ओर रुख कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार और अन्य भाजपा शासित राज्यों द्वारा हिंदू वर्चस्व एवं हिंदू साम्प्रदायिकता के समर्थकों को दिए जाने वाले स्पष्ट संरक्षण में यह संकेत निहित है कि हिंदुत्ववादी एजेंडे को क्रियान्वित करने का यह सर्वोत्तम समय है और इस कार्य को युद्धस्तर पर किया जाए?

छत्तीसगढ़ सरकार ने कालीचरण की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर वही किया जो एक सेकुलर और संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करने वाली सरकार को करना चाहिए था। किंतु कालीचरण को प्रखर एवं निर्भीक हिंदू नेता के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास और उसकी गिरफ्तारी का उग्र विरोध करने की रणनीति यह दर्शाती है कि अराजक शक्तियां इसे भी अपने प्रचार के एक अवसर के रूप में भुनाने का मन बना चुकी हैं।

जहरीले, विवादित, साम्प्रदायिक वैमनस्य और हिंसा फैलाने वाले बयान देकर स्वयं को और अपने घातक एजेंडे को भी चर्चा में बनाए रखने वाले नेताओं-धर्मगुरुओं-पत्रकारों की एक पूरी फौज इन हिंदू संगठनों के पास है। केंद्र सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों की सरकारों द्वारा इन्हें अभयदान प्राप्त है। क्या सेकुलरवाद पर विश्वास करने वाली गैर भाजपाई सरकारों पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वे इस तरह के तत्वों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करें?

रायपुर में आयोजित कथित धर्म संसद में कुछ कांग्रेस विधायक भी उपस्थित थे। निश्चित ही उन्हें यह मालूम रहा होगा कि इस आयोजन का उद्देश्य महज धार्मिक चर्चा नहीं है बल्कि इस जमावड़े की असल मंशा हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए रणनीति बनाना है। इसके बावजूद भी इन्हें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना पड़ा।

● कुमार विनोद

अबकी बार जनता की अग्निपरीक्षा

पांच राज्यों के चुनाव घोषित होते ही मीडिया महोत्सव शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि ये चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल हैं और भाजपा-कांग्रेस समेत उन सभी राजनीतिक दलों (जो मैदान में हैं) की अग्निपरीक्षा इन चुनावों में होगी। लेकिन वास्तविकता है कि ये चुनाव राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि आम जनता या मतदाताओं की अग्निपरीक्षा साबित होने जा रहे हैं। क्योंकि इन चुनावों के नतीजे ही मतदाताओं के मानस का पैमाना होंगे।

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेंगे। यानी 10 मार्च को जनता का फैसला आएगा। उप्र में जहां 7 चरणों में तो उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 1-1, तथा मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें 4 राज्य उप्र, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की सरकारें हैं जबकि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। यानी भाजपा को अपने 4 राज्य बचाने और साथ ही पंजाब में जहां वह पहली बार बिना अकाली दल की बैसाखी के उतर रही है, में अपने बलबूते कमल खिलाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के सामने पंजाब में अपनी सरकार बचाने और उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में सरकार बनाने और उप्र में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चमत्कारिक प्रदर्शन करने का लक्ष्य है। वहीं उप्र में सपा अपने सहयोगी दलों के साथ भाजपा गठबंधन को रोकने और अपनी सरकार बनाने के मंसूबे के साथ मैदान में है तो बसपा की कोशिश कम से कम इतने विधायक जिताकर लाने की है कि बिना उसके कोई सरकार न बन सके। आम आदमी पार्टी पंजाब में इस बार सरकार बनाने से न चूकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और उत्तराखंड, गोवा व उप्र में भी चुनाव मैदान में है।

इन विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह फिर भाजपा के सेनापति होंगे जिनकी लोकप्रिय छवि को पार्टी हर चुनावी राज्य में भुनाने की कोशिश करेगी। मोदी के साथ उनके सिपहसालार के रूप में उप्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उधर कांग्रेस में पंजाब में जहां जीत का दारोमदार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ आदि नेताओं पर है तो उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी के तारणहार हैं। आम आदमी पार्टी को पंजाब, उत्तराखंड, उप्र और गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा है। सपा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अकेले ही मोदी-योगी की सेना को मजबूत टक्कर दे रहे हैं। जबकि बसपा प्रमुख मायावती को प्रचार से ज्यादा अपने जनाधार की निष्ठा पर भरोसा है। हालांकि पार्टी महासचिव सतीश मिश्रा 2007 की तरह ब्राह्मण को जोड़ने के लिए लगभग पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर सभाएं कर चुके हैं।

इसके साथ ही भाजपा उप्र में सपा के राज को अपराधियों का राज घोषित करते हुए जनता को आगाह करने में जुटी है कि अगर सपा जीती तो फिर उन माफियाओं का राज लौट आएगा जिन्हें योगी सरकार ने या तो जेल में भेज दिया है या फिर पुलिस मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी भाजपा नेता इस मुद्दे को जोरशोर से **अपनी सभाओं में** उठा रहे हैं। जब वो माफिया कहते हैं तो उनका इशारा आमतौर पर अतीक अहमद

स्वामी सहित 14 विधायक बदल चुके हैं पाला

उप्र में जिस तरह भाजपा सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 14 विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, उससे यह अनुमान लगाया जाने लगा है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का मौसम आ गया है। दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं। खुद उन्होंने सपा का दामन थामते हुए यह कहा कि मैं जिस पार्टी में रहता हूं, उसकी सरकार बनती है। अगली बार सपा की सरकार बनेगी। उधर, विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद से भाजपा में असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। इस बीच भाजपा ने 15 जनवरी को 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जिसके अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से तो उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने 21 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। उनकी जगह नए चेहरों को टिकट दिया गया है।

और मुख्तार अंसारी जैसों की तरफ होता है जिससे दो निशाने सधते है, एक तो अपराधीकरण के खिलाफ भाजपा का नारा बुलंद होता है तो साथ ही मुस्लिम विरोधी ध्रुवीकरण में मदद मिलती है। जबकि कई अपराधी और माफिया चरित्र वाले लोग सत्ता के गलियारों और भाजपा नेताओं के मंच पर भी देखे जाते हैं। विपक्ष भी इसे अपने तरीके से मुद्दा बना रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राकेश मिश्रा टेनी का लिया जा रहा है, जिनके इस्तीफे की मांग लगातार किसान संगठन और विपक्षी दल करते रहे हैं।

इन चुनावों में उप्र में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उस सामाजिक समीकरण को साधे रखने की है जिसकी वजह से उसे उप्र में 2014, 2017 और 2019 के चुनावों में लगातार भारी जीत मिली है। इन चुनावों में जहां सवर्ण हिंदू पूरी तरह एक मुश्त उसके साथ रहे वहीं गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलितों का बड़ा समर्थन भाजपा को मिला और एक तरह से आरएसएस की हिंदुत्व की अवधारणा जातीय गोलबंदी पर भारी पड़ी। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनाव लड़ने के बावजूद उनकी जगह एकाएक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने, जातीय जनगणना के मुद्दे पर भाजपा की हीला हवाली, और शासन-प्रशासन में सवर्णों के वर्चस्व ने पिछड़ों को नाराज किया है। जबकि पश्चिमी उप्र में पिछले तीन चुनावों में भाजपा के लिए मजबूती से डटे रहने वाले जाट और अन्य किसान जातियों को किसान आंदोलन ने नाराज कर दिया और तीनों कृषि कानून वापस लेने के बावजूद अभी उनकी नाराजगी कितनी दूर हुई यह कहना मुश्किल है।

अखिलेश यादव ने इस सामाजिक असंतोष को भांपकर अपने चुनाव अभियान को पिछड़ों के इंकलाब का नाम दिया है और उन्होंने गैर यादव पिछड़ों के सपा के साथ पहले की तरह गोलबंद करने के लिए ओम प्रकाश राजभर की सभासपा, संजय चौहान की पार्टी, केशवदेव मौर्य के महान दल, जयंत चौधरी के राष्ट्रीय

लोकदल, अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल, कांग्रेस से सपा में शामिल हुए पाल समाज के नेता राजाराम पाल, जाटों के नेता हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक, सुखदेव राजभर के बेटे रामअचल राजभर, लालजी वर्मा समेत कई पिछड़े और किसान जातियों के नेताओं को साथ लेकर सपा के जनाधार का विस्तार करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के भी सपा के साथ गठबंधन की चर्चा है।

अखिलेश यादव की नजर भाजपा के साथ गए निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद और योगी सरकार के कुछ मंत्रियों पर भी है। अखिलेश की कोशिश भाजपा के हिंदुत्व की काट में मंडल के जमाने का पिछड़ा गठबंधन करके चुनाव की बाजी पलटने की है। इसके अलावा इस चुनाव में ब्राह्मण **समुदाय जिसकी तादाद** राज्य में करीब 12 फीसदी है जो सर्वाधिक मुखर मतदाता समूह है, उसे अपने साथ लेने की होड़ सभी दलों में हैं। भाजपा उसे अपना परंपरागत जनाधार मानती है और कांग्रेस के कमजोर होने के बाद भाजपा ही ब्राह्मणों की स्वाभाविक पसंद और अपनी पार्टी रही है। इस बार अनेक कारणों से राज्य में यह धारणा बन गई है कि ब्राह्मण उपेक्षित हैं और इसीलिए सपा जहां परशुराम मंदिर का उद्‌घाटन करके ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश में है तो बसपा ने सतीश मिश्र को आगे करके प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए ये कोशिश की है। साथ ही बसपा विकास दुबे कांड में जेल में बंद खुशी दुबे का मुद्दा भी उठा रही है और सतीश मिश्र खुद इसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

भाजपा इसे भांप चुकी है। इसलिए भाजपा ने एक बार फिर हिंदू ध्रुवीकरण के दांव को तेज किया है। एक तरफ उसने अपने ब्राह्मण नेताओं के जरिए इस वर्ग को साधने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को भाजपा ने अपने साथ लेकर उन्हें राज्य में मंत्री बना दिया। तमाम विरोध के बावजूद लखमीपुर खीरी कांड में विवादित गृह राज्य मंत्री राकेश मिश्र टेनी को नहीं हटाया गया है। साथ ही अपने विकास कार्यों से ज्यादा भाजपा नेता अखिलेश और सपा को यादव-मुसलमानों की पार्टी साबित करने में जुटे हैं ताकि मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा सके। इसके लिए एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा के श्रीकृष्ण मंदिर के विकास का नारा दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जिन्ना से लेकर गाय तक को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भाषणों में जगह मिल रही है।

● **रजनीकांत पारे**

उत्तराखंड और पंजाब में कांग्रेस की परीक्षा

उत्तराखंड में कांग्रेस ने भाजपा द्वारा 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे को जनादेश का अपमान और सरकार की अक्षमता के रूप में पेश करना शुरु कर दिया है। हालांकि तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हरीश रावत को भी कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी झेलनी पड़ी और उन्होंने जब तीखे तेवर दिखाए तो हाईकमान ने उन्हें पूरे अधिकार दे दिए। रावत ने अपने चुनाव अभियान को उत्तराखंडियत के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया है। वहीं पंजाब में इस बार चुनाव दो ध्रुवीय न होकर बहु ध्रुवीय हो गया है। कांग्रेस और अकाली बसपा गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी, भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन, किसान आंदोलन के बाद किसान नेता बलबीर सिंह राजोवाल की पार्टी और गुरुनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी भी मैदान में उतर रही है। एक समय लगता था कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस फिर बाजी मारेगी। लेकिन जब कैप्टन-सिद्धू झगड़े के बाद कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो लगा कि कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भाजपा ने इसमें अपने लिए अवसर देखा क्योंकि अकाली दल पहले ही उससे अलग हो चुका था। भाजपा ने फौरन अमरिंदर से दोस्ती की और चुनावी तालमेल कर लिया।

मोदी के सामने कई चैलेंजर

2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं से भी चैलेंज मिलने की संभावना है। यानी 2024 में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दावेदार मानी जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी ही सबसे बड़े चैलेंजर लगते हैं। अगला आम चुनाव 2024 में होना है। तब तक मोदी को चुनौती देने के लिए चैलेंज करने वाले का टिका रहना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, ये सब काफी हद तक इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों में ही साफ हो जाएगा। मतलब ये कि इस साल होने वाले 7 विधानसभा के चुनाव नतीजों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। साल की शुरुआत में उप्र और पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होंगे। ऐसे में 2022 की राजनीति 2024 के आम चुनाव के लिए नींव के पत्थर की भूमिका में भी हो सकती है, यानी एक किरदार तो योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं।

बेरोजगारी और महंगाई से होते हुए कोरोना से लेकर चीन और किसानों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी काफी दिनों से मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देखा जाए तो ममता बनर्जी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। मुद्दों के हिसाब से देखें तो **किसान आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती** है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने फैसले से पीछे हटना तो यही बता रहा है। 2020 में सीएए और एनआरसी भी चुनौती बने थे, लेकिन कृषि कानूनों पर तो पीछे ही हटना पड़ा। पंजाब चुनाव और पश्चिम उप्र में भाजपा के लिए ये कितना फर्क डालने वाला है देखना होगा। अब तो ऐसा भी लगने लगा है कि अकाली दल के एनडीए छोड़ देने के बाद भाजपा पंजाब में बेहतर नतीजे ला सकती है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद पूछी गई तो आगे भी वे भाजपा नेताओं के पक्ष में ही खड़े नजर आए। मोदी के बाद अगर भाजपा से ही किसी और नेता को प्रधानमंत्री बनाना हो तो कौन हो सकता है? जवाब देने वालों में 30 फीसदी लोग अमित शाह के पक्ष में दिखे, जबकि 21 फीसदी लोग योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि, देश में प्रधानमंत्री पद की पसंद के मामले में मोदी के बाद सर्वे में शामिल लोगों की जुबान पर योगी आदित्यनाथ का ही नाम सुना गया।

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने पर गुजरात में अमित शाह तो उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदी बेन पटेल का नाम मंजूर किया। आनंदी बेन पटेल फिलहाल चुनावी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उप्र की राज्यपाल हैं। हो सकता है, मोदी ने तभी शाह को लेकर बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां तय कर रखी हों और दिल्ली में उनकी ज्यादा जरूरत महसूस की हो, इसलिए उनको अहमदाबाद तक ही सीमित नहीं रखा। हो सकता है, अमित शाह के जेल से रिहा होने के बाद भी गुजरात लौटने पर हाईकोर्ट की पाबंदी जैसी बातों की वजह से भी मोदी को अलग फैसला लेना पड़ा हो। बहरहाल, अब तो ये साबित भी हो चुका है कि शाह को दिल्ली साथ लाने का मोदी का फैसला सर्वोत्तम रहा।

उधर कई मामलों में मोदी के खिलाफ जाकर और उनकी अवहेलना करके उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भविष्य में उनके इरादे कैसे हो सकते हैं। योगी के उप्र के मुख्यमंत्री बनने में भी ऐसे ही पैंतरे महसूस किए गए। 2017 में उप्र के मुख्यमंत्री को लेकर कई नाम आए और सबसे दमदार नाम राजनाथ सिंह का लगा। जब राजनाथ सिंह ने इंकार कर दिया तो मनोज सिन्हा पर सहमति बन गई, लेकिन ऐन वक्त पर योगी आदित्यनाथ प्रकट हो

भाजपा में नंबर दो की लड़ाई

2019 में जब मोदी सरकार दोबारा बनी तो नंबर दो की लड़ाई नजर आने लगी थी। माना जाने लगा कि अमित शाह और राजनाथ सिंह में नंबर दो की होड़ लग गई थी। तभी राजनाथ की नाराजगी की भी खबरें आई थीं। हालांकि, बाद में मोदी ने सारी चीजें ऐसे मैनेज की कि अमित शाह भी बुरा न मानें और राजनाथ की वरिष्ठता पर भी आंच न आने पाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए अक्सर योगी का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन ध्यान रहे चेहरा भले ही मोदी के बाद योगी का लोकप्रियता में आगे हो, कमान पूरी तरह शाह के हाथों में ही है। तभी तो योगी आदित्यनाथ से पहले मोदी के लिए शाह ही चैलेंजर बन सकते हैं। शाह को आडवाणी की तरह ही टस से मस न होने वाला नेता माना जाता है, वैसे भी गांधीनगर से लोकसभा पहुंचने के बाद उत्तराधिकारी भी बन गए हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला भी शाह को सूट नहीं करता, लेकिन वीटो चूंकि मोदी के हाथ में रहता है, इसलिए आखिरी फैसला वही लेते हैं।

गए और कुर्सी पर बिठा दिए गए। भाजपा को लेकर योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड कभी अनुशासित नहीं रहा है। 2002 में गोरखपुर विधानसभा सीट पर पहली बार योगी आदित्यनाथ के तेवर देखने को मिले थे। भाजपा ने 1989 से विधायक रहे शिवप्रताप शुक्ला को फिर से उम्मीदवार बनाया तो योगी आदित्यनाथ विरोध में खड़े हो गए। फिर योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन दास अग्रवाल को खड़ा कर दिया और चुनाव प्रचार में खुद ही मोर्चा संभाल लिया। शिव प्रताप शुक्ला चुनाव हार गए। उसके बाद फिर कभी योगी ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट नहीं देने दिया। 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा ने शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा भेजा और फिर मंत्री बनाया गया। ये योगी पर लगाए जाने वाले ठाकुरवाद के आरोपों को काउंटर करने की भाजपा की तरकीब रही। शिव प्रताप शुक्ला को भाजपा में हाल ही में बनी ब्राह्मण कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जो योगी आदित्यनाथ भाजपा के साथ एक अनुशासित नेता की जगह एक गठबंधन सहयोगी जैसा व्यवहार करते आ रहे हों, 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बन जाने के बाद क्या मोदी के लिए चुनौती नहीं बन सकते?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने कामकाज को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और मोदी सरकार में वो मिस्टर परफॉर्मर के तौर पर खुद को पेश करते रहे हैं। नागपुर से आने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पसंदीदा नेता होने के नाते 2019 के आम चुनाव से पहले से ही नितिन गडकरी को मोदी के चैलेंजर के रूप में देखा जाता रहा है। बीते आम चुनाव से पहले तो नितिन गडकरी ने ऐसा रुख अख्तियार किया हुआ था कि भाजपा नेतृत्व की तरफ से दिल्ली दो दूतों की एक टीम को उनके घर भेजना पड़ा था। समझाने के लिए। दूतों ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके तेवर में तब तक कोई तब्दीली नहीं महसूस की गई जब तक कि आम चुनाव के नतीजे नहीं आ गए। भाजपा को 2019 में 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली थीं और ये गडकरी या उनके जैसे खामोश नेताओं को चुप कराने के लिए काफी थीं। मोदी के बाद संघ की पसंद होने के साथ-साथ गडकरी अपने बात व्यवहार से विपक्षी खेमे में भी ज्यादा स्वीकार्य हैं। फर्ज कीजिए अगली बार भाजपा को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है और अगर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं का सपोर्ट लेने की नौबत आ जाती है, फिर तो मोदी की जगह गडकरी के नाम पर ही बात बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो संघ की तरफ से गडकरी के कामकाज को आगे कर देश का आर्थिक सुपर पावर बनाने का स्लोगन भी दिया जा सकता है।

विपक्षी खेमे से एक दौर में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध की आवाज माने जाते रहे। हालांकि, सभी का नंबर राहुल गांधी के बाद ही आता रहा। अब ये समीकरण बदलने लगा है। मोदी को कभी कायर और मनोरोगी बता चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी दिनों तक मोदी-शाह के खिलाफ बोलने से बचते रहे, लेकिन एक बार टीवी पर हनुमान चालीसा क्या पढ़ दिया, 2020 में दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद से तो नारा ही लगाने लगे हैं-जय श्रीराम।

2022 में अरविंद केजरीवाल उप्र, उत्तराखंड और पंजाब के अलावा गोवा विधानसभा चुनावों को लेकर काफी एक्टिव हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद अगर उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं तो कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं है। केजरीवाल नगर निगम के नतीजों में विधानसभा चुनाव का नक्शा देखने लगे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी की कॉपी करने लगे हों। जिस अयोध्या को मोदी सरकार उप्र की योगी सरकार के साथ डबल इंजन के विकास के **मॉडल के तौर पर** पेश कर रही है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में भी तो हिंदुत्व के ही विकास मॉडल की झलक दिखाई पड़ रही है। मनीष सिसोदिया के साथ अयोध्या जाकर केजरीवाल जय श्रीराम तो बोलते ही हैं, दिल्ली लौटकर लोगों को ट्रेन से भेजकर अयोध्या दर्शन करा रहे हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां दोहरा रहे हों-राह पकड़ तू एक चला जा पा जाएगा मधुशाला।

2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो भाजपा की हार हुई ही, सालभर बाद पश्चिम बंगाल में तो और भी बुरा हाल हुआ। भाजपा के प्रदर्शन ने तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की वो भविष्यवाणी भी सच कर दी जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। नीतीश कुमार के मोदी को नेता मान लेने और केजरीवाल के उनका फॉलोवर बन जाने के बाद मार्केट में संघ और भाजपा की राजनीति के विरोध में एक ही जोरदार आवाज है और वो है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के अलावा विरोध की आवाज तो राहुल गांधी की जुबान से भी सुनाई पड़ती है, लेकिन उनके पास वो आवाज जमीन से नहीं आती। जो हैसियत ममता बनर्जी ने मोदी-शाह को शिकस्त देते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में जीतकर हासिल की है, राहुल गांधी तो जैसे तरस कर रह गए हैं। ये जरूर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ममता बनर्जी को एक दायरे में समेटने की कोशिश हो रही है, लेकिन 2022 में तस्वीर ज्यादा साफ होने वाली है। सत्ता भले न मिल पाए, लेकिन अगर ममता बनर्जी गोवा में तृणमूल कांग्रेस को सबसे बड़ा विपक्षी दल भी बना लेती हैं तो कुछ लोगों के मुंह तो बंद करा ही सकेंगी।

● इन्द्र कुमार

ममता बनर्जी मोदी को चैलेंज करने में सबसे आगे!

ममता बनर्जी अभी तक मोदी को चैलेंज करने वालों में सबसे आगे तो नहीं है, लेकिन फ्रंट रनर बनी हुई हैं। अगले आम चुनाव तक अभी कई तरह के उलटफेर होंगे और रास्ते की बाधाओं को खत्म करती चली गईं तो ममता बनर्जी सबको पीछे छोड़ते हुए आगे भी निकल सकती हैं। जिस तरह महिला रिजर्वेशन को लेकर प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में 50 फीसदी की बात भी करने लगी हैं, भाजपा सहित उन राजनीतिक दलों के लिए भी दिक्कत हो सकती है जो 33 फीसदी पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अपने-अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर चुके हैं, ये याद दिलाते हुए कि भाजपा बहुमत में है और कांग्रेस पूरी सपोर्ट करेगी। सोनिया और राहुल ने ये समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस से जितना संभव हो सकता यूपीए सरकार में कर दिया गया है अब आगे भाजपा की जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के ऊपर लीड मिलती लग रही है और ये इसीलिए लग रहा है कि राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी चैलेंजर बन सकती हैं और ये सब 2022 के उप्र विधानसभा चुनाव में तय भी हो जाना है।

कांग्रेस ने बदला काउंटर का तरीका!

बीते कुछ सालों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी प्रचार और जवाबी शैली को बदला है। कांग्रेस अब विरोधियों के बयानों के आधार पर ही प्रति प्रहार के अनूठे तरीके अपनाना जान गई है। यह कला उसने भाजपा से ही सीखी है। बात लोकसभा चुनाव 2019 के समर की हो, जब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मे चायवाला वर्सेस छोटा आदमी की जंग छेड़कर चाय पर चर्चा की तरह ही आय पर चर्चा का चुनावी अभियान शुरू किया था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस की शैली में हमेशा विरोधियों को जवाब देने के नायाब तरीके शामिल रहे हैं। ताजा मसला है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बयान को सरपंचों का अपमान बताया जाना।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी को पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं और ऐसे ही वक्त में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाषा शैली पर सवाल उठाते हुए, उन्हें सरपंच स्तर की भाषा प्रयोग करने वाला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ जनता द्वारा निर्वाचित निचले पायदान के प्रमुख जनप्रतिनिधि सरपंचों के लिए इतने पूर्वाग्रही क्यों हैं? अगर वे सरपंचों की भाषा समझ जाते तो भाजपा 15 सीट पर नहीं अटकती।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि डॉ. रमन सिंह सरपंचों को हिकारत की नजर से क्यों देखते हैं? शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछते हुए कहा कि क्या देश और प्रदेश के सरपंचों में भाषा के संस्कार नहीं हैं? रमन सिंह ने सरपंचों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने अपने सुरक्षा की तथाकथित चूक को लेकर जिस स्तर तक प्रतिक्रिया दी है, उसे सारा देश सुनियोजित ड्रामा की संज्ञा दे रहा है। भाजपा नेता देशभर में जो हवन यज्ञ की नौटंकी कर रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर संबोधित करने के कारण कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ चायवाला ही नहीं कह रही थी, बल्कि उनकी योग्यता पर सवाल उठा रही थी।

भाजपा ने मुद्दे को भुनाते हुए इसे देशभर के गरीब परिवार चाय बेचने वालों का अपमान बताते हुए कहा था कि कांग्रेस एक गरीब को देश का प्रधानमंत्री बनते नहीं देख सकती है। तब भाजपा ने मुद्दा लपकते हुए चाय पर चर्चा नाम से चुनावी कैंपेन छेड़ दिया था। इसका भाजपा को चुनाव में फायदा भी हुआ। जनता के मन मे नरेंद्र मोदी की छवि आम जनता के नेता की बनी और बचपन में चाय बेचने वाले मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। दरअसल, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने संघर्ष को भुनाने के लिए कई मंचो पर बार-बार कहा था कि वो बचपन में चाय बेचा करते थे और वहां से उठकर लंबे संघर्ष के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं।

बात 2019 के लोकसभा चुनावी समर की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस ने 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 68 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 15 साल तक सत्ता संभालने वाली भाजपा को 13 सीट पर समेट दिया था। चुनाव जीतने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनावी अभियान के तहत अपना सच देखने के लिए आइना भेजा। इस घटना के बाद से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बघेल को छोटे मन से छोटी हरकतें करने वाला छोटा आदमी कह दिया। जिसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे छोटा आदमी लिख दिया था। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे छोटा आदमी लिखना शुरू कर दिया था।

दरअसल बघेल को यह आइडिया राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार-बार निशाना बनाकर चौकीदार चोर है के नारे लगाए जाने के बाद भाजपा की तरह से आलोचना को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से ही आया था। राहुल गांधी के हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया था।

● रायपुर से टीपी सिंह

क्या सरपंचों के मान-अपमान का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस?

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना सामने आने के बाद से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से लगातार दिए जा रहे बयानों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बघेल की भाषा पर आपत्ति जताते हुए उन्हें सरपंच स्तर का बयान देने वाला व्यक्ति बताया था और इसकी शिकायत राज्यपाल से भी की थी। जिसके बाद कांग्रेस ने इसे सरपंचों का अपमान बताया है। अब देखना यह होगा कि 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ में हो रहे आगामी सरपंच चुनावों में इस मुद्दे को कांग्रेस भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती है।

ये दाग अच्छे नहीं हैं!

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक बैकग्राउंड वाले जनप्रतिनिधियों के मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे 23 फीसदी आपराधिक बैकग्राउंड वाले जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत का गठन अभी तक नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान में 2008 और 2014 से अधिक संख्या में 2018 में आपराधिक बैकग्राउंड वाले जनप्रतिनिधि जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं।

न्याय में देरी, अन्याय है। अर्थात् दोषी को यदि बहुत अधिक देरी के बाद सजा मिलती है, तो ऐसे न्याय की कोई सार्थकता नहीं है। राजस्थान के 31 विधायक और 6 सांसदों के खिलाफ 16 साल से लंबित आपराधिक मामलों को लेकर पुलिस के नजरिए से यह बात याद आई। दरअसल एडीजी (क्राइम) रविप्रकाश मेहरड़ा का कहना है कि विधायक और सांसदों के खिलाफ दर्ज कुल 64 आपराधिक मामलों का बहुत ही सूक्ष्मता से अनुसंधान किया जा रहा है। यह बयान बहुत ही हैरान-परेशान करने वाला है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से साफ छवि वाले नेताओं को टिकट देने की जोर शोर से बात की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राजनीतिक दल आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं पर मेहरबान नजर आते हैं।

राजस्थान की बात करें तो साल दर साल आपराधिक बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट देने के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं जनता भी आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं को भरपूर आशीर्वाद दे रही है। प्रदेश में साल 2008 से साल 2013 की तुलना में साल 2018 में दागी विधायकों की संख्या बढ़ी है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2008 में राजस्थान विधानसभा में करीब 23 फीसदी विधायकों पर ही अपराधिक मुकदमा दर्ज था। इनमें से 8 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। साल 2008 में 15 फीसदी यानी 30 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। यह संख्या साल 2013 में बढ़कर 36 हो गई और अब साल 2018 में दागी नेताओं की संख्या बढ़कर 46 पर पहुंच गई है, यानी 23 फीसदी विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 14 फीसदी विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजनीति से आपराधिक छवि के लोगों को बाहर करने के लिए लंबे समय से बहस चल रही है। जब अनुसंधान की दशा और दिशा यही होगी तो समझ सकते हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था किस हाल में है? क्या राज्य का कोई भी समझदार और तजुर्बेकार अधिकारी पुलिस के इस कथन से सहमत हो सकता है? हैरानी की बात है कि डेढ़ दशक बाद भी 37 जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमों पर अनुसंधान टस से मस नहीं हुआ। ये मामले अब तक अनुसंधान अधिकारी के स्तर पर ही लंबित हैं।

इस बीच कांग्रेस और भाजपा की तीन सरकार आईं और बदल गईं। चिंता की बात यह है कि इसमें दोनों प्रमुख दलों की लगभग बराबर भागीदारी है। इससे स्पष्ट है कि अपराध से दागदार नेता हमारा सिस्टम चला रहे हैं। ऐसे में क्या राजनीति को दागियों से मुक्त करने की उम्मीद की जा सकती है? पुलिस का दायित्व है कि वह पारदर्शिता के साथ अनुसंधान करके उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश करे। चुनावी वादों में राजनीति को अपराध मुक्त करने के खूब वादे होते हैं लेकिन विरोधाभास देखिए, जब टिकट देने का समय आता है तो कांग्रेस हो या भाजपा उन्हें सबसे मजबूत और जिताऊ प्रत्याशी वही नजर आता है जिस पर मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही के एक सर्वे में सरकार के कामकाज से 68.5 फीसदी लोग संतुष्ट नहीं हैं। उधर, सर्वे में 66.4 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विपक्ष भी जनता की आवाज नहीं बन पाया।

अदालतों ने भी राजनीति में अपराध के घालमेल को लेकर कई बार सरकार के कान खींचे हैं। पिछले चुनाव में तो इस बात के लिए बाध्य किया गया कि चुनाव में खड़े प्रत्याशी को उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों को विज्ञापन के जरिए जनता को बताना होगा। इसके बावजूद खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं हुआ। चुनाव आयोग अब तक कोई ठोस मानक तय नहीं कर सका है। आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि गंभीर आपराधिक धाराओं में विचाराधीन नेता चुनाव ही न लड़ सकें। चूंकि ऐसे लोग जब चुनकर संसद या विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो कानून-व्यवस्था को अपने इशारे पर नचाते हैं। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे भी फिर सालों-साल लंबित ही रहते हैं। मुकदमों की पूंजी के साथ कोई दागदार व्यक्ति जीतकर मंत्री बन जाता है तो जनता ही दुख पाती है। निश्चित ही ऐसा नेता कई जगह समझौते करेगा, भ्रष्ट और अपराध में लिप्त स्वार्थी समर्थकों को प्रश्रय देगा। दूषित गठबंधन बनाएगा और लाचार व बेबस जनता उसके क्रियाकलाप देखती रहेगी। बाद में पश्चाताप करने से बेहतर है, जनता आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को वोट ही न दे तो कुछ सुधार की गुंजाइश जरूर है।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

राजस्थान में फिर बदलेंगे सियासी समीकरण

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उठापटक की स्थिति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर बड़ा फैसला आने की संभावनाएं हैं। सूत्रों की मानें तो पायलट को लेकर पहले से ही कांग्रेस आलाकमान अपना मन बनाए हुए हैं लेकिन फिलहाल अभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया जा रहा है। अजमेर के एक मजबूत कांग्रेस नेता का कहना है कि प्रदेश में एक बार फिर से उठापटक के हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान मार्च महीने के बाद पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व स्थानीय नेताओं संग बातचीत भी कर रहा है। राजस्थान के सट्टा बाजार में भी पायलट के प्रदेश में वापस मजबूत होने की चर्चाएं जोरों पर हैं। सटोरियों के मुताबिक, मार्च के बाद पायलट प्रदेश में मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट को दिल्ली भेजकर उन्हें सगठन की जिम्मेदारी देकर प्रदेश से दूर किया जा सकता है।

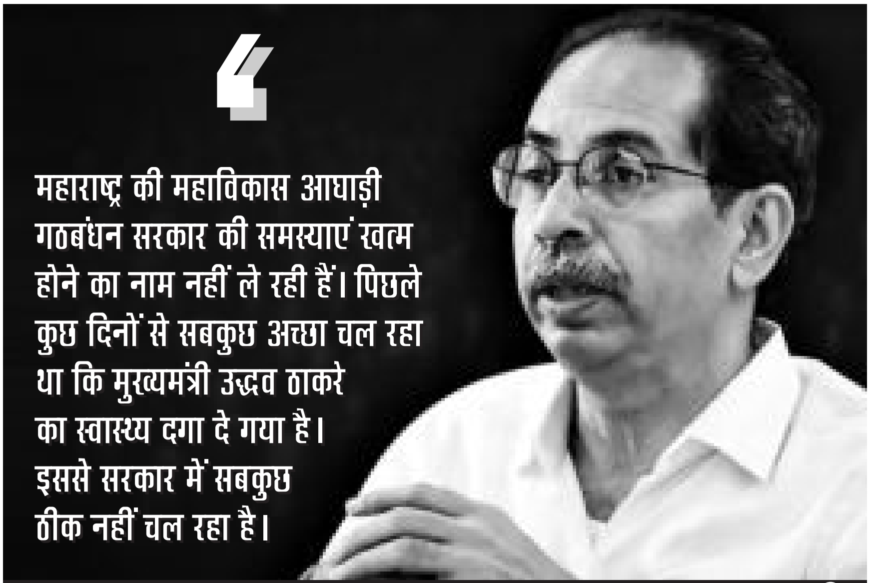

सब कुछ ठीक नहीं

राजनीति में नेता और नेता पर निर्भर पार्टी का भविष्य चुनाव से तो आंका ही जाता है, नेता के स्वास्थ्य से भी ये सीधा जुड़ा होता है। इसीलिए कई बार किसी नेता की तबियत ठीक ना हो तो उसपर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। यही वजह है कि पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश होती है कि जहां तक हो सके मामला छुपाया जाए, नहीं तो, 'सब ठीक है' का माहौल बनाए रखा जाए। लेकिन अगर नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो तो ऐसा करना काफी मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का मामला इसका प्रमाण है।

वैसे भी उद्धव ठाकरे बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह मुंबई में मुख्यमंत्री दफ्तर में आकर काम करने के बजाय अपने मुख्यमंत्री आवास पर रहकर काम करना पसंद करते हैं। कोविड के समय ये चल पाया जब पूरी दुनिया वर्चुअली काम पर जोर दे रही थी। लेकिन स्थिति सुधरने के बाद भी उद्धव अपने तरीके से काम करते रहे। विपक्षी भाजपा ने इसे मुद्दा भी बनाया। लेकिन किसी संवैधानिक पद पर काम कर रहे पहले 'ठाकरे' ने अपने तरीके से ही काम जारी रखा। हाल-फिलहाल में उनकी हुई सर्जरी की वजह से उद्धव एकबार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन इसबार सिर्फ उनकी सेहत या उनके काम करने के तरीके पर नहीं बल्कि उनकी सेहत की आड़ में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की सेहत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है।

दरअसल, 10 नवंबर को उद्धव ठाकरे की गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। 2 दिसंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उनके चलने-फिरने या सामान्य रूप से काम करने पर काफी अटकलें लगीं। इस तरह के ऑपरेशन के बाद सामान्य रूप से चलने-फिरने में कई महीनों का समय लगता है। कई दिनों तक शांत रहने के बाद विपक्ष ने इस मामले को तूल देना शुरू किया कि अगर उद्धव ठाकरे की सेहत महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को संभालने के लिए साथ नहीं दे रही तो उन्हें अपने पद का प्रभार किसी और को दे देना चाहिए। भाजपा ने कटाक्ष भी किया कि कांग्रेस एनसीपी के किसी नेता को उद्धव अगर चार्ज नहीं देना चाहते तो अपनी पत्नी या बेटे आदित्य ठाकरे जो उनकी ही सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें दे दें। दरअसल भाजपा की ये कोशिश थी कि सरकार की राजनीतिक मजबूरी को वो उजागर करे और साथ ही दबाव बनाएं कि कैसे सरकार मुख्यमंत्री की सेहत की वजह से सक्षम नहीं है।

उद्धव एक विशिष्ट स्थिति में मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने बेटे आदित्य की तरह खुद चुनाव लड़कर विधानसभा की राजनीति में आने का फैसला नहीं लिया था। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों के बाद जो स्थिति बनी उसकी वजह से अपनी 'रिमोट कंट्रोल' राजनीति छोड़ उनको मैदान में उतरना पड़ा। शिवसेना के किसी और नेता के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी के वरिष्ठ नेता काम करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे को खुद मुख्यमंत्री बनना पड़ा ताकि शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बन सके, अब किसी वजह से उद्धव मुख्यमंत्री नहीं रह सकते तो इस सरकार के चलने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या सालों तक मंत्री रह चुके हैं वो किसी 'जूनियर' शिवसेना नेता को मंजूर नहीं करेंगे।

सीएम की सेहत खराब रहना चुनाव में खतरा

ऐसा नहीं है कि सेहत खराब रहना किसी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव में खतरा ही साबित हुआ हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन अमेरिका में कैंसर का इलाज कराते हुए भी चुनाव जीते थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव भी जब विदेश में इलाज करा रहे थे तभी उनकी सरकार गिराई गई थी लेकिन लोक दबाव के चलते उन्हें दोबारा अपना पद मिल गया था। कई बार सेहत का ठीक ना होना सहानुभूति भी पैदा कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अकेले शिवसेना की नहीं है, ये तीन पार्टियों की मिली-जुली सरकार है और ऐसे में उद्धव ठाकरे का सेहतमंद रहना सरकार चलाने के लिए जरूरी बन गया है। तीनों पार्टियों की आपसी सूझबूझ कितनी बेहतर है ये जांचने की भी ये एक और परीक्षा है। क्योंकि भाजपा ये मौका भुनाने से नहीं चूकेगी।

आदित्य पहली बार मंत्री बने हैं और उम्र के हिसाब से भी काफी छोटे हैं। ऐसे में सरकार को टिकाना है तो जो स्थिति है उसी में उद्धव ठाकरे के नाम पर सरकार चलाना शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों की मजबूरी है। भाजपा को ये पता है और इसीलिए उद्धव की सेहत पर अटकलों का बाजार गर्म रखना उनके लिए फायदे का सौदा है। ऐसे में उद्धव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट और बाकी अहम मीटिंग ले रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें और वीडियो अनौपचारिक तौर पर जारी कर दिए गए। खुद उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भरोसा दिलाया कि उद्धव विधानसभा सेशन में आएंगे।

आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि उद्धव मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का डेढ़ महीने से किसी खुले कार्यक्रम में ना दिखना अटकलों का बाजार गर्म कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2022 में महाराष्ट्र में मुंबई समेत 12 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। मुंबई महानगर पालिका शिवसेना के कब्जे में पिछले 25 साल से है, उस पर कब्जा बनाए रखना सरकार से ज्यादा पार्टी के लिए जीने-मरने का सवाल है। और अगर किसी वजह से उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में नहीं दिखे तो शिवसेना के लिए अच्छा नहीं होगा। सरकार की स्थिरता पर दोबारा सवाल उठना शुरू हो सकता है, इसीलिए कोशिश ये हो रही है कि जितना हो सके सब ठीक है का नारा बरकरार रहे।

● **बिन्दु माथुर**

हार भी जीत का रास्ता

कांग्रेस की महासचिव और उप्र प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, लड़कियों में हिम्मत बांध रहीं हैं, उनकी हौसला-अफजाई कर रही हैं। अच्छा होगा कि वो खुद भी हिम्मत दिखाएं और निडरता से उप्र के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अपना नाम पेश कर दें। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में हार की संभावना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंधाधुंध रैलियों को याद करें। प्रियंका ये न सोचें कि उप्र में हार गए तो मुख्यमंत्री की दावेदारी की वजह से उनका नाम खराब होगा। प्रियंका खुद कह रही हैं कि हार भी जीत का रास्ता तय करती हैं, अहम चीज है निडरता से लड़ना। हिम्मत और हार ही हर जीत का फलसफा तय करती है। प्रियंका की यात्राओं और हिरासत के संघर्षों से लेकर लड़कियों की मैराथन के आकर्षण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते देख लग रहा है कि उप्र कांग्रेस का इवेंट मैनेजमेंट अपना असर दिखा रहा है।

प्रियंका इवेंट के मामले में भाजपा की सफलता के मूल मंत्र पर अमल करती दिख रही हैं। तो फिर भाजपा के उस हुनर को भी अपनाए जिसके तहत चुनावी लड़ाई में भाजपा के शीर्ष नेता अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने में ये नहीं सोचते कि हार गए तो उनका नाम खराब होगा या उनकी ब्रांड वैल्यू कम होगी। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनावों में भाजपा के जीतने अथवा सरकार बनाने की संभावना बेहद कम थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं ने यहां अपनी सभाओं-रैलियों की झड़ी लगा दी थी। ये नहीं सोचा कि यहां चुनाव हार गए तो बड़े नाम की साख खराब होगी।

राजनीति में ये परंपरा रही है कि बड़ा नेता अथवा पार्टी अपनी कमजोर जमीन वाले चुनावों में खुद के बजाय छोटे प्यादों को सामने लाती है ताकि चुनाव हारे तो हार का ठीकरा उसके सिर न फूटे। ऐसी परंपरा को भाजपा ने तोड़ा है। यहां तक कि छोटे-छोटे चुनावों (उपचुनाव-निकाय चुनाव) में भी भाजपा के बड़े नेता सभाएं-रैलियां करते हैं। कांग्रेस को भाजपा से ऐसी जोखिम भरी हिम्मत के जज्बे का सबक सीखना होगा। उप्र में प्रियंका का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके कांग्रेस हिम्मत बढ़ा कदम बढ़ा कर अपना जनाधार बढ़ा सकती है और ऐसे में संगठन में भी मजबूती आ सकती है। देश के जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीख चंद दिनों में आने वाली है उनमें उप्र सबसे अहम है।

कांग्रेस उप्र में बेहद कमजोर है पर यहां पार्टी सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। जिसके कई कारण हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उप्र में अपना संगठन और जनाधार बेहतर करके वोट प्रतिशत में इजाफा करना चाहती है। विशाल उप्र लोकसभा में हार-जीत के लिए निर्णायक होता है? उप्र में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की लोकसभा सीट है और प्रियंका गांधी ने बतौर उप्र प्रभारी इस सूबे में कांग्रेस की खोई हुई जमीन को हासिल करने का जिम्मा लिया है। इसलिए पार्टी ने प्रियंका गांधी और संपूर्ण गांधी परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जान फूंक दी है। यहां पार्टी ने धर्म-जाति से अलग हटकर महिलाओं और युवतियों को लुभाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जारी रखें हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बिलकुल अलग हटकर महिलाओं का मुद्दा कांग्रेस के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है।

यदि प्रियंका गांधी को उप्र के मुख्यमंत्री का दावेदार पेश कर दिया जाए तो पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। ब्राह्मण समाज भी पार्टी की तरफ आकर्षित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ऐसा करने से झिझक रही है, क्योंकि पार्टी को पता है कि बहुत बेहतर सीटें पाने के बाद भी सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए पार्टी सिर्फ प्रियंका के चेहरे और आकर्षक इवेंट वाले प्रचार के जरिए लोकसभा चुनाव तक अपना जनाधार और वोट प्रतिशत बढ़ाने की जमीन तैयार कर रही है। आकर्षक प्रचार में माहिर भाजपा के नक्शे-कदम पर चलकर कांग्रेस जनता तक पंहुचने, दिलों में जगह बनाने और चर्चाओं में आने के लिए प्रचार तंत्र और इवेंट मैनेजमेंट पर खूब ध्यान दे रही है। इसके अलावा धर्म और जाति की राजनीति की नूराकुश्ती से अलग हटकर उप्र कांग्रेस महिला वर्ग को आगे बढ़ाने के एजेंडे का प्रयोग कर रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, नारे के साथ महिला वर्ग को आगे लाने वाले कांग्रेस खुद में भी ये हौसला और भरोसा पैदा करे कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए अच्छी लड़ाई लड़ सकती हैं।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना क्यों मुश्किल?

वैसे, प्रियंका गांधी का उप्र चुनाव लड़ना मुश्किल ही नजर आता है। क्योंकि, प्रियंका गांधी ने भले ही कांग्रेस के लिए देशभर में चुनाव प्रचार से लेकर राज्यों में चल रही खींचतान को निपटाने वाली नेता के तौर पर पहचान बना रखी हो। लेकिन, सक्रिय राजनीति से वह अभी तक दूर ही रही हैं। प्रियंका अगर सक्रिय राजनीति में कदम रखने की सोचती हैं, तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन, उनके इस फैसले का सीधा असर राजनीति में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ स्थापित करने की कोशिश कर रहे उनके भाई राहुल गांधी पर पड़ेगा। इससे पहले भी कांग्रेस में कई बार प्रियंका गांधी को नेतृत्व देने की मांग उठ चुकी है। लेकिन, शायद ही प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर ताला लगाना चाहेंगी। प्रियंका पार्टी के लिए और पार्टी में सक्रिय नजर आ सकती हैं। लेकिन, चुनाव में उतरने से सीधा खतरा राहुल गांधी पर बन जाएगा।

राज्यसभा की सीटों को लेकर रस्साकशी

2022 में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है। यह 5 सीटें बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होगी। खासतौर पर जदयू से एकमात्र केंद्र में मंत्री बने आरसीपी सिंह साल के जुलाई में राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं। तो वहीं, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी राज्यसभा से रिटायर हो जाएंगी। भाजपा की तरफ से 2 सीटें खाली होने वाली हैं। इसमें गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे शामिल है। वहीं जदयू से किंग महेंद्र के निधन के बाद एक सीट पहले से ही खाली है। इन 5 सीटों के लिए सभी दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है जो भी नेता रिटायर हो रहे हैं वह राजनीति में महत्वपूर्ण हैं और उनके दल के लिए खास हैं।

पहले बात भाजपा की करते हैं। भाजपा से दो सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं। दोनों अगड़ी जाति की सीटें हैं। मसलन दोनों पर सवर्ण नेता हैं। गोपाल नारायण सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं। शाहाबाद के इलाके में खासा प्रभाव है। साथ ही संघ में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। इसके अलावा इनके लिए विशेष यह है कि भाजपा के गिने-चुने अमीर नेताओं में आते हैं। ऐसे में भाजपा इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजती है या फिर इन पर विराम लगाती है ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी। इसके अलावा सतीश चंद्र दुबे भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि वह ब्राह्मण जाति से आते हैं। हाल के दिनों में जीतनराम मांझी ने ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान देकर इनके सीट को सेफ कर दिया है। हालांकि राज्यसभा की सीटों का अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से होता है। वैसे भी सतीश चंद्र दुबे को भाजपा ने वाल्मीकि नगर से लोकसभा का चुनाव ना लड़ाकर जोखिम लिया था, उन्हें आनन-फानन में राज्यसभा भेजकर डैमेज को कंट्रोल किया था। एक बार फिर से सतीश चंद्र दुबे अपने सीट पर दावा ठोकेंगे।

जदयू की तरफ से 2 सीटें हैं। एक अभी खाली है इस सीट पर किंग महेंद्र थे उनके निधन के बाद सीट खाली है। उनका 2 साल का कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है। इस 2 साल के लिए जदयू किसे राज्यसभा भेजती है यह देखने वाली बात है। हालांकि इस सीट के लिए केसी त्यागी का नाम चलने लगा है। उन्हें जदयू राज्यसभा भेज सकती है। वहीं, दूसरी सीट जो जुलाई में खाली होने वाली है। वह केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की है। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं और लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो जदयू इस लिहाज से कोई जोखिम नहीं उठाने वाली है। यानी कि जदयू तीसरी बार रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि आरसीपी सिंह की अदावत ललन सिंह से लगातार चलती रही है। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बावजूद जदयू आरसीपी सिंह को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहेगी।

राजद की तरफ से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। अब मीसा भारती को लेकर फैसला लालू यादव को ना करके तेजस्वी यादव को करना है। तेजस्वी यादव रणनीति के तहत मीसा भारती को एक बार फिर से राज्यसभा सदस्य बनाकर दिल्ली भेज सकते हैं। ताकि उनकी राजनीति बिहार में आराम से चलती रहे। माना जाता है कि मीसा भारती राजद के सर्वोच्च पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। लेकिन, तेजस्वी यादव उन्हें इस से दूर रखना चाहेंगे। इसलिए बिना कुछ सोचे-समझे मीसा भारती को दोबारा राज्यसभा भेजा जा सकता है।

हालांकि, राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का निधन होने के बाद उनकी सीट को लेकर अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इन 4 सीटों के अलावा उनके 1 सीट का अलग नोटिफिकेशन होगा। उस पर जदयू किसी दूसरे नेता को राज्यसभा सदस्य बना सकती है। यदि यह 5 सीट हो जाती तो जदयू को एक सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता था। क्योंकि इस बार जदयू की कम सीटें हैं और राजद-भाजपा की ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में नुकसान जदयू को उठाना पड़ता। लेकिन किंग महेंद्र के निधन से और उनके नोटिफिकेशन अलग होने से जदयू की ये सीट बच जाएगी।

उधर इसके साथ ही यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि क्या बिहार के दो युवा नेता तेजस्वी यादव (राजद) तथा चिराग पासवान (लोजपा) अपने पिता लालू प्रसाद यादव तथा रामविलास पासवान के खाली स्थान को भर पाएंगे। लालू तथा पासवान दशकों से बिहार की राजनीति के श्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं। इन नेताओं ने 80 के दशक के अंत में राजनीति की सोच को समझ कर प्रभावशाली कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी और कुछ हद तक इसमें सफल भी रहे।

● **विनोद बक्सरी**

भाजपा के जवाब में नीतीश की यात्रा!

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी राजनीतिक रूप से कमजोर होते हैं या अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा को कोई मैसेज देना होता है तो वे यात्रा शुरू कर देते हैं। उनकी ऐसी लगभग सारी यात्राएं वाल्मीकि नगर से शुरू होती है। इस क्षेत्र का बड़ा धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। इस बार नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं। उनके लिए समाज सुधार का मतलब शराबबंदी है। वैसे यह मतलब भी उनको पांच-छह साल पहले ही पता चला था क्योंकि उससे पहले तो वे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले शराब की दुकानों के लाइसेंस बांट रहे थे। लेकिन अब उन्होंने पूरे प्रदेश की पुलिस और प्रशासन को शराबबंदी कानून लागू कराने में लगा दिया है। बहरहाल, उनकी इस यात्रा की टाइमिंग और मकसद दोनों बहुत स्पष्ट हैं। वे अपनी सहयोगी भाजपा को मैसेज देने के लिए यात्रा कर रहे हैं। वे लोगों से सीधे कनेक्ट कर रहे हैं और जहां भी यात्रा में जा रहे हैं वहां अपने स्थानीय नेताओं के साथ आगे की राजनीति पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। उनको पता है कि उनके बगैर भाजपा राज्य में सरकार नहीं बना पाएगी और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जरूरत है। इसलिए वे पार्टी के प्रदेश नेताओं को अपने तेवर दिखा रहे हैं।

कौन लेना चाहेगा पाकिस्तान की नागरिकता...?

दुनियाभर के देशों और वैश्विक बैंकों के कर्ज में गले तक डूबे पाकिस्तान के आर्थिक हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कर्ज उतारने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नए-नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान ने अपने कर्ज को कम करने के लिए चीन को गधे बेचने से लेकर संरक्षित प्रजाति की सोन चिरैया के शिकार के लिए सऊदी राजघरानों को लाइसेंस देने तक के अजीबोगरीब फैसले लिए हैं। वहीं, अब इमरान खान ने पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। दरअसल, इमरान खान सरकार दुनियाभर के लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता देने की तैयारी कर रही है। और, इसके लिए बस एक छोटी सी शर्त है, जो घूम-फिर कर पाकिस्तान का कर्ज कम करने की तरकीब ही कही जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने एक मिलियन डॉलर का निवेश करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक को अपने देश की नागरिकता देने का मन बनाया है।

पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री इमरान खान ने केवल अफगानिस्तान के व्यवसायियों और बड़े धनकुबेरों को पाकिस्तान की नागरिकता देने के प्लान को नकार दिया। इमरान खान का मानना था कि पाकिस्तान की नागरिकता को केवल अफगानिस्तान के लोगों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। दुनियाभर के जो भी लोग पाकिस्तान में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता दी जानी चाहिए। इस स्कीम को लेकर हुई बैठक में इमरान खान ने माना कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों ने भी अपने यहां पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ही पॉलिसी अपनाई है, तो पाकिस्तान को भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। दुनियाभर के लोगों के लिए पाकिस्तान की नागरिकता के रास्ते खोल देना एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। लेकिन, सबसे बड़ी बात यह ही है कि आखिर पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान की नागरिकता कौन लेना चाहेगा?

अगर किसी देश की नागरिकता लेने का मौका मिला, तो लोग अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों को तरजीह देते हैं। शायद ही कोई कम अक्ल होगा, जो पैसे लगाकर पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहेगा। सवाल ये भी है कि जिस देश अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने नागरिकता देने की योजना बनाई है, वहां के लोग भी आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली कहावत को क्यों चरितार्थ करना चाहेंगे? पाकिस्तान में पहले से ही रह रहे अफगानिस्तानी नागरिकों और अफगानिस्तान में तालिबान का असर बढ़ने के बाद देश छोड़ रहे लोगों को जब पैसों का निवेश ही करना होगा, तो वो पाकिस्तान में क्यों बसना चाहेंगे? क्योंकि, पैसों का निवेश कर सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों का रास्ता भी तो खुला हुआ है। और, वहां पर किसी तरह के इस्लामिक आतंकी संगठन का खतरा भी नहीं होगा। पाकिस्तान पर तो वैसे ही तालिबान के आतंकियों को शरण देने का आरोप लगा है। इस स्थिति में अफगानिस्तान के व्यापारी पाकिस्तान पर कितना भरोसा कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है।

वैसे, इमरान खान की दुनियाभर के लोगों को पाकिस्तान की नागरिकता देने की बात करने के पीछे की वजह भी बहुत दिलचस्प है। दरअसल, अगर पाकिस्तान की ये पॉलिसी केवल अफगानिस्तान के लोगों के लिए ही मान्य होगी, तो अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान का भड़कना स्वाभाविक है। क्योंकि, हाल ही में तालिबान की ओर से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के सैनिक अगर अफगानिस्तान की जमीन पर एक भी कदम रखें, तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाए। तालिबान का ये आदेश इस नागरिकता पॉलिसी की सुगबुगाहट के बीच ही आया है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो पाकिस्तान की इस पॉलिसी में बदलाव की सबसे बड़ी वजह तालिबान का डर है। इसी वजह से इमरान खान ने इस पॉलिसी को दुनियाभर के लोगों के लिए बनाने का निर्देश दिया है। वैसे भी पाकिस्तान के पास दोस्त देशों के नाम पर चीन, तुर्की और अफगानिस्तान ही हैं। अगर इनमें से भी एक भड़क गया, तो पाकिस्तान के पास बचेगा कौन? क्योंकि, सऊदी अरब को तो पाकिस्तान पहले ही कश्मीर मामले को लेकर गुस्सा कर चुका है।

● ऋतेन्द्र माथुर

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही

खैर, अरबों के कर्ज में लदे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान कर्ज उतराने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, आईएमएफ द्वारा ग्रे लिस्ट में डाले जाने के बाद से इमरान खान किसी भी देश से कर्ज लेने में उसकी नियम-शर्तों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब की कई शर्मनाक शर्तों को मानते हुए कर्ज लिया था। जिसमें कहा गया था कि अगर सऊदी अरब अपनी पैसों को वापस मांगता है, तो पाकिस्तान को 10 दिनों के अंदर पूरा कर्ज वापस करना होगा। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों की बात की जाए, तो हर पाकिस्तानी नागरिक के ऊपर करीब एक लाख 75 हजार रुपये का कर्ज है। वैसे, गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए इमरान खान की ये स्कीम कितना काम करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन, ये देखना दिलचस्प होगा कि आतंकिस्तान के नाम से मशहूर पाकिस्तान की नागरिकता लेता कौन है?

भोपाल विकास प्राधिकरण

विज्ञापन क्रमांक 134/सम्पदा/भोविप्रा/21 — भोपाल, दिनांक 05.01.22

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में स्थित सम्पत्ति के ऑफर एवं नियत मूल्य दर पर ऑनलाईन आमंत्रित रिक्त सम्पत्ति जैसे:- भूखण्ड/प्रकोष्ठ/डुप्लेक्स/हॉल/पी.एस.पी. भूखण्ड/दुकानें, जो कि निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन ऑफर वेबसाइट https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in के माध्यम से नियत दर/प्रस्ताव दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 26.01.2022 तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2022 को खोले जावेंगे।

निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट www.bda.org.in पर देख सकते है।

क्र.	योजना का नाम	ऑफर/ नियत दर	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति की संख्या	रिमार्क
1	नवी बाग व्यवसायिक भूखण्ड (बैरसिया रोड़)	ऑफर	भूखण्ड व्यवसायिक	12	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी-पी.एल. -17-837
2	स्वामी विवेकानन्द परिसर, कटारा हिल्स	ऑफर	भूखण्ड	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
3	सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद फेस-1	ऑफर	भूखण्ड	01	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी.पी.एल. -20-2629
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद-2	ऑफर	भूखण्ड	04	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी.पी.एल. -17-1018
5	सरदार वल्लभ भाई पटेल मिसरोद-2	ऑफर	नर्सरी एवं प्राईमरी स्कूल	03	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी.पी.एल. -17-1018
6	गुरू रविन्द्रनाथ टैगौर, साकेत नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
7	अन्नपूर्णा कॉम्पलेक्स (पी.एण्ड.टी चौराहा)	ऑफर	हॉल	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
8	इन्द्रपुरी सेक्टर-सी	ऑफर	भूखण्ड	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
9	सोनिया गांधी परिसर (कोटरा सुल्तानाबाद)	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
10	अन्नपूर्णा कॉम्पलेक्स (पी.एण्ड.टी चौराहा)	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
11	विद्या नगर	ऑफर	प्रकोष्ठ	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
12	एम.जी. रूसिया नगर, पीपलनेर	ऑफर	डूप्लेक्स	04	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
13	कटारा हिल्स सेक्टर-ए एवं सी	ऑफर	दुकानें	31	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
14	आई.एस.बी.टी. (कुशाभाऊ ठाकरे टर्मिनल)	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
15	गुरू रविन्द्रनाथ टैगोर परिसर (साकेत नगर)	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
16	अन्नपूर्णा कॉम्पलेक्स (पी.एण्ड.टी चौराहा)	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
17	पंचशील नगर	ऑफर	दुकानें	05	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
18	महर्षि पतंजलि	ऑफर	दुकानें	35	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
19	पंडित भीमसेन जोशी परिसर, साकेत नगर (एम्स के पास)	ऑफर	दुकानें	03	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
20	माता मंदिर (न्यू मार्केट)	ऑफर	दुकानें	06	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
21	आमेर कॉम्पलेक्स नाले के ऊपर जोन-2, एम.पी. नगर	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
22	बस स्टाप नं.-7	ऑफर	दुकान	01	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
23	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स, (भवन)	ऑफर	भवन	29	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी.पी.एल. -21-2845
24	अमरावद खुर्द योजना	ऑफर	शाला भूखण्ड	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
25	स्वामी विवेकानन्द परिसर कटारा हिल्स	ऑफर	प्रकोष्ठ	45	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
26	महालक्ष्मी आवासीय परिसर योजना (जिन्सी चौराहा पुल बोगदा के पास)	ऑफर	3बीएचके प्रकोष्ठ	13	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी.पी.एल. -17-306
27	महर्षि पातंजलि, गोंदरमउ	नियत दर	प्रकोष्ठ	22	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
28	अमरावद खुर्द	नियत दर	एल.आई.जी. डुप्लेक्स	21	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
29	विनायक नगर गोंदरमऊ	नियत दर	ई.डब्लू.एस.	02	वर्ष 2017 के पूर्व निर्मित
30	नवीबाग योजना (बैरसिया रोड़)	नियत दर	2बीएचके प्रकोष्ठ	21	रेरा पंजीयन क्र. पी-बी.पी.एल. -17-837

नोटः-वेबसाईट पर दिये गये लिंक को ओपन करने के पश्चात आपको योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें सेम्पल फार्म, योजना के मानचित्र तथा भूखण्ड/प्रकोष्ठ/दुकान/हॉल के मानचित्र व अपलोड करने हेतु विभिन्न आवश्यक अभिलेखों की जानकारी देखी जा सकती है। ऑनलाईन फॉर्म भरने हेतु प्राधिकरण की आई.टी. सेल से संपर्क किया जा सकता है।

आवश्यकतानुसार जानकारी हेतु सम्पर्कः-

1- श्री निरंजन सिंह मो.- 9827116746,

2- श्री रवि सिंह मो.- 8770234380

सम्पदा अधिकारी
भोपाल

विवाह की आयु पर विवाद

भारत में विवाह की न्यूनतम आयु खासकर महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु एक विवादास्पद विषय रही है। जब भी इस प्रकार के नियमों में परिवर्तन की बात उठी तो सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादियों का कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला। ऐसा इस बार भी हो रहा है। शायद इसी कारण लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने संबंधी विधेयक को संसद की स्थाई समिति के पास भेजना पड़ा। जो भी हो, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। विरोध में उठे तथ्यहीन तर्कों की चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि उस तस्वीर को देखा जाए, जो 1954 के पहले की थी।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई। इसका असर यह हुआ कि 1951 में देश में प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 116 थी, वह 2019-21 में 35 पर आ गई। यह तर्क अचंभित करता है कि 18 साल की लड़की जब वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तो जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती? यहां प्रश्न जीवनसाथी के चुनाव के लिए मानसिक परिपक्वता का नहीं, अपितु उस शारीरिक परिपक्वता का है, जो एक लड़की को अपने गर्भ में संतान को पालने के लिए चाहिए। गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात मां और बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर के साथ विवाह की आयु और मातृत्व के मध्य गहरा संबंध है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, गर्भावस्था और प्रसव संबंधी जटिलताओं का विश्व स्तर पर 15-19 वर्ष के मध्य की किशोर माताओं को 20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं की तुलना में गर्भाशय का संक्रमण और उच्च रक्तचाप के कारण दौरे पड़ने के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि जब लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 होने पर भी बाल विवाह हो रहे हैं तो इसे 21 साल करने का क्या औचित्य? इसमें दो राय नहीं कि देश के विभिन्न हिस्सों में आज भी चोरी-छिपे बाल विवाह हो रहे हैं, परंतु हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि विवाह की न्यूनतम 18 साल की कानूनी बाध्यता ने समाज में एक भय को अवश्य स्थापित किया है। अगर 67 साल पहले विवाह की न्यूनतम आयु में चार साल की बढ़ोतरी नहीं हुई होती और उसे 14 वर्ष यथावत रखा जाता तो आज मातृ और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े डरावने होते।

सामाजिक बदलाव के लिए यह आवश्यक है कि समयानुसार कानून में परिवर्तन किए जाएं, परंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि कानून निर्मित होते ही मनुष्य की मानसिक जड़ताएं यकायक परिवर्तित हो जाएं। किशोरावस्था में विवाह व्यवस्थागत समस्या से कहीं अधिक समाज में व्याप्त उस सोच की परिणति है जहां लड़कियों के जीवन का अंततोगत्वा उद्देश्य विवाह को ही माना जाता है। यह स्थिति निर्धन परिवारों से लेकर मध्यमवर्गीय परिवारों में बदस्तूर कायम है। इस सोच में परिवर्तन शनैः शनैः ही संभव है, परंतु यह कानून उन बच्चियों के लिए राहत अवश्य लेकर आएगा, जिनके अभिभावक हर स्थिति में 18 साल के होते ही उनके विवाह के लिए आतुर हो जाते हैं।

देश का एक बड़ा तबका, जो कथित रूप से स्वयं को बुद्धिजीवी और समानता का प्रवर्तक मानता है, वह भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। यह विरोध उनके दोहरे व्यक्तित्व को उजागर कर रहा है। लड़के और लड़कियों की वैवाहिक आयु में अंतर समानता के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 14) की अवहेलना है। यही वर्ग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरजोर आवाज भी उठाता है, परंतु क्या यह संभव है कि 18 वर्ष में विवाह हो जाने पर कोई युवती आर्थिक स्वावलंबन की ओर से सहजता से अपने कदम उठा पाए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन तथा विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती हैं कि किशोरावस्था में विवाह के चलते आई शिक्षा में रुकावट महिलाओं के अर्थ अर्जन में औसतन नौ प्रतिशत की कमी करती है, जिसका परिवार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट यह भी बताती है कि अगर दुनिया की प्रत्येक लड़की 12 वर्षों तक बिना किसी रुकावट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाए तो विश्व की कमाई 15 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। वर्कले इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि किशोरावस्था में विवाह किसी देश की जीडीपी को कम से कम 1.7 प्रतिशत की क्षति पहुंचाता है। साथ ही महिलाओं की कुल प्रजनन क्षमता में 17 प्रतिशत की वृद्धि करता है, जो उच्च जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहे विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाती है। दुनियाभर में हुए अनेक अध्ययन बताते हैं कि किशोरवय विवाह लड़कियों और युवा महिलाओं को अशक्त बनाता है। उन्हें शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य, शोषण और हिंसा से मुक्त रहने सहित कई मौलिक मानव अधिकारों से वंचित करता है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

किशोरावस्था विवाह को रोकने पर जोर

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की एक रिपोर्ट में किशोरावस्था में विवाह को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, दशकों के अनुभव और अनुसंधान से स्पष्ट है कि बिल्कुल निचले स्तर पर जमीनी दृष्टिकोण के जरिए स्थायी परिवर्तन लाने में अधिक मदद मिलती है। महिलाओं को समर्थन देती कानूनी प्रणालियां इस तरह निर्मित की जानी चाहिए कि हर महिला को समान अवसर अवश्य मिले। इस दिशा में विवाह की न्यूनतम आयु में बढ़ोतरी युवतियों को शिक्षा और जीवन कौशल सिखाने के अवसर उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगी।

रामचरितमानस की प्रासंगिकता

एक संपूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए ग्रंथ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस पर जितनी भी चर्चा, आलोचना-समालोचना और समीक्षा हुई है उतनी शायद ही किसी अन्य लिपिबद्ध ग्रंथ की हुई होगी, और हो भी क्यों न? ऐसा और कौन सा ग्रंथ है, जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न अंगों को इतने मर्मस्पर्शी एवं स्पष्ट ढंग से छुआ हो- चाहे वह परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंधों की गरिमा-मर्यादा हो, समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी संबंधों की मर्यादा हो अथवा राजकीय काम-काज व राजा के कर्तव्यों की।

श्रीरामचरितमानस में निरूपित जीवन-व्यवस्था एक आदर्श समाज एवं आदर्श राज्य की कोरी कल्पना मात्र न होकर पूर्णत: अनुभवगम्य और व्यावहारिक है। इस ग्रंथ के माध्यम से गोस्वामीजी ने परस्पर स्नेह-सम्मान के साथ कर्त्तव्य-परायणता के माध्यम से न केवल जीवन को समृद्ध-सुखी बनाने में असंख्य-अप्रतिम योगदान दिया है वरन मानस के पात्रों के माध्यम से ढेरों सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में अभूतपूर्व कार्य किया है।

आज के संदर्भ में हमारे समक्ष विद्यमान विशालतम चुनौतियों में जो अग्रणी हैं उनमें सामाजिक व्यवस्था में समरसता का उत्तरोत्तर ह्रास प्रमुख है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि इक्कीसवीं सदी के उन्नीस वर्ष और भारतीय संविधान लागू होने के उनहत्तर वर्ष बाद भी वर्ण-व्यवस्था और रुढ़ियों के कुचक्र को भेदने में सफल होने की अपेक्षा हम उसमें और उलझते जा रहे हैं और अपने वर्तमान को संभालने के संकट से जूझ रहे हैं।

सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए रामचरितमानस ने जो योगदान कई सौ वर्ष पूर्व किया था वह आज भी उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक प्रासंगिक तथा आवश्यक है। मानस के रचना काल को देखें तो पता चलता है कि उस समय वर्ण-व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय समाज मुख्यत: दो सम्प्रदायों (वैष्णव और शैव) में विभाजित था। तत्कालीन अन्य वैश्विक धर्मों के मतावलम्बियों में विभाजित समूहों-अनुयायियों की भांति, हिंदू धर्म के अनुयायी भी दो वर्गों में विभक्त थे और अपने पंथ (वैष्णव-शैव) तथा आराध्य (भगवान श्रीराम एवं भगवान शंकर) को एक-दूसरे से उच्चतर समझने की वजह से प्राय: एक-दूसरे से विद्वेष-विद्रोह में अपना समय व ऊर्जा व्यर्थ करते थे जिसके फलस्वरूप हानि अंतत: समाज की होती थी।

बालकांड में वर्णित प्रयागराज के मुनि-समागम में ऋषि भरद्वाज अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ अपने संवाद में भगवान शंकर को भगवान श्रीराम का उपासक बताते हुए कहते हैं कि हर कोई अविनाशी भोलेनाथ की उपासना करता है, वहीं स्वयं भगवान शंकर श्रीराम की महिमा का बखान करते हैं-

'संतत जपत संभु अविनासी,
सिव भगवान ज्ञान गुन रासी।
सोपि राम महिमा मुनिराया,
सिव उपदेश कीन्ह करि दाया।

तथा 'जासु कथा कुम्भज ऋषि गाई सोइ मम इष्ट देव रघुबीरा... के माध्यम से बार-बार शंकर का राम के प्रति सम्मान दिखाना निश्चित ही शैवों के मन से वैष्णवों के प्रति विद्वेष भाव समाप्त करने और दोनों सम्प्रदायों के बीच की खाई को भरने और उनमें परस्पर सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया अत्यावश्यक, सार्थक, सफल प्रयास था। यही नहीं बालकांड में माता पार्वती को श्रीराम जन्म-प्रसंग की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर जन्मोत्सव का आनंद देखने के लिए कागभुशुण्डि के साथ मनुष्य रूप में चोरी से अपने अयोध्या विचरण तथा बाल-लीला देखने की चर्चा करते हैं, जिससे उनके मन में भगवान राम के प्रति आदर परिलक्षित होता है।

विचित्रता यह कि ये प्रेम-सम्मान एकांगी नहीं बल्कि विशुद्ध द्विपक्षी है। इसकी एक अति मनोहारी झलक पुष्प वाटिका में मिलती है जब सीताजी शंकर-प्रिया भवानी से अपने लिए एक सुयोग्य वर की प्रार्थना करती हैं। यदि हम थोड़ी और गहराई में उतरें तो पाएंगे शंकर और राम (अर्थात् शैव-वैष्णव) समीकरण-एकीकरण मानस का छिटपुट प्रसंग न होकर यत्र-तत्र-सर्वत्र का प्रसंग है। इसका प्रमाण हमें इस तथ्य से मिलता है कि श्रीराम-शंकर का परस्पर स्नेह-सम्मान, पूजा-अर्चना बालकांड से प्रारंभ होकर अयोध्याकांड और लंकाकांड होते हुए उत्तरकांड तक बारहमासी पवित्र सलिला सदृश निरंतर चलती रहती है।

वनगमन-प्रसंग में भी श्रीराम अपने चौदह-वर्षीय वनवास की यात्रा पर अयोध्या से प्रस्थान करते समय विघ्नहर्ता गणेश और मां भवानी के साथ भगवान शंकर का ही स्मरण करते हैं-

गणपति गौरि गिरीसु मनाई,
चले असीस पाई रघुराई।

और गंगाजी को पार करने के बाद पुनः शंकर को शीश झुका कर वनगमन करते हैं-

तब गणपति सिव सुमिरि प्रभु,
नाइ सुरसरिहि माथ।
सखा अनुज सिय सहित वन,
गवन कीन्ह रघुनाथ।

राम से ऐसा कहलवाकर तुलसीदास जी वैष्णवों को भी शैवों के प्रति वैर-वैमनस्य छोड़कर उन्हें मैत्री भाव हेतु प्रेरित ही नहीं बल्कि विवश करते हैं।

● **ओम**

ड्यूटी

चौराहे पर लॉकडाउन के नियमों को लागू कराने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कॉन्सटेबल ब्रजेश के मोबाइल फोन पर घंटी बजी। फोन करने वाला उनका दोस्त आनंद था, जो सिंचाई विभाग में क्लर्क था। फोन पर आनंद का संदेश सुनाई देता है–

यार, ब्रजेश जब देखो तुम ड्यूटी करते रहते हो, बहाना बनाकर छुट्टी ले लो न।

नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लोगों की सुरक्षा करना मेरा फर्ज है।

वह इतना कह पाया था कि तभी सामने दो बाइकों में जोरदार टक्कर हुई, और एक लड़का, जिसका नाम गौरव था, बुरी तरह घायल हो गया। उसे ब्रजेश तुरंत अस्पताल लेकर गया। समय पर इलाज मिल जाने से वह बच गया, पर डॉक्टर ने कहा कि यह घायल को समय पर कॉन्स्टेबल द्वारा अस्पताल लाने के कारण ही संभव हो सका है। डॉक्टर, कॉन्स्टेबल ब्रजेश की तारीफ कर ही रहा था कि तभी गौरव का पिता पहुंचा, जिसने भी ब्रजेश की तारीफ सुनी। गौरव का पिता और कोई नहीं, बल्कि ब्रजेश का दोस्त आनंद था, जो कुछ देर पहले मोबाइल पर उसे ड्यूटी से बचने की सलाह दे रहा था। यह सुनकर उसका सिर झुक गया। वह ब्रजेश से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।

– प्रो. शरद नारायण खरे

मोलभाव

राधा अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाने के रिक्शे की तलाश में सड़क के किनारे खड़ी थी। एक भी रिक्शा खाली नहीं दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से एक खाली रिक्शा दिखा तो राधा ने उसे झट से रोक लिया और पूछा भैया... डॉ. सुभाष क्लिनिक चलोगे?

हां चलूंगा।

कितने लोगे?

पचास रुपए।

ठीक है चलो कहकर राधा अपने बेटे के साथ रिक्शे पर बैठ गई। राधा के बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन कहने लगा आज ये मम्मी को क्या हो गया वह तो हमेशा ही रिक्शेवाले, सब्जीवाले, फेरीवाले से मोलभाव करती है, फिर आज क्यों नहीं, वह राधा के कान में धीमी आवाज में कहने लगा– मम्मी आज आपने रिक्शे के पैसे कम नहीं करवाए... क्यों? राधा ने मुस्कुराकर कहा– बेटे आज से मैंने गरीबों से मोलभाव करना बंद कर दिया। हम डॉक्टर की फीस से तो मोलभाव नहीं करेंगे ना। जितने रुपए कहें उतने तो देने ही पड़ेंगे ना। वो अपने पढ़े–लिखे होने की फिस लेते हैं तो ये लोग अपने मेहनत का मेहताना लेते हैं। आखिर ये रिक्शेवाला हवाई जहाज के किराए जितना तो नहीं मांग रहा। राधा रास्ते भर सोचती रही कि बच्चे हमसे ही सीखते हैं बच्चे के मानसपटल पर मोलभाव कैसे छाया है। तभी क्लिनिक आ गया। राधा ने रिक्शे से उतरकर रिक्शेवाले को पचास रुपए पकड़ा दि। रिक्शेवाले ने खुशी से रुपए चूमकर माथे से लगा लिया और जेब में रख लिया।

अपना रिक्शा मोड़कर वह दूसरी सवारी की खोज में चल पड़ा उसके दिमाग में भी एक बात चलने लगी कि आज पहली बार बिना मोलभाव की सवारी कैसे मिली।

– अमृता जोशी

कैसे कोई गीत सुनाए

कैसे कोई गीत सुनाए
कितने साथी छूट गए
सब रिश्ते–नाते टूट गए
पल–पल मरती आशाएं
जब अपने ही लगें पराए
कैसे कोई गीत सुनाए?
बचपन बीता अठखेली में
यौवन बीता रंगरेली में
भूले सब वह जो करना था
खोए रहे एक पहेली में
समय चक्र आगे निकला
संग आने की टेर लगाए
कैसे कोई गीत सुनाए?
नित नई आती बाधा में
सफर हद से ज्यादा में
अंतर भी न समझ सके
रुक्मणी और राधा में
रोज द्रौपदी लुटती है
कान्हा कितनी चीर बढ़ाए
कैसे कोई गीत सुनाए?
तजे प्राण राजा दशरथ ने
आंसू नहीं हैं कौशल्या में।
जातिवाद के हो हल्ला में
झगड़ा है गली मुहल्ला में।
इस युग में राम के जूठे बेर
कहां किस शबरी ने खाए
कैसे कोई गीत सुनाए?
शून्य हुईं सब अभिलाषाएं
नर्तन करती मृत्यु निशाएं
अपने–अपने में यूं खोए हैं
कौन सुने किसकी आहें
हो यदि मुफलिस की बेटी
उसकी डोली कौन उठाए
कैसे कोई गीत सुनाए?

– आशीष तिवारी निर्मल

क्या लौटेगा कोहली का फार्म?

"एक साल पहले विश्व के सबसे महान बल्लेबाज की श्रेणी में गिने जा रहे विराट कोहली का फार्म इतना खराब हो गया है कि उनके भविष्य के सामने खतरा मंडराने लगा है। हालांकि उनके फैंस और भारतीय टीम को भी उम्मीद है कि विराट जल्द ही अपनी लय पकड़ लेंगे। लेकिन कब इसको लेकर संशय बना हुआ है।"

एक दौर था। सितारे बुलंद थे और वक्त भी सही था तो पूरी टीम इंडिया तराजू के एक पलड़े पर और विराट कोहली दूसरे पर। क्योंकि उस समय कोहली ट्राम इंडिया के लिए परफार्मिंग असेट थे तो टीम में उनका एक अलग मरतबा था वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे। ये वो समय था जब टीम इंडिया का स्टार परफॉर्मर मौज-मस्ती के लिए अंतरराष्ट्रीय शतक बना रहा था और तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल और टी-20 में भारत का नेतृत्व कर रहा था, जिसका सौभाग्य अतीत में बहुत कम भारतीय कप्तानों को मिला था।

जिक्र कोहली का हुआ है। तो शायद ही कोई 2017 का वो समय भूल पाए जब कोहली का गेम अपने पूरे शबाब पर था। और उसी समय उनका टीम के कोच अनिल कुंबले के साथ विवाद हुआ था। कोच-कप्तान विवाद कुछ इस हद तक बढ़ा कि दुनिया के महानतम गेंदबाजों में शुमार अनिल कुंबले ने कप्तान के साथ अस्थिर रिश्तों का हवाला देते हुए अपना पद त्याग दिया था। बाद में जब **चैंपियंस ट्रॉफी** के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के हाथों हार देखी विवाद थम गया और बात विवाद पर न होकर फाइनल पर मिली हार पर होने लगी।

कुंबले के बाहर होने के बाद, रवि शास्त्री, जिन्होंने 2016 तक कोहली के साथ टीम मैनेजर के रूप में काम किया था, को मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। शास्त्री की नियुक्ति सीधी नहीं थी, लेकिन कथित तौर पर कोहली ने पूर्व विश्वकप विजेता ऑलराउंडर को ड्रेसिंग रूम में वापस लाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया और शास्त्री के मद्देनजर सिलेक्टर्स के सामने अपने मन की बात रखी। चूंकि कोहली की परफॉर्मेंस बोलती थी इसलिए सिलेक्टर्स को भी उनकी बातें माननी पड़ी और शास्त्री टीम में आए। विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। माना जाता है कि ये वो समय था जब भारत ने कई मौकों पर इतिहास रचा। ऐसा नहीं था कि कोहली और शास्त्री की जोड़ी ने विजय का परचम ही लहराया। ऐसे भी मौके आए जब भारत को मुंह की खानी पड़ी और 2019 में विश्वकप के सेमीफाइनल से बाहर होना भारत के लिए एक ऐसा ही पल था।

विश्वकप में जो हुआ उसको लेकर तमाम तरह के सवाल-जवाब हुए, भांति-भांति की बातें हुईं लेकिन कोहली का बाल भी बांका नहीं हुआ। कारण? कोहली की परफॉर्मेंस। विश्वकप से बाहर होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट के तहत अपना नंबर एक का दर्जा बरकरार रखा। क्योंकि इस समय तक रोहित शर्मा ने भी इंडियन प्रीमियर लीग में सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में अपनी योग्यता साबित की थी। स्प्लिट कैप्टेंसी की बातों ने जोर पकड़ा लेकिन टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने उस पर कान नहीं दिए और इस तरह कोहली ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में नेतृत्व करना जारी रखा। वो वक्त भी आया जब डायनामिक्स बदलने शुरू हुए।

हालांकि, 2021 में गतिशीलता बदल गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार टेस्ट सीरीज जीती। पहली बार विराट कोहली के नेतृत्व में 2018-19 में भारत ने जीत दर्ज की और 2020-21 में अपने प्रभावशाली नेता यानी विराट कोहली के बिना। कोहली के लिए ये वो समय था जब वो एडिलेड में पहले टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार के बाद पितृत्व अवकाश पर घर लौट आए थे। कोहली के जाने के बाद ये समय भारत के लिए भी बहुत निर्णायक था। इस समय तक इस बात का फैसला हो चुका था कि टीम किसी एक की नहीं है। भारत ने अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में इतिहास रचा और गाबा के किले पर तिरंगा लहराया। भारत ने इस सीरीज को 2-1 से जीता और दुनिया को बताया कि कोहली टीम में रहें या न रहें इतिहास लिखा जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया में रहाणे के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन के बाद भी, इसमें कोई संदेह नहीं था कि 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में घर में इंग्लैंड के खिलाफ टीम का नेतृत्व कौन करेगा। विराट कोहली ने टीम की कमान संभाली और भारत को होम ग्राउंड में जीत दिलाई। ध्यान रहे ये वो समय था जब कप्तान कोहली ने कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। कोहली का खराब बैटिंग फॉर्म तब सुर्खियों में आया जब कप्तान के रूप में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक साल से अधिक समय तक कोई सेंचुरी नहीं जड़ी।

● **आशीष नेमा**

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मिस

मई में कोविड-19 के कारण आईपीएल 2021 के निलंबन के बाद, इंग्लैंड के दौरे से पहले तक भारत के पास ठीक-ठाक समय था। भारत ने साउथेम्प्टन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना किया, जो कोहली के लिए अपने विरोधियों को गलत साबित करने और कप्तान के रूप में आईसीसी खिताब जीतने का एक और मौका था। हालांकि, चीजें भारत के अनुकूल नहीं रहीं और न्यूजीलैंड ने आराम से फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि, कोहली के सारथियों ने इंग्लैंड में उनका पूरा साथ दिया और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत इंग्लैंड पर हावी हुआ, सीरीज अधूरी रही क्योंकि 5वां टेस्ट कोविड-19 के कारण निलंबित कर दिया गया। भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त तो ली लेकिन कोहली के बैटिंग फॉर्म में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। जबकि रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शतक बनाए। इस सीरीज में कोहली संघर्ष करते नजर आए और उन्होंने 4 टेस्ट मैच में सिर्फ 218 रन बनाए।

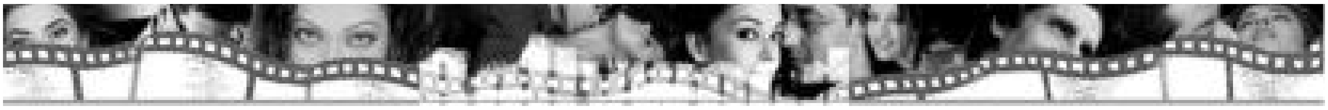

काजोल ने 'कुछ-कुछ होता है' में इस वजह से लगाया था हेयरबैंड

करण जौहर लिए 'कुछ-कुछ होता है' सबसे खास फिल्मों में से एक है क्योंकि ये उनके डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म थी। प्यार दोस्ती है के थीम पर बनी इस फिल्म ने सफलता के कई झंडे गाड़े और इस तरह के रोमांस को लेकर कई और फिल्में भी बाद में बॉलीवुड में बनी लेकिन 'कुछ-कुछ होता है' ने जो मुकाम हासिल किया था उसे कोई और नहीं छू पाया। इस फिल्म से शाहरुख खान का कूल नेक चैन, फ्रेंडशिप बैंड और काजोल के हेयरबैंड खासकर बहुत पॉपुलर हुए थे। लोगों ने इस फैशन को सालों तक फॉलो किया था। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि काजोल के उस आइकॉनिक हेयरबैंड के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। काजोल ने इस हेयरबैंड को फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ में पहना था लेकिन ये असल में काजोल के लुक को कंप्लीट करने के लिए बल्कि खास वजह से लगाया गया था। दरअसल ये चौड़े और मोटे हेयरबैंड काजोल के विग के लिए फिक्स का काम करते थे।

रणवीर सिंह के शो 'द बिग पिक्चर' में करण जौहर ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कैरेक्टर अंजलि असल में हेयरबैंड नहीं पहनती थी लेकिन काजोल के विग के साथ समस्या थी और उन्होंने हेयरबैंड का इस्तेमाल विग के फिक्स की तरह किया था ताकि ये अपनी जगह पर दिखे। एक्सिडेंटल हेयरबैंड एक्सपेरिमेंट असल में आगे जाकर फैशन ट्रेंड में शुमार हो गया।

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन कभी हुआ करते थे चेन स्मोकर

एशिया के सबसे हैंडसम मैन रहे ऋतिक रोशन 48 साल के हो चुके हैं। ऋतिक ने साल 2000 की हिट फिल्म 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी। इसके बाद ऋतिक ने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दीं। हाल ही में उनकी फिल्में 'सुपर-30' और 'वॉर' ने कई रिकॉर्ड तोड़े।

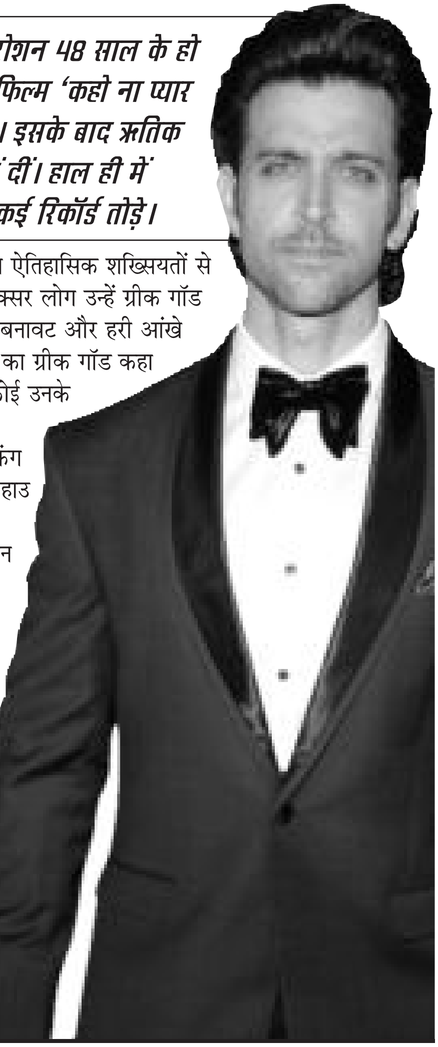

ऋतिक को हॉलीवुड स्टार और कई खूबसूरत ऐतिहासिक शख्सियतों से जोड़ा जाता है, लेकिन ऋतिक को देख अक्सर लोग उन्हें ग्रीक गॉड कहते हैं। दरअसल, उनके चेहरे की खास बनावट और हरी आंखे ग्रीक गॉड से मिलती हैं। इसलिए उन्हें बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर कोई उनके स्टाइल और खूबसूरती का कायल है। ऋतिक रोशन चेन स्मोकर थे, लेकिन फिर उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होनें हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग नाम की एक किताब पढ़ने के बाद स्मोकिंग करना छोड़ दिया था। ऋतिक रोशन बचपन में हकलाते थे। ऋतिक के दो अंगूठे हैं और इसी वजह से वह अपने आप को लकी भी मानते हैं। बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल जोड़ी में कभी ऋतिक रोशन और सुजैन खान का नाम टॉप पर था। ऋतिक अपनी स्वीटहार्ट सुजैन को जिस तरह प्यार करते थे, उन्हें पैंपर करते थे, वो देख लड़कियां जलती थीं। वो भी अपने लिए कोई ऋतिक रोशन जैसा राजकुमार चाहती थीं। लेकिन कपल के प्यार को किसी की बुरी नजर लग गई। बी-टाउन के ये मोस्ट एडोरेबल कपल जुदा हो गए। कहो न प्यार है से लेकर वॉर तक कई फिल्म्स उनकी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं।

अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर से कल्कि ने कर ली थी शादी

अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन 38 साल की हो चुकी हैं। अपने दमदार अभिनय और अलहदा किरदारों से लोगों की दिलों में कल्कि ने खास जगह बनाई है। कल्कि ने 30 अप्रैल 2011 को 'देव डी' के डायरेक्टर अनुराग कश्यप से शादी की थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। उस समय वह अनुराग से बेइंतहा प्यार करती थीं। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। दो

साल में ही दोनों अलग हो गए। अनुराग की यह दूसरी और कल्कि की पहली शादी थी। तलाक होने के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हैं।

बगैर शादी के बनी मां

अनुराग से तलाक होने के बाद कल्कि गाय हर्शबर्ग को डेट करने लगी। इस समय भी उनके साथ एक्ट्रेस रिलेशन में हैं। कल्कि के ब्वॉयफ्रेंड गाय हर्शबर्ग इजराइल से हैं और वो पेंटिंग्स बनाते हैं। फरवरी 2020 में कल्कि ने बगैर शादी के एक बच्ची को जन्म दिया था। अक्सर वो अपनी बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर करती रहती हैं।

चारण-पुराण

सत्य को पर्दे में छिपाना और सत्ता-सत्ताधीश का बिगुल बजाना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। देश की क्या? पहले राजा, राजनेता, राजनीति, सत्ता, जिसकी इच्छा के बिना हिलता नहीं पत्ता। वही देश है, उसी की भक्ति देशभक्ति है। इसी में उनकी मुक्ति है, चाहे आम आदमी की हो या न हो।

देश के इतिहास में एक समय ऐसा भी था, जो घोषित चारण-युग था। इसके विपरीत आज अघोषित चारण-युग है। प्राचीन चारण-युग में कवि रचनाकार कवि ही नहीं, राजाओं, राज परिवारों और राजघरानों के अतिशयोक्ति परक चाटुकार, पत्रकार और अंधानुयायी भी थे। तिल का ताड़ बनाकर प्रशंसात्मक कविता कहना, सुनाना और उनकी प्रशस्ति का गुणगान करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। एक की दस, दस की सौ और सौ की हजार करना उनका बाएं हाथ का खेल था। इतना ही नहीं उनके मित्र राजा द्वारा किसी की सुंदरी पत्नी/पुत्री/प्रेयसी को प्राप्त करने या राज्य का विस्तार करने के लिए किए जा रहे युद्ध के मैदान में उनका उत्साहवर्द्धन करना भी उनका ही काम था। श्रृंगार से वीर रस की गंगा में ये चारण कवि ही तो गोते लगवाते थे।

संदर्भित चारण कवियों का अपनी लेखनी या मुंह-वाणी से चाहे जितना भी घनिष्ठ संबंध रहा हो, किंतु मेरी सोच के अनुसार उनका संबंध 'चरणों' से अधिक था। जो राजा और रानी के चरणों के जितना अधिक निकट संबंध स्थापित कर लेता, ख्याति की श्रेणी उतनी ऊपर चढ़ जाती थी। संभवत: 'चरण-चुम्बन करना', मुहावरे का जन्म भी तभी से हुआ होगा। आज उसका साक्षात स्वरूप जीवंत हो रहा है। जो राज परिवार, राज सेवक और राज संबंधियों का जितना अधिक सानिध्य प्राप्त कर ले, वह उतनी ही अधिक माखन-मिश्री, दूध-मलाई, बदन पर लुनाई, देह पर चिकनाई का लाभ प्राप्त कर फर्श से अर्श की ऊंचाईयां हासिल कर लेता है।

वर्तमान कालीन युग के चारणों की सूची बहुत बड़ी है। रीतिकालीन कविवर बिहारी लाल ने भले ही सात सौ सोलह दोहा-सोरठा छंदों की सतसई लिखकर मिर्जा राजा आमेर नरेश जय सिंह से प्रत्येक छंद पर सोने की अशरफी प्राप्त की हो अथवा नहीं, परंतु आज के तथाकथित चारण-वृंद ऐसा एक भी सुनहरा अवसर हाथ से खाली नहीं जाने दे सकते। चाहे वे टीवी पत्रकार हों, अखबार या अखबारी पत्रकार हों, चापलूस कवि हों, चरण-चुम्बन के बिना ऊपर जा ही नहीं सकते। छुटभैये समाज सेवी, अंधानुकरण में आपादमस्तक डूबे हुए बैनर पोस्टर लगाने वाले, गड्ढ़े खोदने वाले (अब ये कैसे कहें कि वे किसके लिए गड्ढ़े खोदते हैं, अपने लिए तो कदापि नहीं खोदते होंगे।), प्रचारक, परचम लहरावक अथवा कोई अन्य। सबका एक ही उद्देश्य है, चाहे वह सत्ता कैसी भी क्यों न हो।

सत्य को पर्दे में छिपाना और सत्ता-सत्ताधीश का बिगुल बजाना, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। देश की क्या? पहले राजा, राजनेता, राजनीति, सत्ता, जिसकी इच्छा के बिना हिलता नहीं पत्ता। वही देश है, उसी की भक्ति देशभक्ति है। इसी में उनकी मुक्ति है, चाहे आम आदमी की हो या न हो। जब आम आदमी की मुक्ति हो ही गई, फिर नेताओं का होगा भी क्या! क्या होगा चुनाव का। चुनाव ही तो चुन-चुनकर पार उतारता है। यह तो उसकी इच्छा है कि किसे उतारे किसे नहीं भी उतारे! जो उसकी नित्य आरती उतारे, उसी को वह अपने सिर पर धारे।

चारण के लिए चरणों का सोपान अनिवार्य है। वह नख को छूकर शिखा तक पहुंच यों ही नहीं बना पाता। इसी से नख-शिख शब्द श्रृंगार के शब्दकोश में आया प्रतीत होता है। यही तो श्रृंगार-चित्रण की भारतीय पद्धति है। नीचे से पहाड़ पर चढ़ती हुई पिपीलिका सर्वोच्च शिखर पर जा पहुंचती है, तो फिर महान चारण जी तो उस नन्हीं पिपीलिका से लाखों-करोड़ों गुणा विशाल हैं, महान हैं, ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं। वे तो पहाड़ से भी ऊपर हेलीकॉप्टर यात्रा के मेहमान हैं। मेरा देश इसीलिए तो महान है।

अभी आपने यह जाना कि चारण का विशेष और घनिष्ठ संबंध 'चरणों' से है। चरणों के साथ-साथ 'रण' से भी उनका विशेष संबंध रहा है। रण की चाह में चापल्य, चूना चिपकाने में जो चतुर हो, वही सफल 'चारण' की पदवी धारण कर सकता है। चपलता, चतुराई, चटुलता, चमत्कारिता, चश्मेबद्दूरी (बुरी नजर से दूर हटाने वाला) की चाशनी चिपका पाए, वही सच्चा चारण।

आज 'चारण' के बिना नहीं होता शंका निवारण। जब चापलूस 'चारण' कहेगा कि आपको लघु शंका निवारण करनी होगी, तो कर लीजिए, आइए मैं कुछ मदद कर दूं! तभी उन्हें याद आएगा कि अरे! आप तो बहुत अच्छे हैं!

अन्यथा पता नहीं क्या हो जाता!

यों तो 'चारण-पुराण' की कथा अंनत है। हर चारण आज के युग का आधुनिक संत है, उसी से सियासत के खेतों में वसंत है, किंतु चारण के आचरण, चरण और संचरण पर सियासती धनवंत है। वह राजनीति के देवालय का ऐसा महंत है, कि उसके बिना न पूजा है, न पाठ और न ही आरती। जब आरती ही नहीं, तो प्रसाद मिलेगा भी क्यों? आरती के बाद फिर वही पुरानी बात 'अंधा बांटे रेवड़ी...'

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687